हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

27 जुलाई, 1998

खण्ड - 2, अंक - 5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 27 जुलाई, 1998

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5)1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(5)17
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5)24
विभिन्न सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं इत्यादि	(5)26
सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र	(5)33
वर्ष 1998-99 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(5)34
बैठक का समय बढ़ाना	(5)64
वर्ष 1998-99 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(5)65
विधेयक–	(5)66
(i) पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1998	(5)66
(ii) हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1998	(5)69
वाक आउट	(5)71
विधेयक–	(5)72
हरियाणा नगरपालिका(संशोधन) विधेयक 1998 (पुनरारम्भ)	(5)72
(iii) हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 1998	(5)72
(iv) पंजाब आबकारी (हरियाणा तृतीय संशोधन) विधेयक, 1998	(5)74

-क्रमशः-

110

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 27 जुलाई, 1998

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में बाद दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : साहेबान अब क्वैशचन आवर होगा।

Loading/Unloading and Transportation Charges

***670. Shri Ram Pal Majra :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether it is a fact that the loading/unloading and transportation charges of sugarcane are being charged from the farmers by the Haryana State Cooperative Sugar Mills for bringing the sugarcane to the Mills from their respective collection centres; if so, since when the same is being charged ?

सहकारिता मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : वर्णन सदन के पटल पर रखा जाता है।

वर्णन

सहकारी चीनी मिलें गन्ना संग्रह केन्द्रों से गन्ना मिल तक लाने के लिए हमेशा से ही किसानों से ढुलाई खर्चा लेती रही हैं। लदाई/उतराई खर्च की प्रथा 1995-96 तक घटती बढ़ती रही। पिड़ाई सत्र 1996-97 व 1997-98 के लिए सभी मिलों ने लदाई/उतराई का खर्चा लिया था। अब सरकार ने आने वाले पिड़ाई सत्र 1998-99 के लिये ढुलाई, लदाई/उतराई का खर्चा लेने का निर्णय प्रत्येक सहकारी चीनी मिल के निदेशक-मण्डल पर ही छोड़ दिया है।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, इस खर्चे को किसानों पर डालने के बाद किसान निरूत्साहित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गन्ने की लदाई/उतराई का जो 5 रुपये से 11 रुपये तक का खर्चा है उसे सरकार वापिस लेने पर विचार करेगी?

श्री नरबीर सिंह : स्पीकर साहब, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, किसानों पर यह खर्चा डालने के बाद किसानों ने काफी कम गन्ना उगाना शुरू कर दिया है जिसके कारण अब की बार गन्ने की पिड़ाई इसीलिए थोड़े समय तक रही और आगे के लिए भी ऐसा महसूस किया जा रहा है कि गन्ने की कम पैदावार होने के कारण चीनी मिलें कम समय तक चल पाएंगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा कोई अल्टरनेटिव प्रबंध कर रही है जिससे किसान प्रोत्साहित हो कर गन्ने की पैदावार बढ़ाएं ताकि चीनी मिलें पूरे सीजन चलें।

श्री नरबीर सिंह : स्पीकर साहब, अगर यह खर्चा किसानों से न भी लिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गन्ने की पैदावार हर साल घटती बढ़ती रहती है।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्राइवेट चीनी मिलों ने गन्ने का काफी ज्यादा रेट दिया है। जैसे भादसों प्राइवेट चीनी मिल ने किसानों को काफी ज्यादा गन्ने के रेट दिये इसलिए उस इलाके में किसानों ने प्रोत्साहित हो कर ज्यादा गन्ना बोया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या सरकार उनको कोई इनसैंटिव देगी ताकि किसान गन्ना ज्यादा बोयें ? क्या सरकार गन्ने के पिछले रेट को मद्देनजर रखते हुये अगले सीजन में गन्ने के रेट बढ़ाएगी ?

श्री नरबीर सिंह : स्पीकर साहब, गन्ने के पिछले रेट को ही ध्यान में रख कर नया रेट निर्धारित किया जाएगा लेकिन गन्ने की उतराई/लदाई के बारे में फैसला चीनी मिलों के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्ज पर छोड़ दिया गया है। सहकारी चीनी मिलों के नजदीक जो प्राइवेट चीनी मिलें हैं जैसा वह करते हैं वैसा ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्ज अपने हिसाब से कर लें।

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने गन्ने की उतराई/लदाई के खर्चे के बारे में फैसला चीनी मिलों के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्ज पर छोड़ दिया है इस फैसले को सरकार क्यों नहीं करती और यह खर्चा चीनी मिलें ही दें यह खर्चा किसानों पर नहीं पड़ना चाहिए।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह फैसला बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्ज पर इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि वे जनता के चुने हुए हैं इसलिए वही जनता की ज्यादा भलाई समझते हैं।

श्री अशोक कुमार : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि गन्ने की उतराई/लदाई के खर्चे के बारे में फैसला चीनी मिलों के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्ज पर छोड़ दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि कोई प्राइवेट चीनी मिल किसानों को गन्ने के ज्यादा रेट देता है तो क्या उसके नजदीक के चीनी मिल का बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्ज उतना ही रेट देंगे।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में केन कमिशनर फैसला करेगा।

Vegetable Market for Charkhi Dadri

***755. Shri Sat Pal Sangwan** : Will the Minister of State for Horticulture and Marketing be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Vegetable Market at Charkhi Dadri, District Bhiwani ?

Minister of State For Horticulture and Marketing (Shri Jagbir Singh Malik) : Yes, Sir.

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन में मैंने यही सवाल किया था उस वक्त भी मुझे यही जवाब मिला "यस सर"। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वहां पर सब्जी मण्डी व अनाज मंडी बनाने के लिए क्या सैक्शन 4 व 6 के नोटिस इशू हो चुके हैं या नहीं। दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारी ये मंडियां कब तक बन जाएंगी ?

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, वहां पर सब्जी मण्डी व अनाज मंडी बनाने का प्रावधान किया हुआ है। वहां पर इस काम के लिए सैक्शन 4 के तहत 32 एकड़ 6 कैनाल जमीन अधिग्रहण कर ली गई है। अब सैक्शन 6 के तहत वहां पर औब्जैक्शंज मांगे हुए हैं। इन औब्जैक्शंज के बाद यदि कोई दिक्कत न आई तो ये दोनों मंडियां दो साल में बना कर तैयार कर दी जाएंगी।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि नारनौल के अन्दर सैनी बाहुल एक छोटा सा कस्बा है। वहां पर पहाड़ी एरिया है। वहां सब्जी की कम खपत है जबकि वहां पर सब्जी बहुत अधिक होती है। वहाँ पर मंडी आदि न होने के कारण वह सब्जी बाहर पड़ी रहती है और सड़ जाती है। वहां पर सब्जी मंडी बनाने की मांग लोगों की तरफ से बराबर आ रही है। क्या मंत्री जी वहां पर सब्जी मंडी बनाने की कृपा करेंगे?

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, जहां पर भाई कैलाश चन्द्र मंडी बनाने की बात कह रहे हैं और ये इसको बनाया जाना जरूरी समझते हैं तो इसको हम एग्जामिन करवा सकते हैं।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल सब्जी मंडी, दादरी के बनाये जाने तक सीमित है। मैं इसको वहीं तक सीमित रखूंगा। लेकिन मैं सरकार की मंडी बनाये जाने की पालिसी मैटर के बारे में जानना चाहूंगा। सरकार ने घोषणा की थी कि जो लाईसेंसी आलरेडी दादरी की सब्जी मंडी में था दूसरी सब्जी मंडियों में बैठें हैं क्या उनको रियायती दरों पर दुकानें देंगे ? उनको दुकानें देने के बाद जो दुकानें बचेंगी उन दुकानों की ओक्शन करेंगे इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, यह मैटर सब-जुडिस है। रिजर्व प्राईस पर दुकानें देने या न देने के कारण ही यह मामला कोर्ट में पैंडिंग है। इसलिए इसका ज्यादा जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : दादरी में सब्जी मंडी बनायी जानी बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमारा सबसे पुराना सब डिवीजन है। वहां से तीन एम०एल०ए० मैं, सांगवान साहब व नृपेंदर जी हैं। क्या इस मामले को आप जल्दी से एक्सपीडाइट करवाने का आश्वासन देंगे ?

श्री जगबीर सिंह मलिक : जो जमीन हमने अधिग्रहण करनी है, उसका हमने पोजैशन लेना है व पोजैशन लेने के बाद जो एतराजात आएंगे उनको सैटल करना है। उसके बाद मंडी को जल्दी से जल्दी बनवाने की कोशिश करेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मंडियों के अन्दर जहां जहां पर भी शैड बन गए हैं उनका अभी तक औक्शन क्यों नहीं किया गया। मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि रिवाड़ी के अन्दर पिछले तीन साल से शैड बन कर तैयार हो चुके हैं लेकिन अभी तक वे औक्शन नहीं हुए हैं। लोग बाहर रेहड़ी लगाते हैं जिससे वहां से निकलना भी मुश्किल हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह इररेलेवेन्ट क्वेश्चन है। आप बैठिये।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह बताया कि यह मामला सब-जुडिस है, ये सब-जुडिस सिर्फ इसलिये कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने उन दुकानों की ओपन औक्शन करने के लिए पोलिसी बना ली है। अगर ये दुकानें रिजर्व प्राईस पर ही अलाट कर देते तो दुकानदार बेचारे कोर्ट में ही न जाते। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने मैनिफैस्टो में भी सस्ते दामों पर दुकानें देने के बारे में कहा था, मैनिफैस्टो मेरे पास है और आपने भी पढ़ा होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर ये सस्ते दामों पर दुकानें देने का फैसला कर लें तो यह मामला खत्म हो सकता है। यह एज ऐ मटर ऑफ पोलिसी की बात है। अध्यक्ष महोदय, जो लोग लाईसैंस होल्डर हैं उनको तो रिजर्व प्राईस पर दुकानें दे देनी चाहिएं, बाकि जिनके पास लाईसैंस नहीं हैं उनको ओपन औक्शन से दुकानें दे अगर ये ऐसा करेंगे तो सरकार के पास पैसा भी आ जाएगा और उन लोगों की तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि ये दुकानें लाईसैंस होल्डरों को सस्ते दामों पर देने के लिये बनाई गई थीं, लेकिन लाईसैंस होल्डरों में झगड़ा हो गया कि कौन लाईसैंस होल्डर है और कौन नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये दुकानें अलाट न होने से बोर्ड को बहुत ज्यादा नुक्सान हो रहा था इसलिए यह मामला कोर्ट में चला गया। अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही यह तय किया गया है कि इन दुकानों की ओपन औक्शन की जायेगी।

Construction of Roads

***617. Shri Dev Raj Dewan :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road from village Mahara to Sitauli in District Sonipat ?

Public Works Minister (Shri Dharam Vir Yadav) : This road stands already constructed.

श्री देव राज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के में माहरा से सितौली तक की सड़क टूटी पड़ी है, उसको कब तक ठीक करवायेंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क बहुत पुरानी बनी हुई है, इसका एस्टीमेट पास कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस सड़क को हम मार्च, 1999 से पहले ठीक करवा देंगे।

श्री देव राज दीवान : अध्यक्ष महोदय, एक इंच भी वह सड़क ठीक नहीं है, दो-दो, अढ़ाई-अढ़ाई फुट के गढ्ढे पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, गाड़ी, बैल गाड़ी को तो छोड़िए ट्रैक्टर भी वहां से नहीं जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी वहां मेरे साथ जायें और देखें कि उस सड़क की कितनी बुरी हालत है। (विघ्न)

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी बता चुका हूं कि उस सड़क को मार्च, 1999 से पहले ठीक करवा देंगे।

श्री जसविन्द्र सिंह सिंधु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय श्री अमर सिंह धानक पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर थे, उन्होंने कग साहब से अधोया तक की सड़क को बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन वह सड़क अभी तक भी पूरी नहीं बनी है, क्या मंत्री महोदय इस सड़क को बनवाने का काम करेंगे और अगर करेंगे तो कब तक करेंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मैं कल दूंगा। इसके लिये तो अलग से प्रश्न होना चाहिए था। (विघ्न)

श्री सूरज मल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मांगल से अटेरना तक चार पांच गांवों का एक रास्ता है वह रास्ता पिछले कई दिनों से टूटा पड़ा है, वह मुश्किल से 500 गज के करीब लम्बा होगा, वहां के लोग इस टूटे हुये रास्ते के कारण 15-20 कि०मी० घूमकर साईड से जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में एक्सीयन से शिकायत भी की थी लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अध्यक्ष महोदय, उस 500 गज जगह में बग्गी धंस जाती है, गाड़ी धंस जाती है, इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस सड़क को जल्दी से जल्दी ठीक करवायें।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, हम उस सड़क को जल्दी से जल्दी ठीक करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री सूरज मल : अध्यक्ष महोदय, यह काम जल्दी से जल्दी कोशिश करने वाला नहीं है बल्कि करने वाला है। यह बड़े दुख की बात है कि मंत्री जी ऐसा कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मेरे साथ वहां जाकर देखें तो इन्हे पता लग जायेगा कि लोगों को वहां पर कितनी तकलीफ हो रही है।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि किसी रोड़ को बनवाने के लिए पहले उसका एस्टीमेट पास करवाया जाता है, उसके बाद टैण्डर लिये जाते हैं, टैण्डर लेने के बाद किसी ठेकेदार को ठेका दिया जाता है और उसके बाद ही रोड़ ठीक की जाती है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस सड़क को बनवाने में कुछ समय तो लगेगा ही। सरकार कोई बनिये की दुकान तो है नहीं कि जो चाहे कर लिया। (विघ्न)

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से हाउस में बताना चाहूंगा कि पिछले सैशन में भी मैंने हसन गढ़ से खुर्म पुर रोड के लिए सवाल पूछा था और माननीय मंत्री जी ने इसको बनवाने का आश्वासन दिया था अब यह दूसरा सैशन आ गया है लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानकारी चाहूंगा कि इस सड़क को कब तक बना कर तैयार कर देंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मायना साहब को बताना चाहूंगा कि वे मुझ से मिले थे और मैंने उनके सामने ही एक्सीयन को टैलीफोन कर दिया था। इन्होंने स्वयं मुझ से यह कहा था कि काम शुरू हो गया है। अध्यक्ष महोदय, हम इस सड़क का काम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक दिन मिट्टी की एक ट्रॉली आई थी और मैंने सोचा कि काम शुरू हो गया है। (विघ्न)

श्री दिलू राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के में एक ब्रिज बन रहा था और मंत्री महोदय भी वहां पर गये थे। एक पब्लिक मीटिंग के अन्दर इन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि दो किलोमीटर का जो सड़क का टुकड़ा है इसको तीन महीने के अन्दर चालू कर देंगे, इस बात को करीब दो साल हो गये हैं अभी तक वहां पर एक टोकरी मिट्टी की भी नहीं पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि इस सड़क का काम कब तक पूरा करवा देंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, इस काम में अभी समय तो लगेगा क्योंकि अभी तक इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं हो पाई है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बाद ही कोई काम शुरू हो सकता है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहूंगा कि जब से यह सैशन चला है तब से ले कर आज तक पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर ने एक भी सवाल का जवाब सही नहीं दिया है। कहीं पर भी कोई काम नहीं हुआ है और झूठे बिल बना कर ये सारा पैसा हज़म कर गये हैं। क्या इस बारे में सरकार कोई निष्पक्ष इन्क्वायरी करवाएगी या किसी एजैंसी से कोई इन्क्वायरी करवाएगी ?

श्री अध्यक्ष : भागी राम जी, यह सवाल इररैलेवैन्ट है, आप बैठिए।

Supply of the Sprinkler Nozzle

***775. Shri Narpender Singh :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether Mahavir Aluminium Ltd., Delhi had supplied the Sprinkler Nozzle to the farmers during the period from 1986-87 to 1997-98; if so, the year-wise details thereof; and

(b) whether it is a fact that the firm referred to in part (a) above has supplied Sprinkler Nozzle Model 'A' and charged the rates of the Sprinkler Nozzle Model 'AA'; if so, the action taken against the said firm ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) :

(क) हाँ, श्रीमान जी । इस फर्म द्वारा सप्लाई किए गये फव्वारा संयन्त्रों का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) वर्तमान में यह मामला जाँच के अधीन है।

विवरण

क्र० सं०	वर्ष	आपूर्ति किए गये पैटों की संख्या
1.	1986-87	344
2.	1987-88	686
3.	1988-89	उपलब्ध नहीं है।
4.	1989-90	547
5.	1990-91	547
6.	1991-92	984
7.	1992-93	1097
8.	1993-94	218
9.	1994-95	69
10.	1995-96	352
11.	1996-97	388
12.	1997-98	221

श्री नृपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या साल 1997-98 से स्प्रिंक्लर नोज़लज़ का आई०एस०आई० मार्का होना आवश्यक कर दिया गया है यदि हां तो क्या दोनों मॉडलज़ की सप्लाई के आई०एस०आई० न होने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो पहला सवाल किया है ये दोनों मॉडलज़ "ए" और "एए" आई०एस०आई० मार्का कर दिए गए हैं, यह बिल्कुल ठीक है। दूसरे इन्होंने यह पूछा है कि क्या इस से सम्बन्धित इस कम्पनी ने ठीक सप्लाई नहीं की, इसकी कोई शिकायत प्राप्त हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में किसानों से अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है लेकिन डिवैल्पमैंट बैंक ने हमारे डिपार्टमैंट में एक क्वायरी जरूर लगाई है और उसका जवाब हम लिख कर बैंक को भेजेंगे। इस बारे हमारा डिपार्टमैंट पहले विस्तृत इन्क्वायरी कर रहा है।

श्री नृपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि अभी इस बारे में इन्वैस्टिगेशन्ज़ चल रही है, मैं उनसे यह जानकारी चाहूंगा कि यह जांच कब तक पूरी हो जाएगी ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सकेगा यह कम्पलीट हो जाएगी।

Repair of Damaged Roads of Narnaul City

***644. Shri Kailash Chander Sharma :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state the time by which the damaged roads of Narnaul city are likely to be repaired ?

Public Works Minister (Shri Dharamvir Yadav) : The P.W.D. roads in Narnaul city have already been repaired.

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मैं उससे सन्तुष्ट नहीं हूँ। इन्होंने कहा है कि नारनौल की पी०डब्ल्यू०डी० के अण्डर आने वाली सभी सड़कों की रिपेयर पहले ही कर दी गई है। क्या मंत्री जी वहां का कोई भी एक प्वायंट या किसी सड़क का नाम बताएंगे कि हमने वहां पर यह सड़क रिपेयर करी है ?

श्री धर्मबीर यादव : अध्यक्ष महोदय, पी०डब्ल्यू०डी० के अण्डर साढ़े आठ किलोमीटर का टुकड़ा आता है जिसका स्टेट हाई-वे नम्बर 17 और 26 है यह रेवाड़ी से खेतड़ी और महेन्द्रगढ़ से राजस्थान तक जाता है।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, साढ़े आठ किलोमीटर की कोई भी सड़क महेन्द्रगढ़ में नहीं है जोकि ये बता रहे हैं । ये जो बता रहे हैं वह महेन्द्रगढ़ से खेतड़ी तक बता रहे हैं आगे जाकर तो निजामपुर से राजस्थान लग जाता है।

श्री धर्मबीर यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न शहर के बारे में है रूरल एरिए का नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वह ठीक है मेरे पास नक्शा है ये उसको चश्मा लगा कर देख लें।

श्री नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जिला महेन्द्रगढ़ की सड़कें कब तक पूरी होने की सम्भावना है। क्या इस फाईनैंशियल ईयर में कोई और नई सड़क बनाने का सरकार का विचार है ?

श्री धर्मबीर यादव : अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ और नारनौल के आस-पास की सड़कें 1995-96 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई थीं और उन पर रिपेयर का काम चल रहा है। इस साल और अगले साल तक काफी सड़कों को रिपेयर कर दिया जाएगा। अगर कुछ सड़कें रिपेयर नहीं हो पाई तो उनको सन् 2000 तक रिपेयर कर दिया जाएगा।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने लिखित जवाब में आश्वासन दिया है कि सड़कों की रिपेयर कर दी गई है। नारनौल सड़कों की जो रिपेयर की गई हैं मंत्री जी उन सड़कों के नाम, सड़कों की लैंथ और उन पर कितना खर्चा आया है यह बताएं ?

श्री धर्मबीर यादव : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो निजामपुर नारनौल, महेन्द्रगढ़ दादरी रोड़ है यह 11 से 15 कि०मी० है इसकी लैंथ 4 कि०मी० है। रिवाड़ी नारनौल रोड 103.63 से 105.63 कि०मी० लम्बी है इसकी लैंथ 2.00 किलोमीटर है। नारनौल से सिंघाना रोड 106.10 से 108.00 कि०मी० है इसकी लैंथ 1.90 कि०मी० है और महावीर चौक से पुरानी कचहरी रोड तक 0.65 कि०मी० लैंथ है यह टोटल लैंथ 8.55 किलोमीटर बनती है और इस पर लगभग 16 लाख खर्चे का एस्टीमेट है।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : स्पीकर सर, मंत्री जी ने मुझे कहा है कि मैं चश्मा लगाकर देख लूं लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये केवल औफिस में बैठकर नक्शा ही देख लेते हैं और अपना सारा समय बर्बाद करते हैं लेकिन इनको मौके पर नारनौल में जाकर देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर आप वहां मौके पर जाकर देखें तो आप भी पाएंगे कि इन्होंने वहां पर कहीं भी रिपेयर नहीं करवायी है। मैं तो सामने जो लिखा हुआ है उसको देखकर बातें करता हूं इनको भी ऐसा ही करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप सवाल पूछें।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो यहां पर आठ किलोमीटर जगह बतायी है कि वह रिपेयर कर दी गयी है लेकिन मौके पर तो आठ किलोमीटर कोई जगह नहीं है और जब मौके पर ऐसी कोई जगह ही नहीं है तो फिर ये सड़क कहां बनायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा क्वैश्चन और क्या होगा ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, इसको दोबारा नपवा लेंगे।

Handicapped Welfare Fund

***782. Shri Dharambir Gauba :** Will the Minister for Social Welfare be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a National Handicapped Welfare Fund was evolved to create the jobs for the handicapped persons during the year 1983;

(b) whether any amount has been received from the Government of India for the aforesaid funds so far, if so, the yearwise details thereof; and

(c) the yearwise details of the amount spent so far out of the amount referred to in part (b) above ?

समाज कल्याण मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) :

(क) राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि, अपंगताओं का शीघ्र पता लगाने और उसकी रोकथाम करने हेतु विकलांगों के लिए सेवायें उपलब्ध कराने और अपंग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण, उनके शारीरिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्वयं सेवी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के ध्येय से वर्ष 1983 में स्थापित हुआ था।

(ख) मार्च, 1998 में वर्ष 1998-99 के लिए 2.25 लाख की राशि प्राप्त हुई है।

(ग) अभी तक कोई राशि खर्च नहीं हुई।

श्री धर्मवीर गाबा : स्पीकर सर, मंत्री जी ने बताया है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियाँ सृजित करने के लिए राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि के तहत अब भारत सरकार से 2.25 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं तो क्या यह राशि अभी तक सिर्फ पहली बार ही वहां से मिली है और क्या मंत्री जी इस बात से वाकिफ हैं कि वहां से जो भी पैसा जिस मद के लिए आता है, अगर वह उस मद में खर्च नहीं किया जाता है तो वह पैसा वापस सैंट्रल गवर्नमैंट को चला जाता है। क्या यह पैसा भी उनको वापस तो नहीं करना पड़ेगा ? क्या सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई स्कीम बनायी है ?

डॉ० कमला वर्मा : स्पीकर सर, जब यह 1983 में नोटिफिकेशन की गयी थी तो उस समय हमारे पास इसका कोई रिकार्ड नहीं था। 23-10-1997 को हमारे डायरैक्टर ने इस बारे में एक मीटिंग बुलायी

[डॉ० कमला वर्मा]
थी जिसमें केन्द्र सरकार का प्रौजैक्ट ओफिसर भी आया था। उन्होंने बताया कि हमारे पास एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत स्वैच्छिक संस्थाओं को विकलांगों के लिए काम करने के लिए वहां से पैसा दिया जाता है। उस मीटिंग में भिवानी जिले के रिहैबिलेटेशन ओफिसर भी थे और एक आर्थोपैडिक सर्जन भी था। इसके अलावा इस मीटिंग में बाकी स्टेट के दूसरे रिप्रैजेंटेटिव्ज भी थे। बाद में विकलांग रोगियों की शल्य चिकित्सा के लिए एक स्कीम बनायी गयी जो विकलांगों की सर्जरी कर सके और वे पूरी तरह से ठीक हो सकें। वह स्कीम बनाकर सैंट्रल गवर्नमैंट को भेजी गयी। 31-3-1998 को योजना की स्वीकृति और व्यय का ड्राफ्ट आया। इसके अनुसार हरियाणा सरकार ने इस बारे में एक सर्वेक्षण करवाया। बाद में भिवानी जिले के रिहैबीलिटेशन ओफिसर को ट्रैनिंग दी गयी। साथ ही कुछ और लोगों ने भी इस बारे में ट्रैनिंग ली। बाद में डायरैक्टोरेट के कुछ और ओफिसर्ज को भी यह ट्रैनिंग दिलवायी गयी। जिसकी वजह से हम एक महीना लेट हो गये और मई के महीने में इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सके। स्पीकर सर, अब यह पैसा आ चुका है और बरसात के बाद जल्दी ही हम इससे विकलांग रोगियों की शल्य चिकित्सा करवाएंगे। हमने 150 विकलांग रोगियों की चिकित्सा व शल्य क्रिया करने का ऐस्टीमेट्स बनाया हुआ है। हर महीने हमने 15 रोगियों की शल्य चिकित्सा करनी है लेकिन अब हमें ज्यादा रोगियों की शल्य चिकित्सा करनी पड़ेगी। स्पीकर सर, 2.25 लाख रुपये का पूरा इस्तेमाल शल्य चिकित्सा में किया जाएगा।

श्री धर्मबीर गाबा : स्पीकर सर, क्या मंत्री जी बताएंगे कि इन्होंने कोई इस बारे में रिप्रैजेंटेशन भारत सरकार को भेजी है कि इतनी बड़ी स्टेट के लिए 2.25 लाख रुपये बहुत कम है। इतनी राशि इस काम के लिए कोई मायने नहीं रखती। क्या कमिश्नर साहब को इन्होंने वहां भेजा है और क्या उन्होंने वहां पर इस बारे में कोई रिपोर्ट की है ? इसके अलावा मैंने पहले भी यह सवाल पूछा है कि क्या विकलांग लोगों को इम्प्लायमैंट देने के लिए कोई स्कीम तैयार की है जिससे उनको रोजगार मिल सके और उन गरीबों को रोटी मिल सके ?

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख यह होता है कि इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। मेरी सरकार ने तो योजना का पता लगाया, और अब 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की सहायता राशि उनसे लेंगे और इस राशि से हम विकलांगों की मदद अधिक कर सकेंगे। इसके अलावा हम बेरोजगारों को भत्ता देते हैं जिन बेरोजगार विकलांगों का रोजगार कार्यालय में नाम होता है और स्नातकोत्तर तक के जो भी अनइम्पलायड यूथ हैं उनको 150 रुपये से लेकर 250 रुपये मासिक भत्ता देते हैं इनके लिए 3 प्रतिशत नौकरियाँ रखी है इससे ज्यादा में कोई सुझाव दे दें तो हम विचार कर लेंगे।

श्री रामजी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहिबा से जानना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ ऐसी संस्थाओं का जिक्र किया है तो वे कौन-कौन सी संस्थाएं है जिनके माध्यम से विकलांगों की मदद की जा रही है और जिन संस्थाओं को सरकार पैसा दे रही है। वे ठीक ढंग से प्रैक्टिकली काम कर रही हैं या उन्हें पैसा ही दिया जाता है ?

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, स्वैच्छिक संस्थाओं को पैसा उस जिले के उपायुक्त के माध्यम से खर्च के लिए जाता है ऐसी 37 संस्थाएं है जिनको हमने पैसा दिया और वह ठीक तरह से प्रयोग हुआ और उन्हीं लोगों के लिए हुआ जिनके लिए दिया गया था। वर्तमान सरकार ने सैन्टर से 1 करोड़ 23 लाख रुपये का अनुदान लिया और रेड क्रास सोसायटीज को केवल 6-6 लाख रुपये केवल विकलांगों के उपकरण आदि के लिए दिए और जिन अन्य संस्थाओं को इसी कार्य के लिए पैसों की अधिक

आवश्यकता थी उनको अधिक भी दिये जिससे विकलांगों को उनकी जरूरत के उपकरण और बधिरों को श्रवण यंत्र आदि मिल सकें।

Repair of Roads

***783. Dr. Virender Pal Ahlawat** : Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state–

(a) whether it is a fact that the following roads of district Jhajjar which were badly damaged in the floods of 1995 have not been repaired so far :

(i) Dighal to Barhana;
(ii) Barhana to Chhochhi;
(iii) Beri Kalanaur road to village Dharana and Chimni;
(iv) Dhandlan to Gochhi;
(v) Jahajgarh to Dubaldhan via Paira; and

(b) if so, the time by which these roads are likely to be repaired ?

Public Works Minister (Shri Dharam Vir Yadav) :

(a) Yes, Sir.

(b) The roads will be repaired by June, 1999.

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : स्पीकर सर, 1995 में क्षतिग्रस्त हुई सड़कें अगर 1999 में ठीक की जाएंगी तो मेरे ख्याल में इन चार सालों के दौरान तो जो ठीक सड़क होगी वह भी ठीक नहीं रह पाएगी। गांव में रहने वाले लोगों की आने जाने की समस्या का समाधान कैसे होगा। कई सड़कें तो ऐसी हैं जिन पर कि यातायात के साधन इस वजह से नहीं जाते क्योंकि वहां रोड़ नहीं बनी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए। स्टेटमैंट न दीजिए।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : स्पीकर सर, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। जैसा अभी मंत्री जी ने बताया था कि वहां टैन्डर हो चुके हैं। वहां सड़क पर काम तो शुरू हुआ है लेकिन उन सड़कों पर जो थोड़ा बहुत आने जाने का रास्ता था वह भी मोटे-मोटे रोड़े पड़ जाने के कारण ब्लॉक हो गया है वहां रोलर भी नहीं घुमाया गया। वह रास्ता पैदल जाने लायक भी नहीं है तो क्या इन दिक्कतों को देखते हुए वहां काम 2-3 महीने में पूरा किया जाएगा यह आश्वासन मंत्री जी से चाहूंगा ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, जून 1999 तक इन सड़कों की रिपेयर कर दी जाएगी। उन सभी सड़कों पर काम चल रहा है। तारकोल आ चुका है, बरसात के बाद इन पर काम शुरू हो जाएगा।

श्री रमेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पिछले समय जो इन्होंने मेरे हल्के में सड़कें बनवाई, तो क्या उनके बारे में बताएंगे कि उनके ऊपर कितना खर्च आया है और वे कौन-कौन सी सड़कें हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह इररैलेवैन्ट क्वेश्चन है इसका इस सवाल से कोई संबंध नहीं है।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि बेरी हल्के की सड़कों का काम चालू है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्रमांक (1) से (5) तक की सड़कों की मरम्मत पर इस बजट के अन्दर कितने पैसों का प्रावधान किया गया है। दूसरी बात 1995 में जो झज्जर हल्के की सड़कों का नुकसान हुआ है उनके लिए मंत्री महोदय ने कितना पैसा अलाट किया है ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, क्रमांक संख्या (1) डीघल से बरहाना तक की सड़क की लम्बाई 4.65 कि०मी० है जिसमें से पौने चार कि०मी० सड़क डैमेज है तथा उसमें 1.75 कि०मी० सड़क रिपेयर हो चुकी है। जिस पर साढ़े चार लाख रुपये खर्च हुआ है। 1.7 कि०मी० सड़क अभी रिपेयर होनी बाकी है तथा 1.30 कि०मी० सड़क दुबारा से बननी है इस पर लगभग चार लाख रुपये खर्च होना है। (2) बरहाना से छौछी सड़क की लम्बाई 3.75 कि०मी० है। जिसमें से 2.1 कि०मी० सड़क डैमेज्ड हो गई है और 1 कि०मी० की रिपेयर चल रही है तथा 100 मीटर की रेजिंग की गई है जिसपर लगभग एक लाख रुपये खर्च किये गये हैं बाकी 1 कि०मी० सड़क की स्ट्रेंथ तथा रिकंस्ट्रक्शन जून 1999 तक हो जायेगी जिस पर लगभग साढ़े चार लाख रुपये खर्च होने हैं (3) बेरी कलानौर सड़क से गांव धराना तथा चिमनी की सड़क जिसकी लम्बाई 4.7 कि०मी० है जिसमें से 3.5 कि०मी० सड़क डैमेज्ड है उसमें से 2.75 कि०मी० सड़क रिपेयर की गई है, जिस पर दो लाख दस हजार रुपये का खर्चा हुआ है बाकी की सड़क पर कारपैटिंग करना बाकी है जिस पर लगभग 1.75 लाख रुपये खर्च होंगे (विघ्न) (4) भांडलान से गोछी की सड़क की लम्बाई 6 कि०मी० है जिसमें से 3 कि०मी० सड़क डैमेज्ड है, उसमें से 1 कि०मी० की रिपेयर हो चुकी है जिस पर नौ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है, उस पर प्रिमिक्सिंग और कारपैटिंग का काम भी होगा जो जून 1999 तक पूरा हो जायेगा। (5) जहाजगढ़ से दुबलधन वाया पलड़ा सड़क की लम्बाई 9.5 कि०मी० है जिसमें से 6.5 कि०मी० सड़क क्षतिग्रस्त है उसमें से 2 कि०मी० की रिपेयर कर दी गई है जिस पर 10 लाख रुपया खर्च हुआ है बाकी सड़क का काम जून 1999 तक पूरा हो जाएगा। जिस पर लगभग 9 लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बाढ़ के दौरान हुये नुक्सान पर इस हल्के पर होने वाले काम के बारे में खर्च का अनुमान पूछा है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 1996-97 के अन्दर 45 लाख रुपये, 1997-98 में 70 लाख रुपये सड़कों की रिपेयर पर खर्च हुए हैं जिसमें से 1996-97 में वाइडिंग पर 5.5 लाख रुपये, वार्षिक रख-रखाव पर साढ़े पांच लाख रुपये, वार्षिक सरफेसिंग पर साढ़े आठ लाख रुपये, बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर 34 लाख रुपये तथा 1997-98 में वार्षिक रख-रखाव पर दो लाख रुपये, वार्षिक सरफेसिंग पर पांच लाख रुपये तथा स्पैशल रिपेयर जो बाढ़ के दौरान सड़क क्षतिग्रस्त हुई उन पर 63 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, को बताना चाहूंगा कि ये जो सड़कें बारिश की वजह से या पानी खड़ा होने की वजह से बार-बार टूटती हैं, यह इसलिए टूटती हैं क्योंकि विभाग पुराने ढर्रे के मुताबिक उनकी रेजिंग कर देता है। अर्थ वर्क में ठेकेदारों व अन्य व्यक्तियों को कुछ मार्जन मिल जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां जहां पर इस रेजिंग को किया जाता है, इसका तब तक कोई प्रभाव होने वाला नहीं है जब तक कि सड़कों के साथ-साथ पानी निकालने के लिए नालियां नहीं बनाई जाएंगी। हरियाणा के अंदर कहीं भी, चाहे शहरों में अथवा देहातों में जहां कहीं भी पानी खड़ा होने की समस्या आ जाती है तो विभाग सड़कों की रेजिंग कर देता है तथा कोई नालियां वगैराह

नहीं बनाई जाती है। मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि भविष्य में कोई ऐसी नीति निर्धारित की जाए कि जहां जहां पर सड़कों की रेजिंग की जाए वहां पर पानी निकालने के लिए भी नालियों वगैरह का इंतजाम किया जाए अन्यथा इस रेजिंग को करने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही फरमाया है। लेकिन यह परम्परा बहुत पहले होती थी। मौजूदा सरकार के समय में जितनी भी सड़कों की रेजिंग की जा रही है, उन के साथ साथ नालियां भी जरूर बनाई जा रही हैं।

Paddy Growing Area

***699. Shri Bhagi Ram :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether any district of the State has been declared as paddy growing area; if so, the names thereof ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : नहीं, राज्य में किसी भी जिले को धान उपजाऊ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि जिस एरिया में धान की फसल होती है, उसके लिए पानी की सख्त जरूरत होती है और यदि एक दिन भी इस फसल को पानी नहीं दिया जाए तो फसल सूख जाती है। इसलिए इस फसल को पानी की अर्थात् बिजली की सख्त जरूरत होती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या पैडी एरिया में, जहां धान ज्यादा पैदा होता है, सरकार किसानों को विशेष रूप से ट्यूबवैल चलाने के लिए बिजली देने का प्रावधान कर रही है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि क्या सरकार पैडी एरिया में विशेष तौर पर पानी अथवा बिजली दे रही है। मैं इन को बताना चाहूंगा कि जहां तक पानी देने की बात है, वह कृषि विभाग की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। सिंचाई विभाग की तरफ से किसानों को मोगों के द्वारा अच्छे तरीके से पानी दिया जा रहा है। जहां तक इन्होंने बिजली के बारे में कहा है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे बिजली की कितनी भारी कमी हो लेकिन हमारी सरकार बिजली की वजह से किसानों की फसलों को प्रभावित नहीं होने देती है तथा किसानों को अपनी फसल पकाने के लिए बिजली देने का पूरा प्रयास कर रही है।

श्री भागीराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि मौजूदा सरकार किसानों को ज्यादा बिजली दे रही है। मैं कहना चाहता हूं कि नहरों में जहां कहीं भी पानी के मोगे हैं, किसानों को ये हर साल मंजूर करवाने पड़ते हैं। क्या यह बात मंत्री जी के नोटिस में है ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, के नोटिस में यह बात होगी कि नहरों के मोगे मंजूर करवाने के लिए हर साल कुछ लेना देना पड़ता है इसलिए सरकार कुछ ऐसा उपाय करे कि हर साल किसानों को इसके लिए लेना-देना न पड़े। सीजन के समय सरकार को नहरों में रैगुलर मोगे खोल देने चाहिएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पहली जुलाई से 10 सितम्बर तक हम ये दरख्वास्ते मांगते हैं क्योंकि हर किसान को टेल पर पानी देना हमारा फर्ज है।

[श्री कर्ण सिंह दलाल]
जब मोगा देते हैं तो यह ध्यान देते हैं कि टेल पर जो किसान हैं उनको किसी तरीके से पानी का नुकसान न हो। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने धान के बारे में जो चिन्ता जताई है जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बिजली प्राथमिकता के आधार पर दी जाती हैं और जो जिले धान उगाते हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर बिजली देते हैं। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 48 लाख यूनिट बिजली कुरूक्षेत्र और करनाल जिलों को एलोकेट की गई है।

श्री भागी राम : सिरसा जिले की ऐलनाबाद कांस्टीच्युएंसी के जीवन नगर एरिया में सैन्ट परसैंट धान ही धान पैदा होती है क्या वहां पर आप कोई रियायत देते हैं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : आप किस तरीके की रियायत की बात कर रहे हैं ?

श्री भागी राम : मैं बिजली ज्यादा देने की रियायत के बारे में कह रहा हूं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, किसानों की फसल को बिजली की वजह से नुकसान न हो, चाहे सिरसा जिला हो या दूसरे जिले हों, हम उनको प्राथमिकता के आधार पर, जरूरत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा बिजली देने की कोशिश करते हैं। माननीय सदस्य अगर सिरसा के बारे में कोई दिक्कत महसूस करते हैं तो लिखकर बताएं। हमसे जितनी मदद हो सकेगी, हम करेंगे।

श्री जयसिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, किसी क्षेत्र को धान उपजाऊ क्षेत्र घोषित किया जाए और उस क्षेत्र में बिजली ज्यादा देने के बारे में ये 'न' में जवाब दें इसका क्या कारण है। जिस पूरे क्षेत्र में धान की फसल होती है और उसको धान उपजाऊ क्षेत्र घोषित किया जाए तो क्या कारण है कि ये उसमें ज्यादा बिजली नहीं दे सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि कुछ क्षेत्रों में नहरों का पानी केवल धान की फसल के लिए यानि एक फसल के लिए ही मिलता है। आज जीरी की बहुत अरली किस्में आ गई हैं, जो कि जल्दी लगाई जाती हैं। किसान जून के महीने में सारी जीरी लगाकर अपना काम कर लेता है। नहरों में पानी 15 जुलाई तक तक नहीं छोड़ा जाता। क्या सरकार भविष्य में इस पर विचार करेगी कि यह पानी पहली जून को ही नहरों में दे दिया जाए जिससे किसान पूरा लाभ उठा सकें ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : किसी भी कानून में इस तरह का प्रावधान नहीं है कि किसी भी इलाके को धान उपजाऊ एरिया घोषित किया जाए। जैसा इन्होंने कहा, यह सही है कि धान के मामले में किसान विकासशील हो गया है। नई-नई किस्मों के धान के बीज हमारे हरियाणा प्रदेश के अन्दर आए हैं लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि किसान की फसल को किसी भी तरीके से नुकसान न हो हम इस बात की कोशिश करते हैं कि उनको बिजली और पानी पूरा मात्रा में मिले। हरियाणा में जो धान उपजाऊ क्षेत्र जाने जाते हैं उनमें हमारी सरकार इस बात का ख्याल करती है कि उनको बिजली और पानी दें।

Building of Govt. Hospitals, Safidon

***716. Sh. Ram Phal Kundu :** Will the Minister for Health be pleased to state whether the Government is aware of the fact that the building of Government General Hospital, Safidon, is in dilapidated condition; if so, the time by which it is likely to be repaired or constructed a new one ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : यह सही नहीं है कि राजकीय सामान्य अस्पताल, सफीदों का भवन खस्ता हालत में है।

श्री रामफल कुण्डु : स्पीकर साहब, सफीदों के जनरल होस्पीटल की बिल्डिंग बहुत पुरानी है। जिन कमरों में मरीजों के बैड लगे हुए हैं उनके साथ साथ दीवारों पर लुणी लग जाती है और बरसात का पानी नीचे आता रहता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस बिल्डिंग की रिपेयर कराई जाएगी या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सफीदों जनरल होस्पीटल की बिल्डिंग लगभग 40 साल पुरानी है लेकिन वह बिल्डिंग ठीक ठाक है। हर साल उस बिल्डिंग की रिपेयरिंग की जाती है। यह बात नहीं है कि उस बिल्डिंग की रिपेयर के लिए पैसा नहीं दिया गया है उसकी मुरम्मत के लिए इस साल भी पैसा दिया है। यह बात ठीक है कि उसमें जो सड़कें हैं वे खराब है। उन सड़कों की मरम्मत के लिए 4 लाख 21 हजार रुपये का एस्टिमेट बन कर आ गया है उसकी एप्रूवल के लिए गवर्नमैंट को केस जाएगा। अगर माननीय सदस्य चाहें तो सैशन के बाद, मैं खुद मौके पर जा कर उस होस्पीटल को देख लूंगा अगर उसमें कोई कमी होगी तो उसको भी पूरा करवा देंगे।

श्री रामफल मांजरा : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जनरल होस्पीटल्ज की ऐसी कितनी बिल्डिंग्ज हैं जो अनसेफ डिक्लेयर की हुई हैं और इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जितनी बिल्डिंगज अनसेफ डिक्लेयर की हुई हैं क्या वहां पर नई बिल्डिंगज प्राथमिकता के आधार पर बनाने की सरकार की कोई योजना है ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, फिलहाल हमने 261 बिल्डिंग्ज छांटी हैं जिनको रिपेयर करने की आवश्यकता है जिनमें जनरल होस्पीटल्ज की बिल्डिंग्ज, पी०एच०सीज० की बिल्डिंग्ज और सी०एच०सीज० की बिल्डिंग्ज शामिल हैं। अगर माननीय सदस्य के ध्यान में और कोई ऐसी बिल्डिंग हो जिसको रिपेयर करने की आवश्यकता है तो वह मुझे बता दें उसका निरीक्षण करवा लिया जाएगा।

श्री बलबीर सिंह : स्पीकर साहब, बलम्भा गांव में सी०एच०सी० की बिल्डिंग तैयार है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस सी०एच०सी० को कब तक चालू करवा दिया जाएगा ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, सैशन के बाद उसको देखने की कोई तारीख तय कर लेंगें फिर उस बारे में विचार करेंगे कि वह तैयार है या नहीं।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सैशन के बाद मंत्री कहां मिलते हैं।

श्री सिरी किशन हुड्डा : स्पीकर साहब, पिछले सैशन में मंत्री जी ने वायदा किया था कि किलोई सी०एच०सी० की बिल्डिंग जल्दी ही बना दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने वहां पर सी०एच०सी० की बिल्डिंग बनाने के बारे में कोई कार्यवाही शुरू की है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, इस साल 10 नए होस्पीटल, 9 सी०एच०सी० और 29 पी०एच०सी० बनाने का सरकार का विचार है इनमें वह शामिल नहीं है अगले वर्ष यह नाम आ सकता है।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में मैंने मंत्री जी से कहा था कि बादली में पी०एच०सी० की बिल्डिंग बनी हुई है उसको टेकओवर किया जाए। इन्होंने उस समय यह आश्वासन दिया था कि उसको टेकओवर कर लिया जाएगा। फिर मैंने एक साल के बाद करीब दो महीने पहले इनको इनके औफिस में आ कर उसके बारे में याद दिलवाया लेकिन आज भी वह बिल्डिंग उसी हालत में है। वह नई बिल्डिंग है और खराब हो रही है। उस पी०एच०सी० को किसी छोटी सी टैक्नीकल बात की वजह से चालू नहीं किया जा रहा है। उस बिल्डिंग को बनाने पर जनता का पैसा खर्च हुआ है। आज फिर दोबारा से मैं मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि बादली सी०एच०सी० को स्वास्थ्य विभाग कब तक चालू करवा देगा?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, अगस्त का महीना हमने इन्हीं कामों के लिए रखा है। हम उस वक्त विजिट करेंगे और उस समय इसकी कोई तारीख तय करेंगे।

श्री धर्मवीर गावा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने ऐसा कोई सर्वे करवाया है कि अस्पतालों की या डिस्पेंसरियों की कितनी बिल्डिंगज खराब हैं और उनको कब तक ठीक करा दिया जायेगा। क्या ऐसा कोई कम्प्रेहेन्सीव सर्वे करवाया गया है?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, जैसे इस सरकार के मुखिया को चिन्ता है यदि इसी प्रकार से इनके वक्त के मुखिया को या इनको चिन्ता होती तो आज यह सवाल करने की नौबत ही न आती। फिर भी मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगस्त के महीने में हम इन सारी चीजों को देखेंगे।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, सांपला में जो सी०एच०सी० है उसकी बहुत बुरी हालत है। उसकी चार दीवारी आज तक नहीं बनाई गई है। मैंने भी इस बारे में कई दफा आवाज उठाई है लेकिन अभी तक न तो चार दीवारी बनाई गई है और न ही वहां पर मरम्मत की गई है। दूसरे मैं एक बात और इनके नोटिस में लाना चाहूंगा कि वहां पर कोई भी डाक्टर बैठने के लिए तैयार नहीं होता। क्या मंत्री महोदय, इन सभी बातों पर गौर फरमाएंगे?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, इनकी इस बात का भी यही जवाब है कि हम अगस्त के महीने में जब सारी स्टेट का सर्वे करेंगे तो उस वक्त इसको भी देखेंगे।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब में कहा कि इस साल 9 सी०एच०सीज० बनाने जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनमें ऐलनाबाद भी शामिल है?

श्री ओम प्रकाश महाजन : जी हां।

तारांकित प्रश्न संख्या 763

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नफे सिंह राठी सदन में उपस्थित नहीं थे)

Augmentation of 220 K.V. Sub Station of Dhulkot

***787. Shri Anil Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to augment the capacity of 220 KV Sub-Station at Dhulkot, Ambala ?

Minister of State For Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : No, Sir. अध्यक्ष महोदय, इसके बनाये जाने की कोई योजना नहीं है क्योंकि इसके दो तीन कारण हैं। एक तो यह 1958-59 को लगाया गया था। इसकी मशीनरी बहुत पुरानी हो चुकी है इसलिए इसकी क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर इसकी क्षमता बढ़ा भी दें तो यह सब स्टेशन एक ऐसी जगह पर है जहां पर इस सब स्टेशन के चारों तरफ शहर है जिस कारण हम वहां से कोई नया फीडर या नई लाईन नहीं निकाल सकते। दूसरे इसका कंट्रोल बी०बी०एम०बी० के पास है, हमारे पास नहीं है इसलिए हम इसकी क्षमता नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इलाके की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने अम्बाला के पास टेपला गांव में इस काम के लिए 29 एकड़ जमीन ले ली है। यह जमीन हमारे कब्जे में है। इस पर 34 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। हम अगले महीने इसके टैण्डर निकाल देंगे। वहाँ पर समस्या को देखते हुए हमने 66 के०वी० का एक सब स्टेशन अम्बाला कैंट के इण्डस्ट्रीयल एरिया में लगाने की योजना बनाई है। इस पर अढ़ाई करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इस पर एक महीने के अन्दर अन्दर काम शुरू हो जायेगा। यह हमने वहां के लिए आल्टरनेटीव इन्तजाम किया है। हम मौजूदा सब स्टेशन की क्षमता को नहीं बढ़ा सकते हैं।

Mr. Speaker : Questions hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Bus Permit

***613. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for Transport be pleased to state the total number of permits have been issued to the unemployed youths for plying of buses in the State under stage carriage permits during the year , 1996-97, 1997-98 ?

परिवहन मन्त्री (श्री कृष्ण पाल गुर्जर) : कोई भी यात्री वाहन परमिट (वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान) बेरोज़गार युवकों को बस चलाने के लिये जारी नहीं किए गए।

Bhalot Minor

***683. Shri Balwant Singh :** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the water of Bhalot Minor does not reach upto its tail; and

(b) if so, the reasons thereof togatherwith steps taken or proposed to be taken to supply the water up to the tail of the said minor ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) :

(क) व (ख) नहीं, श्रीमान जी। फिर भी मई-जून में तालाबों को भरने के कारण व अक्तूबर-नवम्बर में बरसात की वजह से गाद भरने के कारण कुछ कमी आती है। जब भी नहर के अन्तिम छोर पर पानी की कमी पड़ी, समय पर गाद व घास फूस निकालने के लिये कदम उठाये गये।

Financial Assistance for the Maintenance of National Highways

***688. Shri Jai Singh Rana :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) the total length of the National Highways in the State; and

(b) the details of the financial assistance, if any, received from the Central Government for the maintenance of the aforesaid Highways during the year 1995-96, 1996-97 and proposed to be received during the current financial year 1998-99 ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव) :

(क) हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राज-मार्गों की कुल लम्बाई 898.261 कि०मी० है।

(ख) राष्ट्रीय राजू-मार्गों के रख-रखाव के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	वित्तीय सहायता प्राप्त राशि (रुपये लाखों में)
1995-96	756.70
1996-97	885.24
1997-98	772.34
1998-99	689.42 (ऑन अकाउन्ट पेमैंट तौर पर प्राप्त)

Income accrued from the Auction of Liquor Vends

***626. Shri Sampat Singh :** Will the Minister for Prohibition, Excise and Taxation be pleased to state the total income likely to be accrued from the auction of liquor vends or any other sale of liquor/Excise duty in the State during the current financial year ?

निषेध, आबकारी तथा कराधान मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) :

उपरोक्त तारांकित प्रश्न नं० 626 का उत्तर निम्न प्रकार से है :-

वर्ष 1998-99 के दौरान 1130 ठेकों की नीलामी से 491 करोड़ की आबकारी आय प्राप्त होगी तथा आबकारी से कुल राजस्व आय 775 करोड़ अनुमानित है जिसमें देशी व अंग्रेजी शराब इत्यादि पर लगने वाली आबकारी ड्यूटी भी शामिल है।

Chautala & Teja Khera Distributaries

***741. Shri Mani Ram :** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state the details of the amount spent on the desilting of Chautala and Teja Khera distributries separately during the year 1997-98 ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) :

सूचना निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रजबाहे का नाम	वर्ष 1997-98 के दौरान गाद निकालने का खर्चा
1.	चौटाला रजवाह	17,263.00 रुपये
2.	तेजा खेड़ा रजवाह	शून्य

Opening of Government College for Girls

***771. Shri Ramji Lal :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open a Government College for Girls in District Yamuna Nagar; and

(b) if so, the time by which the aforesaid college is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) :

(क) तथा (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Criteria adopted for recruitment of Police Constables

***789. Shri Krishan Lal :** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the details of the criteria, if any, adopted for the recruitment of Police Constables being made in the state at present togetherwith the district-wise number of such posts to be filled up; and

(b) the district-wise number of posts out of those referred to in part (a) above belonging to Scheduled Castes and Backward Classes ?

गृह मन्त्री (श्री मनी राम गोदारा) :

(क) सिपाहियों की भर्ती से सम्बन्धित सिद्धांतों का विस्तृत विवरण जैसा कि नियम 12.14 से 12.18 पंजाब पुलिस नियमावली, 1934 (जो हरियाणा राज्य पर लागू है) तथा

[श्री मनी राम गोदारा]

समय-समय पर संशोधित किया गया है, के साथ सीटों का आवंटन चयन परिषद वार सदन के पटल पर प्रविष्ट (क) में रखा है।

(ख) अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की श्रेणियों के लिए श्रेणी वार विवरण चयन परिषद वार सीटों का आवंटन प्रविष्ट (क) में दर्शाया गया है।

प्रविष्ट (क)

मान दण्ड सम्बन्धित विस्तृत विवरण समय-समय पर संशोधित किये गये पंजाब पुलिस नियमावली जो कि हरियाणा में लागू है, में अंकित है। प्रस्तुत अंतिम संशोधन हरियाणा सरकार द्वारा जारी राजपत्र (असाधारण) दिनांक जून 17,1998 में छपा हैं। फिर भी इसके कुछ अंश निम्नलिखित हैं :-

(क) (आयु) उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम तथा 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। लेकिन अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये ऊपरी आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों के अनुसार होगी।

(ख) शारीरिक माप

ऊँचाई : 5 फुट 7 ईंच

छाती : 33 × 34-1/2 ईंच

अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की ऊँचाई और छाती में एक-एक ईंच की छूट दी जायेगी।

(ग) शैक्षणिक योग्यतायें

सामान्य एवं पिछड़े वर्ग	अनुसूचित जाति एवं जन जाति
10वीं (मैट्रिक)	8 वीं (मिडिल) पास

(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा

(1) 100 मीटर की दौड़

(2) 800 मीटर की दौड़

(3) लम्बी कूद

(4) ऊँची कूद

शारीरिक दक्षता परीक्षा के कुल 20 अंक हैं तथा उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास होने के लिए 9 अंक प्राप्त करने होंगे। उम्मीदवार जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास होंगे, का साक्षात्कार एक चयन परिषद द्वारा उसकी सिपाही के पद की योग्यता बारे होगा। साक्षात्कार/व्यक्तित्व के लिये अधिकतम अंक 15 निर्धारित किये गये हैं। उपरोक्त परीक्षा तथा साक्षात्कार के पश्चात उम्मीदवार का चयन सम्पूर्ण श्रेष्ठता तथा आरक्षित पदों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। चुने गये उम्मीदवारों की चिकित्सा उपयुक्तता के बारे चिकित्सा परीक्षा होगी। चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों का

सिपाही की नियुक्ति से पूर्व चरित्र सत्यापन करवाया जायेगा। उपरोक्त चुने गये उम्मीदवारों की नियुक्ति का कार्य जहां भी रिक्तियां उपलब्ध होगीं, हरियाणा सशस्त्र पुलिस वाहिनीयों के आदेशकों द्वारा किया जाएगा।

(ख) वर्तमान में 1800 सिपाहियों की भर्ती का कार्य चल रहा है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को आरक्षण सरकार की हिदायतों के अनुसार दिया जायेगा। चयन परिषद वार सिपाई की भर्ती के लिए सीटों का आवंटन इस प्रकार है :-

क्र० संख्या	चयन केन्द्र का नाम	आवंटित सीटें	सामान्य वर्ग	अनुसूचित जाति 'क' खंड	अनुसूचित जाति 'ख' खंड	पिछड़े वर्ग 'क' खंड	पिछड़े वर्ग 'ख'खंड
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अम्बाला	100	53	10	10	16	11
2.	पंचकूला	20	11	2	2	3	2
3.	कुरूक्षेत्र	60	33	6	6	9	6
4.	कैथल	100	53	10	10	16	11
5.	यमुनानगर	100	53	10	10	16	11
6.	हिसार	120	63	12	12	20	13
7.	भिवानी	140	73	14	14	23	16
8.	फतेहाबाद	80	43	8	8	13	8
9.	सिरसा	100	53	10	10	16	11
10.	जींद	120	63	12	12	20	13
11.	गुड़गांव	120	63	12	12	19	14
12.	फरीदाबाद	120	63	12	12	19	14
13.	नारनौल	60	33	6	6	9	6
14.	रिवाड़ी	60	33	6	6	9	6
15.	रोहतक	100	53	10	10	16	11
16.	झज्जर	10	52	1	10	16	12
17.	सोनीपत	120	63	12	12	20	13
18.	पानीपत	60	33	6	6	9	6
19.	करनाल	120	63	12	12	19	14
	कुल	1800	954	180	180	288	198

[श्री मनी राम गोदारा]

सरकार की हिदायतों के अनुसार, 15 प्रतिशत समतल आरक्षण (सामान्य वर्ग 4 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग 'ए' ब्लाक 3 प्रतिशत, 'बी' ब्लाक 3 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति 5 प्रतिशत) भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित वर्ग एवं सामान्य वर्ग में दिया जाएगा।

Sand Mines

***767. Shri Suraj Mal :** Will the Minister for Mines and Geology be pleased to state—

(a) the depth upto which the excavation of sand mines is legal; and

(b) whether the government is aware of the fact that the excavation of sand mines is being done illegally in Rai Constituency, if so, the details thereof together with the action taken in this regard ?

खान एवं भू-विज्ञान मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) :

(क) हरियाणा में रेत का खनन खुली खानों द्वारा किया जाता है। धातुमय खान विनियमन 1961 के विनियमन 106 (I) (II) के अनुसार ऐसा खनन, खनन खड्डों में सीढ़ियां बनाकर किया जा सकता है तथा किसी सीढ़ी की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक तथा चौड़ाई ऊंचाई से कम नहीं होनी चाहिए। इन विनियमन में गहराई की अधिकतम सीमा का प्रावधान नहीं है।

(ख) राई विधान सभा क्षेत्र से रेत की अवैध निकासी की कोई सूचना नहीं है।

Number of Cases registered under violation of Prohibition Policy

***611. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the districtwise total number of cases registered and vehicles impounded on account of selling illicit liquor/violation of prohibition act in the state till it remained enforced; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the government to withdraw the cases as referred to in part (a) above ?

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) :

(क) सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ख) नहीं।

विवरण

राज्य में जब तक मद्य निषेध नीति लागू रही, दर्ज किये गये मुकदमों की जिलावार संख्या एवं नाजायज शराब बेचने में जब्त किए गये वाहनों की संख्या निम्न प्रकार से है :-

जिला	कुल दर्ज किये गये मुकदमों की संख्या	जब्त हुए वाहनों की संख्या
1	2	3
पंचकुला	3694	420
अम्बाला	6003	512
यमुनानगर	4935	383
कुरुक्षेत्र	7258	322
कैथल	7027	157
हिसार	4841	719
सिरसा	7957	724
भिवानी	4600	469
जींद	6875	377
फतेहाबाद	4359	407
गुड़गांवा	3926	555
फरीदाबाद	6046	727
नारनौल	3089	434
रिवाड़ी	3330	367
रोहतक	4492	259
सोनीपत	3546	239
करनाल	8627	233
पानीपत	4432	206
झज्जर	2271	262
रेलवेज (हरियाणा)	3176	17
योग	100484	7789

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Number of Electricity Connections

44. Shri Sampat Singh : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of electricity connections in domestic, commercial, agricultural and industrial sectors in the State as on 31-3-96, 31-3-97 and to-date ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : श्रीमान , उदधृत तिथि को श्रेणी अनुसार बिजली कनैक्शनों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी :-

श्रेणी	31-3-96	31-3-97	31-5-98
घरेलू	2397663	2510670	2620330
गैर घरेलू	311466	321288	332957
कृषि	375934	366540	364800
औद्योगिक	76482	77422	79217

Installed Power Generating Capacity

45. Shri Sampat Singh : Will the Chief Minister be pleased to state the total installed power generating capacity in the State from its own resources and the actual power generated in the years 1975-76, 1990-91, 1997-98 and to-date ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : श्रीमान जी, राज्य की अपनी स्थापित उत्पादन क्षमता तथा वर्णित वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	स्थापित उत्पादन क्षमता	उत्पादन लाख यूनिटों में
1975-76	145.8 मैगावाट	3235.8
1990-91	878 मैगावाट	26054.16
1997-98	863 मैगावाट	33675
1998-99/6-98/	863 मैगावाट	6941

Electricity Consumed by the Tubewells

46. Shri Sampat Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total units of power consumed by the Agricultural Tubewells in the State on metered and un-metered separately during the years 1990-91, 1996-97, 1997-98; and

(b) the total amount of bills issued to the aforesaid Agricultural Tubewells on metered and un-metered separately during the period as referred to in part (a) above ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) :

क. ट्यूबवैलों द्वारा मीटर से या बिना मीटर के उपभोग की गई बिजली का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	मीटर द्वारा (यूनिट लाखों में)	बिना मीटर के (यूनिट लाखों में)
1990-91	4363	20813
1996-97	5250	33586
1997-98	5108	31662

ख. उपरोक्त उपभोक्ताओं को बिल में दी गई राशि निम्न प्रकार से थी :-

वर्ष	मीटर द्वारा (रुपये लाखों में)	बिना मीटर के (रुपये लाखों में)
1990-91	1239	3331
1996-97	3466	15079
1997-98	3347	16309

Number of Industries in the State

47. Shri Sampat Singh : Will the Minister for Industries be pleased to State—

(a) the total number of industries registered in the State as on 31-3-96, 31-3-97, 31-3-98 and to-date together with the number of industries out of them are in running condition at present; and

(b) the total number of industries closed in the years 1996-97, 1997-98 and during the current financial year; if so, the reasons therefore?

उद्योग मंत्री (श्री शशि पाल मेहता) :

वांछित सूचना निम्न प्रकार से है :-

(क) राज्य में 31-3-96, 31-3-97, 31-3-98 और 30-6-98 तक कुल पंजीकृत इकाइयों की संख्या क्रमशः 132758, 138381, 143141 एवं 143499 है। इनमें से 65598 औद्योगिक इकाइयां इस समय चालू हालत में है।

[श्री शशिपाल मेहता]

(ख) वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं चालू वित्त वर्ष (30-6-98 तक) में कुल बन्द हुई औद्योगिक इकाइयों की संख्या क्रमशः 130, 105 एवं शून्य है। शेष इकाइयां वर्ष 1967 से 1997 की अवधि में बन्द हुई। इन इकाइयों के बन्द होने की वास्तविक तिथि की सूचना नहीं है।

उद्योगों के बन्द होने के कारण :-

साधारणतः लघु उद्योग इकाइयां (क) एन्टरप्रीन्योरशिप का अभाव (ख) तकनीकी कुशलता का अभाव (ग) भागीदारों में झगड़ा (घ) वित्तीय कठिनाई (ङ) मार्केटिंग की समस्या, और (च) श्रमिक समस्या आदि के कारण बन्द होती है।

विभिन्न मामले उठाना/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं इत्यादि

15.00 बजे **श्री जसविन्द सिंह सिधु :** अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन में एक बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सन् 1947 में हिन्दुस्तान आज़ाद हुआ था और बहुत सारे वीरों ने इस आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। अध्यक्ष महोदय, उन वीरों में सिख जाति के वीर भी शामिल थे और उनका भारत को आजाद कराने में विशेष योगदान रहा। अध्यक्ष महोदय, काले पानी की सजा हुई उसमें भी सिखों की आबादी बहुत अधिक थी। अध्यक्ष महोदय, उस समय सिखों की जमीन कुर्क कर ली गई तब भी सिख वीर आजादी की लड़ाई से पीछे नहीं हटे । वे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गये। अध्यक्ष महोदय, आजादी मिलने के बाद भारत वर्ष के संविधान का निर्माण हुआ और उस संविधान में सिखों को एक विशेष अधिकार दिया गया कि वे 6 इंच लम्बी कृपाण रखकर कहीं भी आ जा सकते हैं चाहे वह राष्ट्रपति भवन हो, प्रधान मंत्री कार्यालय हो या किसी भी राज्य की विधान सभा हो चाहे हवाई जहाज में यात्रा करनी हो। अध्यक्ष महोदय, सरदार सर्वजीत सिंह मेरे पास आये और कहने लगे कि मुझे कृपाण के साथ विधान सभा में नहीं जाने दे रहे हैं। गार्ड कहते हैं कि अगर आपने अंदर जाना है तो आप कृपाण उतार कर जाओ, वरना वापिस जाओ। अध्यक्ष महोदय, अमृत छका हुआ सिख कभी भी अपनी कृपाण नहीं उतारता है। अध्यक्ष महोदय, उस आदमी को लेकर मैं आपके पास आया, आपके चैम्बर में मुख्यमंत्री महोदय भी बैठे हुए थे। मैंने आपसे प्रार्थना की कि आप उनको कृपाण के साथ अंदर जाने की इजाजत दे दें लेकिन आपने उनको कृपाण के साथ अंदर नहीं आने दिया। अध्यक्ष महोदय, सरदार सर्वजीत सिंह वापिस चला गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भारत के संविधान में उनको विशेषाधिकार दे रखा है तब आपने उन्हें अंदर आने की इजाजत क्यों नहीं दी, उस विशेषाधिकार का क्या फायदा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। (विघ्न एवं शोर)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, 6 इंच से छोटी कृपाण मैम्बर भी किसी राज्य की विधान सभा या हमारी लोक सभा में पहनकर जा सकते हैं।

श्री धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि गुड़गावां में न्यू कालोनी के नाम से एक कालोनी है, जो रिसैटलमेंट कालोनी है। यह कालोनी आज से 50-60 साल पहले बनाई गई थी। अध्यक्ष महोदय, इस कालोनी में हरियाणा

सरकार की जमीन खाली पड़ी है जो कि शिक्षा विभाग के लिए रखी हुई है। अध्यक्ष महोदय, उस जमीन पर एक आदमी ने नाजायज कब्जा कर लिया है। वह कहता है कि यह जमीन मेरी है जबकि असलियत यह है कि वह जमीन हरियाणा सरकार के एजुकेशन डिपार्टमैंट की है। अध्यक्ष महोदय, उस आदमी ने कोर्ट में केस करके उस जमीन पर अपना कब्जा कर लिया उस जमीन पर गवर्नमैंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस जमीन के बारे में जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाये।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रिय साथी बताएंगे कि वह जमीन कहां है।

श्री धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, जिस जमीन के बारे में मुख्य मंत्री महोदय पूछ रहे हैं वह जमीन न्यू कालोनी, गुड़गावां में है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मेरा सरदार जसविन्द्र सिंह जी से अनुरोध है कि हाऊस स्थगित होने पर मुझ से आकर मिलें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जसविन्द्र सिंह जी चैम्बर में आपसे मिल कर ही आए हैं और वहां पर आपने उनको अलाउ नहीं किया। इसीलिये वे यहां हाऊस में पूछ रहे हैं। वे आपसे इस बारे में आपकी रूलिंग चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, इस बारे में रिकार्ड देख लेते हैं इस प्रकार की किसी को कोई इजाजत नहीं है। Let me examine the record.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पंजाब विधान सभा के अन्दर भी 6" तक की कृपाण ले कर जाते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जहां तक मेरा विचार है विधान सभा के अन्दर विजिटर कृपाण लेकर नहीं जा सकते हैं। एम०एल०ए० ले जा सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, दूसरे लोगों को भी अलाउड है कि छः इंच तक की कृपाण लेकर हाउस में जा सकते हैं। ऐसी इजाजत है और उसी के तहत वे आपसे आपके चैम्बर में भी मिले लेकिन आपने उनको अन्दर आने की इजाजत नहीं दी। आपकी तरफ से संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने के कारण जसविन्द्र सिंह जी ने इस मुद्दे को यहां पर उठाया है और वे इस बारे में आपकी रूलिंग चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरी जानकारी के मुताबिक जो विधायक हैं उनको ही यह परमिशन है। Let me examine the record of this House. मेरी जानकारी के मुताबिक तथा आफिसर्ज ने मुझे जो जानकारी दी है विधायक के आलावा कोई भी जो गैलरी में आता है उसको यह इजाजत नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात नहीं है यह तो कांस्टीच्यूशन का मामला है। आप तो कांस्टीच्यूशन का बहुत ऐहतराम करते हैं, जो फैसला आपने सुनाया है यह ठीक नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अगर यह कांस्टीच्यूशन की बात है तो मैं गलती पर हूं इसी लिए मैंने पहले ही कहा है कि मुझे इसे एग्जामिन कर लेने दीजिए अगर कांस्टीच्यूशन में अलाउड है तो कल से हमारे यहां भी इजाजत हो जाएगी। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, आपकी दृष्टि से शायद वह गुजरा न हो, अगर गुजरा है तो इसका क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : आपका यह कॉलिंग अटैंशन मोशन आज ही प्राप्त हुआ है and that is under consideration.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा रोडवेज बस में हुए बम विस्फोट के बारे में मेरा एक और कॉलिंग अटैंशन मोशन है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में एक बस में बम विस्फोट हुआ था और जिस बस में हुआ था, वह हरियाणा प्रदेश की है। आज यह मामला अखबारों में काफी हाईलाईट हुआ है और टैलीविज़न पर भी जोर शोर से आया है। "जी" टी०वी० पर भी रात के 10 बजे के खबरों में यह मामला आया है और इस बात की तरफ ध्यान दिलाया गया है कि दिल्ली में अपराधों के बढ़ने की वजह दिल्ली के पड़ौसी राज्यों से आने वाले अपराधी हैं और उस में खासतौर पर हरियाणा प्रदेश का जिक्र किया गया है जिसमें यह भी कहा गया है कि चौधरी बंसी लाल द्वारा हरियाणा में शराब बन्दी खोलने के कारण ये अपराधी दिल्ली में आ गए हैं और यहां पर अपराध कर रहे हैं। यह रात 10.00 बजे जी०टी०वी० पर आया है। यह दिल्ली के करनैल सिंह, डी०सी०पी० क्राईम ब्रांच तथा प्रभोद कारन्थ, डी०जी०पी० की तरफ से यह कहा गया है। अध्यक्ष महोदय, यह आज के अखबार में भी छपा है, यह एक गम्भीर मामला है। आज के अखबार में यह खबर छपी है कि हरियाणा प्रदेश से आए अपराधियों की वजह से अपराध बढ़े हैं यह खबर दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई है। एक कांस्टेबल पर कातिलाना हमला हुआ वह बाल-बाल बच गया। यह खबर आज के पंजाब केसरी में पेज नं०-12 कालम नं०-5 पर छपी है कि एक वाहन को रोकने का पुलिस ने प्रयास किया तो उस वाहन से चलाई गई गोली से पुलिस का सिपाही बाल-बाल बचा। अध्यक्ष महोदय, आज इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हरियाणा में हो रही हैं। विशेष रूप से जब दूसरी स्टेट से ऐसी बात कही जा रही हैं तो इसका मतलब यह है कि यह मामला गम्भीर है। अध्यक्ष महोदय, जब हम यहां पर इस बारे में बात कह रहे थे तब उसे माना नहीं जा रहा था लेकिन अब दिल्ली के डी०जी०पी० और डी०सी०पी० क्राईम ब्रान्च कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में शराबबन्दी खुलने के बाद बंसी लाल की सरकार की वजह से दिल्ली में अपराध बढ़े हैं और अपराधी यहां पर वारदातें बढ़ा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब दिल्ली की पुलिस वहां पर अपराधियों पर सख्ती करती है तो वे अपराधी हमारे हरियाणा में आकर अपराध करते हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी आपकी काल अटैंशन मोशन 1.00 बजे के बाद आई थी वह अन्डर कंसिडरेशन है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो घटनाएं होती हैं वह दिल्ली के क्रिमिनलज़ की वजह से होती हैं और वे वहां से हरियाणा में आकर के वारदातें करते हैं। उनके अलावा हरियाणा के भी कुछ क्रिमिनलज़ है जोकि वारदातें करते हैं और वे इन्हीं के आदमी हैं। वे कौन कौन हैं और क्या-क्या करते हैं मैं आगे उनके नाम भी बता दूंगा जब मैं जवाब दूंगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये चाहे जो भी कहते रहें लेकिन जी०टी०वी० पर 24 तारीख को रात 10.00 बजे खबर आई थी।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जी०टी०वी० भारत सरकार का या हरियाणा सरकार का गजट नोटिफिकेशन नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर गजट नोटिफिकेशन नहीं है तो सरकार उसके खिलाफ ऐक्शन ले।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने मुलजिमों के बारे में पता कर लिया है कि वे किस पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं। जींद में एक गिरोह पकड़ा गया है और हमने उसकी रिपोर्ट मंगवाई कि वे क्या हैं और कौन हैं। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी धर्मपाल उर्फ टिनी गांव धमसाल जिला जींद, मास्टर रघुबीर सिंह का छोटा भाई है। मास्टर रघुबीर सिंह जिला जींद में लोक दल का कार्यकर्त्ता है और श्री ओम प्रकाश चौटाला से उसकी अच्छी जान पहचान बताई जाती है और चौटाला साहब जब भी गांव धमसाना में जाते हैं तो वहां पर चाय पीते हैं। अध्यक्ष महोदय, उसने क्या-क्या किया है मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ। सतबीर उर्फ छब्बल सुपुत्र श्री कपूरा जाट गांव किसाना जिला कैथल, धर्मपाल उर्फ पप्पू सुपुत्र श्री राम स्वरूप गाँव सोढामाजरा, उचाना, दयानन्द सुपुत्र श्री नफे सिंह जाट गांव किसाना जिला कैथल, सुभाष सुपुत्र श्री राम स्वरूप गांव किसाना जिला कैथल, इन सबकी उम्र 26 से 28 साल के बीच में है। ये लोग कार, मोटर साईकलज की चोरी और डकैती आदि करते थे। चोरी की गई कारें और मोटर साईकलज आदि धर्मपाल सिंह उर्फ टिनी के घर ले जाकर खड़ी कर देते थे यानि कि जहां पर वे चाय पीते हैं वहां पर चोरी की हुई गाड़ियां खड़ी रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने जो वारदातें अब से पहले की तसलीम है उस बारे में बताता हूँ कि 13-6-98 को हसोला गांव में पैट्रोल पम्प लूटा, 27-6-98 को सफीदों के कारखाने से 5-6 हजार रुपये लूटे और कार भी छीन कर ले गए, 26-6-98 को जींद में मोटर साईकल छीनी, 30-7-98 को नरवाना पैट्रोल पम्प से 7000 रुपये छीने, 5-7-98 को असंध के तहसीलदार की गाड़ी और 10,000 रुपये छीने, 8-7-98 को सफीदों में एक पटवारी से दिन दिहाड़े 1 लाख 5 हजार रुपये छीने गए और अब इसके तहत चार डकैतियों को जिनका पता ऊपर दिया गया है गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया है। इसके अलावा और भी केसों के बारे में तफतीश हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इनको तो वारदातों के बारे में पहले ही पता होता है हमें तो बाद में पता लगता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यही बात मैंने अपनी बजट स्पीच में कही थी कि हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही है। अगर मुख्यमंत्री जी के नोटिस में ऐसा कोई भी अपराधी आता है और उसका चाहे किसी से भी सम्बन्ध हो उसके खिलाफ सरकार ऐक्शन ले और अगर उस अपराधी का मुझसे कोई सम्बन्ध है तो सरकार मेरे खिलाफ भी ऐक्शन ले। मुख्यमंत्री जी की यह एक आदत बन गई है कि वे सदन को गुमराह करते रहते हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने फैक्चुअल बात की है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई फैक्चुअल बात नहीं है। जो ये कह रहे हैं तो उसी बारे में हम भी कह रहे हैं कि अगर उस मुलजिम का किसी से कोई सम्बन्ध है तो उसके खिलाफ भी ऐक्शन लें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हाउस में गलत ब्यानी का तालुल्क है, उस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी परसों गाबा साहब ने एक प्रश्न किया था कि स्त्रियों के अश्लील विज्ञापन छपने की वजह से स्त्रियों का अपमान होता है तो उसके बारे में मुख्यमंत्री जी से उसको रुकवाने के लिए जानकारी मांगी गई थी और कल संसदीय कार्य मंत्री श्री अतर सिंह सैनी ने उत्तर दिया था कि ऐसा प्रतिबन्ध लगाने के कोई आदेश सरकार को केन्द्र से नहीं मिले। श्री बंसीलाल ने बताया कि दरअसल करनाल के किसी विजय अरोड़ा ने अश्लील विज्ञापनों के लिए केन्द्र को शिकायत पत्र भेजा और केन्द्र ने महज इस पत्र को

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]
हरियाणा व पंजाब की सरकारों को प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र से प्राप्त ज़िराक्स कॉपी साफ न होने के कारण उसे कल ठीक तरह से पढ़ा नहीं जा सका लेकिन बंसीलाल जी ने यह भी कहा कि वे स्वयं अश्लील विज्ञापनों के विरोधी हैं लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए कोई कानून नहीं है। अध्यक्ष महोदय, शायद बंसीलाल जी की निगाह में इस बारे में कानून गुजरा नहीं होगा। इस बारे में कानून क्लीयर है, जो इस प्रकार है—

"Prohibition to advertisement containing indecent representation of women :—No person shall publish or cause to publish or arrange to take part in publication or exhibition of any advertisement which contains indecent representation of women in any case."

फिर सैक्शन 4 में लिखा है —

"Prohibition of publication or sending by post of books, pamphlets etc. containing indeccnt representation of women :—No person shall....."

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कानून है और यह मुख्यमंत्री जी की नैगलीजैन्सी है कि उन्हें इस बारे में ज्ञान नहीं है। इन्होंने सदन को गुमराह किया है। अध्यक्ष महोदय, यह कानून मैं आपको दे रहा हूं आप स्वयं इसे देख लीजिए। यह कानून मेरे पास जो किताब है उसमें छपा है। यह सैंट्रल गवर्नमैंट का कानून है जिसको मैं पढ़कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी को सदन को गुमराह करने की आदत है। (विघ्न)

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, श्री ओमप्रकाश चौटाला जी ने एक तरीका बनाया हुआ है कि कोई भी ऐसी बात जिसका न सिर होता है और न पांव होता है, लेकर खड़े हो जाते हैं। सर, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, हरियाणा की जनता भी अच्छी तरह से जानती है और यह सदन भी अच्छी तरह से जानता है कि हरियाणा में अपराधों को बढ़ावा किससे मिला। किसी राजनैतिक षडयन्त्र के तहत अगर अपराधों की देखभाल की गयी तो वह चौटाला साहब के राजकाज में की गयी। इन्होंने ग्रीन ब्रिगेड की स्थापना स्वयं अपने कर-कमलों से की।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या यह प्वायंट ऑफ आर्डर है ? यह किस बात का प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो अखबार पढ़ा है जिसमें इन्होंने कहा है कि हरियाणा की वजह से ही दिल्ली में अपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये भी दिल्ली पुलिस ने ही माना है कि हरियाणा के अंदर पुलिस बहुत सख्ती से इन अपराधों को रोकने में लगी हुई है इसलिए ये अपराधी दाएं-बाएं अपराध कर रहे हैं। इनको तो हमारी सरकार की सराहना करनी चाहिए कि जिस अपराध की दुनिया की इन्होंने शुरूआत की थी उसको हम रोकने में लगे हुए हैं। इसके अलावा जहां तक अश्लील चित्रों की इन्होंने बात की, हरियाणा की जनता अच्छी तरह से जानती है कि जब इनका राज था तो हरियाणा भवन में एवं हरियाणा रैस्ट हाउसिज में इनके मंत्री एवं ए०एल०एज० * * * * * को ले जाया करते थे। (विघ्न)

* चेयर के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, एम०एल०एज० या मंत्री * * * * * ले जाया करते थे, इसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह अनपार्लियामैंटरी शब्द है इसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो मैंने बातें कही हैं वह अपनी तरफ से नहीं कही हैं। इनके राज में क्या हुआ करता था, उसको हरियाणा की जनता अच्छी तरह से जानती है। ये बातें उस समय हुआ करती थीं। हरियाणा भवन और हरियाणा रैस्ट हाउसिज के अंदर ऐसी ऐसी बातें आम हुआ करती थीं।

लोक सम्पर्क राज्य मंत्री (श्री अतर सिंह सैनी) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने जो बात कही उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ठीक है कि यह कानून है लेकिन यह केन्द्र का कानून है और यह कनकरैन्ट लिस्ट है। राज्य भी इस पर कानून बना सकता है, केन्द्र भी बना सकता है। हमारे हरियाणा में ऐसा कोई कानून नहीं है। हम इस कानून को पूरी तरह फौलो करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो वकील का लैटर था, वह हमें प्रस्तुत किया गया लेकिन हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। अगर हमें ऐसी कोई शिकायत मिलेगी तो हम उस पर पूरी तरह से कानूनी कार्यवाही करेंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ऑन ए प्वाइंट आफ आर्डर स्पीकर सर, कृषि मंत्री जी ने जो बात मैंने कही थी उसका जवाब नहीं दिया कि इनका वर्कर इस मामले में इन्वौल्व था जिस मामले का मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया है उसी मामले में उचाना विधानसभा क्षेत्र से एच०वी०पी का कैन्डीडेट था इसमें जगफूल सिंह ऐडवोकेट का लड़का शामिल है और वह मुलजिम के तौर पर अरैस्ट हुआ है। (विघ्न एवं शोर)

श्री बंसी लाल : वह ग्रीन ब्रिगेड वालों के साथ ही चले गए थे। (शोर एवं विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ग्रीन ब्रिगेड का नेता जिसको लेकर चर्चाएं चलती हैं उनके साथ दलाल साहब की माला डालते हुए तसवीर छपी हुई है इन सब ने मालाएं डाली हुई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बंसी लाल : वह जहां से आया था वहीं इनके पास भेज दिया। (शोर एवं विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हम ऐसे माल के खरीदार नहीं हैं। गिरा वहीं पे खाद जहां का खमीर था। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बार-बार इस सदन को गुमराह करते रहे हैं। अगर हम उस चीज को आगे लाने की कोशिश करें तो अध्यक्ष महोदय, आप हमें मौका नहीं देते हैं। एक विषय जिसकी चर्चा मैं विशेष रूप से करना चाहता था वह कोर्ट की अवमानना का केस था। पांच जजिज की बैंच मुकर्रर हुई थी और उस जजिज की बैंच ने किसी के अगेंस्ट सुओ-मोटो कंटेम्प्ट किया था तो वह बंसी लाल के खिलाफ किया था। यूनैनिमसली पांच जजिज ने फैसला दिया था कि चौधरी बंसी लाल को मुलजिम करार दिया जाए। उस फैसले में बंसी लाल और इनके वकील को गिलटी करार दिया गया। (शोर एवं विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट ऑफ आर्डर पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका क्या प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट आफ आर्डर पर यह कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी सदन को बार-बार गुमराह करते हैं।

Mr. Speaker : Please take your seat.

---

* चेयर के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री बंसी लाल : मेरे और श्री एच०आर० भारद्वाज के खिलाफ पांच जजों की बैंच में कंटम्प्ट का मुकदमा चला और हाईकोर्ट के तीन जजों के बहुमत से हम दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये श्रीमान जी ओम प्रकाश चौटाला जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, इन पर घड़ियों की चोरी का मुकदमा चला और एक हजार रुपये जुर्माना हुआ था। ये सब बातें इस सदन में खुलकर आ चुकी हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कोर्ट के फैसले की कापी दे रहा हूं जिसमें स्पष्ट लिखा है कि पांच जजों की बैंच के फैसले ने चौधरी बंसी लाल जी और इनके वकील श्री एच०आर० भारद्वाज को गिल्टी करार दिया था इन्होंने माफी मांगी तब उन पांच जजों में से दो जजों, श्री संधवालिया और श्री पी०सी० जैन ने इनको कहा कि माफी का कोई लॉ नहीं है और फिर भी ये इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। परन्तु तीन जजों ने इनको माफी दे दी थी। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिस तरीके से अभी इस सदन में बात उठाई है उसका जवाब हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है और वह जवाब सही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री चौटाला जी से पूछना चाहूंगा कि इनकी निगाहें जो हमारे प्रदेश में न्यायाधीश और जो आयोग गठित होते हैं उनके खिलाफ क्यों हैं ? सैकिया आयोग ने महम काण्ड के बारे में जांच की और श्री अमीर सिंह की जिस तरीके से निर्मम हत्या की थी उसके बारे में यह कहा गया कि श्री ओम प्रकाश चौटाला के आदमियों ने 16-17 मई, 1990 की रात को हरियाणा विधान सभा के उप चुनाव के उम्मीदवार श्री अमीर सिंह की हत्या की। अध्यक्ष महोदय, जैसा इनका अपना इतिहास है वैसी बातें ही ये दूसरों के बारे में कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को बने हुये सवा दो साल हुये हैं इस दौरान इस प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है तथा अपराध को रोकने के लिए कोशिश की गई है। सरकार की तरफ से किसी अपराधी को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। हमने पूरे कायदे कानूनों को लागू करने की पूरी कोशिश की है फिर भी हम चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी से कहते हैं कि प्रदेश की भलाई के लिए अगर ये अच्छे सुझाव दे सकते हैं तो दें हम उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि जब चौधरी बंसीलाल जी विपक्ष में होते थे तो सरकार को कई अच्छे सुझाव भी दिया करते थे।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन अजय सिंह जी, बोलिये (विघ्न)

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे से संबंधित बात कही गई है, मैं उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कटाक्ष से न बोलें।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह सब मेरे ऊपर ही लागू है कि ऐसे न करूं यह जिम्मेवारी तो सभी सदस्यों की होनी चाहिये। सैकिया आयोग की बात सदन में पहले भी आ चुकी है। मैं सरकार को पुनः चुनौती देता हूं कि मेरे खिलाफ मुकदमा चलाये। मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने इंक्वायरी करने के लिए बिना किसी डिमाण्ड के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जजों को डैप्यूट किया था तथा महम कांड की इंक्वायरी जस्टिस ग्रेवाल ने की थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की थी। फिर भी मुख्यमंत्री जी इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। 5 जजों के बैंच ने मुख्यमंत्री और उन के वकील हंस राज भारद्वाज को गिल्टी करार दिया है। मैं उस फैसले की कॉपी सदन में पेश करता हूं। अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगर यह बात सही साबित हो जाए तो मुख्यमंत्री

जी इस्तीफा दे दें। (शोर) अध्यक्ष महोदय, यह हाई कोर्ट की अवमानना का मामला है। (शोर एवं व्यवधान) क्या मुझे अपनी बात कहने का अधिकार भी नहीं है ? (शोर)

श्री अध्यक्ष : अब मेरी कैप्टन अजय सिंह से प्रार्थना है कि वे बोलें। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात अधूरी रह गई है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आपकी बात पूरी होने वाली नहीं है। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाते जाएं * * * * * *

श्री अध्यक्ष : जो श्री ओम प्रकाश चौटाला बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, दक्षिणी हरियाणा में कोई भी मैडिकल कॉलेज नहीं है। इस बारे में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 22-7-98 को सदन में प्रस्तुत किया था, जिसके लिए आपने 48 घण्टे का समय दिया था। लेकिन आपकी सरकार ने अब तक इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी के अन्दर एक पोस्टग्रेजुट रीजनल सैंटर है, इस इंस्टीच्यूट के लिए बहुत पैसा खर्च किया जा चुका है और अब दीवारें भी वहां पर गिरने लग गई हैं। इसलिए मेरा शिक्षा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से अनुरोध है कि वे इसके बारे में जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आपकी यह कालिंग अटैंशन मोशन डिसअलाऊ हो चुकी है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नकली पैस्टिसाईड्ज की वजह से किसानों द्वारा आत्महत्या करने के बारे में था। इसके लिए आपने 48 घण्टे का समय दिया था लेकिन इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आपकी यह कालिंग अटैंशन मोशन भी डिसअलाऊ हो चुकी है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या सब कुछ ही डिसअलाऊ हो गया है ? अध्यक्ष महोदय, मेरी एक सबमिशन है कि चण्डीगढ़ में जो एम०एल०ए० अपनी गाड़ी पर रैड-लाईट लगा कर चलता है, यू०टी० वाले उस का चालान कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन को बाकायदा कोई हिदायतें अथवा गाईडलाईज़ दी जाएं ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

Mr. Speaker : Zero hour is over.

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now a minister will lay the papers on the Table of the House.

Minister of State for Public Relation (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to lay on the Table—

The 23rd Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year 1996-97 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[Shri Attar Singh Saini]

The Haryana Legal Services Authority (Transaction of Business and other Provisions) Regulations, 1998 as required under Section 30(2) of the Legal Services Authorities Act, 1987.

The High Court Legal Services Committee Regulations, 1998 as required under Section 30(2) of the Legal Services Authorities Act, 1987.

The Annual Statement of Accounts of the Housing Board, Haryana for the year 1992-93 as required under Sub-Section (3) of Section 19-A of the Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Audit Report of Haryana Financial Corporation for the year 1995-96 as required under Section 37(7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

वर्ष 1998-99 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वैसे तो हम ने सभी सदस्यों को बजट पर बोलने के लिए समय देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी यदि किसी माननीय सदस्य, चाहे वह विपक्ष में हो अथवा सत्तापक्ष में हो उसको यदि बजट पर बोलने के लिए समय नहीं मिला है तो वह डिमांड्ज़ अथवा एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल सकता है। मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हर सदस्य को बोलने के लिए 10 मिनट का समय अवश्य मिलेगा चाहे सदन की कार्यवाही कितनी देर तक चलानी पड़े।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से तो आप पाबंदी लगा रहे हो, बोलने के लिए समय देने की बात नहीं कर रहे हो। 10 मिनट में कोई सदस्य क्या बोल पाएगा ? हो सकता है कोई आधा घंटा भी बोलेगा। इस प्रकार से तो वे सदस्य भी डिमांड्ज़ पर बोलने से रह जाएंगे जिन को अभी तक बजट पर बोलने के लिए समय ही नहीं मिला है। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, इनकी तो हर बात में अपना विरोध प्रकट करने की आदत सी बन गई है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैं चौटाला साहब और दूसरे माननीय सदस्यों की इन्फर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि अब तक बजट पर 11 घण्टे 4 मिनट डिसकशन हो चुकी है जिसमें से हरियाणा लोक दल ने 260 मिनट, इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी ने 188 मिनट, हरियाणा विकास पार्टी ने 128 मिनट, बी०जे०पी० ने 20 मिनट और इंडीपैण्डेण्ट ने 60 मिनट लिए। क्या आप समझते हैं कि यह समय बजट पर डिसकशन के लिए कम रह गया ?

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने डिमाण्ड पर बोलने के लिए जो समय निश्चित किया है उसको निश्चित न करें। अगर कोई साथी डिमाण्ड पर लम्बी चर्चा करना चाहता है तो उसको अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : यह मैंने उन माननीय सदस्यों के लिए कहा है कि जिन को बजट पर बोलने के लिए समय नहीं मिल सका। हर सदस्य को समय जरूर मिलेगा।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी जो टाईम बताया है उसमें बजट पढ़ते समय वित्त मंत्री ने जितना टाइम लिया है क्या वह समय भी उसमें शामिल है।

श्री अध्यक्ष : वह समय इसमें शामिल नहीं है, वह अलग है।

श्री सम्पत सिंह : वह समय भी इसमें शामिल होना चाहिए।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन में हमारे वित मंत्री लाला चरणदास शोरेवाला ने एक बड़ा विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत किया। पिछले वर्ष इस बजट में जो 1997-1998 की योजना थी वह 1400 करोड़ रुपए की थी लेकिन इस वर्ष यह योजना 61 प्रतिशत बढ़ाकर 2260 करोड़ रुपये की है। इस योजना में किसी तरह का कोई नया कर नहीं लगाया गया और हरियाणा के किसी तबके पर कोई टैक्स नहीं है। इस बजट पर लगभग 24 साथी बोले हैं। 17 साथी लोकदल एवं कांग्रेस की तरफ से बोले हैं उनमें से कुछ साथियों ने अच्छे-अच्छे सुझाव भी दिए हैं और कुछ साथियों ने बजट की आलोचना के लिए आलोचना भी की। स्पीकर सर, इस बजट स्पीच पर चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी, बहन करतार देवी, बलवन्त सिंह मायना, चौ० धीरपाल सिंह जी, खुर्शीद अहमद जी, चौ० बीरेन्द्र सिंह जी और रामपाल माजरा बोले। लगभग सारे साथियों ने एक सबसे बड़ी बात कही कि इस सरकार ने शराबबन्दी सदन से पूछकर हरियाणा में लागू की और सदन से बिना पूछे शराबबन्दी उठा ली। स्पीकर सर, इस सदन की कार्यवाही आपके साये में चलती है, आपके सामने आपकी चश्मदीद गवाही में चलती है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, शराबबन्दी हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा के घोषणा पत्र के हिसाब से की गई थी। जब हम हरियाणा की जनता के सामने गांव की चौपाल में बोलते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबन्दी लागू करेंगे, उस समय चौपाल में जितनी महिलाएं और बुजुर्ग बैठे होते थे हमारी इस बात के ऊपर अपनी करतल ध्वनि से हमारा समर्थन करते थे। बंसीलाल जी की सरकार ने 11 मई 1996 को शपथ ली और उसी दिन एलान कर दिया कि पहली जुलाई के बाद शराब नहीं बिकेगी। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि हमारी सरकार द्वारा पूरे हरियाणा में सख्ती से शराबबन्दी लागू की गई। पार्टियों के घोषणा पत्र के हिसाब से हमने हरियाणा में शराब बंदी लागू की थी। प्रजातंत्र में सरकारें जनादेश से चलती हैं। लोक सभा के चुनाव से पहले इसी महान सदन में कांग्रेस के चौधरी भजन लाल जी बोला करते थे कि हरियाणा में शराब बिकती है 12 आदमी भिवानी में मरे। जो उन्होंने भिवानी में 12 आदमियों के मरने की बात कही आपने देखा होगा कि उन्होंने इस बात के लिए किस तरह से अपनी जान छुड़वाई थी। विरोधी पक्ष के भाईयों की तरफ से यह भी कहा गया कि हम शराबबंदी का रचनात्मक समर्थन करना चाहते हैं लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, कांग्रेस पार्टी और लोक दल पार्टी के लोगों ने लोक सभा चुनावों के दौरान कई स्थानों पर यह कहा कि यदि हमारी सरकार आई तो हम हरियाणा में शराब खोल देंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके अलावा चुनावों के दौरान एक बात यह भी कही गई कि सरकार ने शराब बंद करके हरियाणा की जनता पर नए टैक्सों का बोझ बढ़ा दिया। यह बात भी सही है कि शराब बंदी लागू करने से हरियाणा प्रदेश को साढ़े सात सौ करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ। परन्तु 310 करोड़ रुपए के नए टैक्स लगाने के लिए पिछली सरकार के पहले से ही प्रस्तावित थे। शराब बंदी लागू करने के कारण हमने हरियाणा की जनता पर, किसी व्यापारी पर, किसी किसान पर किसी तरह का कोई नये टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाया। बहन करतार देवी ने अपनी स्पीच

[श्री रामबिलास शर्मा]

की शुरूआत में यह कहा कि हम शराब बंदी को रचनात्मक समर्थन देना चाहते थे। डिप्टी स्पीकर साहब, विधान के अन्दर और बाहर कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो प्रदेश के हित में होते हैं, जो देश के हित में होते हैं, जो जनता के हित में होते हैं उनका समर्थन करना कोई बुरी बात नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, सम्पत सिंह जी हाउस में बैठे हैं जब चौधरी भजन लाल जी मुख्य मंत्री हुआ करते थे तो हमने उनसे एक बात कही थी कि चलो हम एस०वाई०एल० नहर के बारे में आपके साथ प्रधान मंत्री के पास चलते हैं और उनको सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके दे देते हैं। उस समय चौधरी बंसी लाल जी विपक्ष में थे हम सब ने उनके साथ मिल कर प्रधान मंत्री जी से मिलने की बात कही और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव प्रधान मंत्री जी को देने की बात कही तो उन्होंने हमारी उस बात को स्वीकार नहीं किया। डिप्टी स्पीकर साहब, हमने शराब जनादेश के कारण खोली है। डिप्टी स्पीकर साहब, कल दिल्ली बस अड्डे पर एक घटना हुई है और वह घटना हरियाणा रोडवेज की बस में हुई है। वह बहुत दुखद घटना हुई है पूरे प्रदेश को उसकी चिन्ता है। भारत के गृह मंत्री ने उस घटना पर चिन्ता व्यक्त की है। बस में विस्फोट के कारण जो लोग घायल हो गए थे उनको हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होस्पीटल में मिल कर आए। डिप्टी स्पीकर साहब, दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं, और बाकी दूसरी जगहों पर भी अपराध बढ़ रहे हैं। हरियाणा में भी अपराधों की घटनाएं बढ़ रही हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि चण्डीगढ़ के हालात 7-8 साल तक बहुत खराब रहे। चण्डीगढ़ में लोग दिन छिपने के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। उस समय चण्डीगढ़ में दिन छिपने के बाद कर्फ्यू जैसा माहौल होता था लेकिन आज सुखना झील पर शाम को लगभग 10 हजार लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानीपत में घटना हुई, डबवाली में घटना हुई वहां पर 20-20 और 28-28 आदमी मरे। कुछ लोग सीमा से बाहर जा कर इस तरह की घटनाएं करने का प्रशिक्षण ले कर आते हैं। जो ए०के० 47 है वह चीन के रास्ते अमरीका से आती थी। इस दुनिया में इस देश की दुश्मन बाहरी ताकतें भी हैं। इसके अलावा इस देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश को ऊपर उठता नहीं देखना चाहते। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हिन्दुस्तान के मजदूर, रिक्शा वाले, किसान, हाली, पाली, व्यापारी और कर्मचारी जिस दिन 11 मई और 13 मई को पोखरन में विस्फोट किया सब खुशी से अपने अपने स्थान पर नाचे थे और सब ने यह महसूस किया कि इससे भारतवासियों का दूसरे देशों में सम्मान बढ़ा है। जो दूसरे देशों में भारतीय मूल के लोग रहते हैं उन्होंने हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी को उसके लिए बधाई संदेश भेजे हैं। जब मैंने पोखरन विस्फोट के बारे में सदन में चर्चा की तो आपने देखा होगा कि कुछ साथियों को मेरी बात अच्छी नहीं लगी उनको मेरी वह बात पसंद नहीं आई। आप आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, इस देश की जनता और खास करके हरियाणा की जनता हमारी राजनीतिक दृष्टि को हमारे चेहरे की लकीर से पढ़ लेती है और यहां के लोग चलते हुए आदमी के कदम की दिशा से उसके मन की बात जान लेते हैं। पोखरन में अणु विस्फोट की घटना के बाद उसकी आलोचना से हिन्दुस्तान का स्वाभिमान बढ़ा है लेकिन कुछ लोग उस घटना को राजनीति के चश्मे से देखना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, वाजपेयी जी वह आदमी हैं जिसने पूरी जिन्दगी विपक्ष में रहकर काटी है, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। जब बंगलादेश में हिन्दुस्तान की फौजें बंगला देश को आजाद करवाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थीं उस समय इन्दिरा जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिनका उस वक्त अल्सर का आपरेशन हुआ था, जज्बातों, अरमानों से ऊपर उठ कर और अपनी देशभक्ति की भावना से भरकर कहा था कि इस समय हिन्दुस्तान में कोई राजनीतिक दल नहीं है, सब एक दल हैं और उसकी नेता इन्दिरा गांधी है। उन्होंने कहा था कि इस समय हम सब लोग पंचाधिका स्तंभ हैं। जब हम अपने देश में राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे तो वह 100 कौरव और

पांच पांडव दो विभागों में लड़ेंगे। लेकिन अब देश की चारदीवारी के बाहर की लड़ाई में हम सब पंचाधिका स्तंभ हैं। यह जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई है यह हम इन्दिरा जी की रहनुमाई में लड़ेंगे। वाजपेयी जी की गाजियाबाद की बी०जे०पी० की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में इस बात को लेकर आलोचना भी हुई थी। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति वैंकटरमन जी ने एक पत्र प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को लिखा है कि आपने पोखरन में जो अणु विस्फोट करने का काम किया है उससे हिन्दुस्तान के इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। उन्होंने पत्र में आगे लिखा है कि 1984 में जब मैं इन्दिरा गांधी जी की सरकार में रक्षा मंत्री था तो उस समय मैं उस जगह पर गया था, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय जगत को इस बात का पता लग गया। डिप्टी स्पीकर साहब, 63 वैज्ञानिक संस्थानों में भारत मूल के जो वैज्ञानिक थे उनको अमेरिका ने काली लिस्ट में डालकर निकाल दिया। यह कोई छोटी घटना नहीं है। यह इस बात का खामियाजा उन देशभक्त वैज्ञानिकों को भुगतना पड़ा क्योंकि उन्होंने इस घटना की जानकारी किसी भी कीमत पर दूसरे किसी आदमी को नहीं दी। मैं उन वैज्ञानिकों का इस बात के लिए अभिनन्दन करना चाहता हूं, उन वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। परन्तु इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बिजली का उत्पादन बढ़ाने की रही है। पिछले 15-16 सालों में एक यूनिट बिजली भी किसी माई के लाल ने नहीं बढ़ाई। आज हरियाणा में सभी को जिन्दा रहने के लिए सुबह-शाम, खेत, घर व चक्की तथा दूसरे कामों के लिए बिजली चाहिए। इन सारी आवश्यकताओं को देखते हुए बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। बिजली का उत्पादन बढ़ाना एक बड़ा अहम काम है। हमारे साथी इस बजट पर बोले हैं। (विघ्न) मैं भी बजट पर बोल रहा हूं। सरकार की उपलब्धियों पर बोल रहा हूं। इस बजट के आंकड़ों पर बोल रहा हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, श्री चौटाला जी ने बोलते हुए कहा कि 2400 करोड़ रुपया सरकार ने बिजली बोर्ड के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लिया, इसकी जरूरत नहीं थी। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की जितनी भी स्टेटों की सरकारें हैं, वे कर्ज लेती हैं। महाराष्ट्र ने अपने यहां बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए लोन लिया। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक से जितनी तत्परता से हरियाणा बिजली बोर्ड को कर्ज मिला है इतनी जल्दी वर्ल्ड बैंक से हिन्दुस्तान की किसी भी सरकार को आज तक कोई कर्जा नहीं मिला है। इस बात के लिए मैं अपने बिजली बोर्ड के समस्त अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सही केस तैयार किया जिस कारण हमारे मुख्यमंत्री जी की कोशिश से हम वर्ल्ड बैंक से यह ऋण इतने कम समय में लेने में कामयाब रहे। बिजली बोर्ड ने यह ऋण बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए लिया है। पिछली सरकारों ने इस काम के लिए कुछ टैण्डर इन्वायट किए थे। हमने सोचा कि पिछली सरकार के समय जो दरख्वास्तें आई उनमें सब को अवसर नहीं दिया गया था जबकि सबको अवसर दिया जाना चाहिए था। हम कुछ लोगों को कानूनी तौर पर अवसर नहीं दे सकते थे। हमने अपने देश की बी०एच०इ०एल० कम्पनी से भी बात की क्योंकि इस कम्पनी ने बाहर के कई देशों में काम किया है। हमने उनको एक नहीं दो नहीं तीसरी बार भी अवसर दिया। परन्तु फिर भी वे नहीं आये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने श्री मनीराम गोदारा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसमें 5-7 मिनिस्टर थे। उनमें से मैं भी एक था। चाहे टैण्डर काल किये या नहीं किये, अपने देश की कम्पनी को जिनका बिजली जनरेशन में काफी अच्छा काम रहा है और कई देशों में जिन्होंने काम किया है उनको चौथी बार अवसर दिया। फिर उनके मैनेजिंग डायरैक्टर आये। वे कहने लगे कि हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको अवसर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास कोई बैंकर नहीं हैं, कोई आर्थिक स्पोंसरशिप नहीं है, इसलिए हम अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस समय का जिक्र करना चाहता हूं जब फरीदाबाद

[श्री रामबिलास शर्मा]

फरीदाबाद में प्रधान मंत्री इन्द्र कुमार गुजराल जी गैस पर आधारित 430 मैगावाट के संयन्त्र का उद्घाटन करने आये। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपनी जुबान से कहा कि 430 मैगावाट का गैस पर आधारित भारत का यह पहला संयन्त्र है और इस संयन्त्र को हम हरियाणा में शुरू करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, श्री इन्द्र कुमार गुजराल जी ने कहा कि जिस दिन से मैंने शपथ ग्रहण की है उस दिन से हरियाणा की सरकार संयन्त्र लगाने के लिए लगातार मेरे पीछे पड़ी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, इस काम के लिए हरियाणा के मुख्य मंत्री चौ० बंसी लाल जी बधाई के पात्र हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस संयन्त्र से जितनी भी बिजली का उत्पादन होगा वह सारी की सारी बिजली हरियाणा प्रान्त पर खर्च की जायेगी किसी दूसरे प्रान्त को उसमें से बिजली नहीं मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने खुद घोषणा की कि इस प्रोजैक्ट से जितनी भी बिजली उत्पन्न होगी उस पर केवल हरियाणा का अधिकार होगा। उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि हम महंगी बिजली दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम 50 पैसे यूनिट बिजली हरियाणा के किसानों को दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने स्लैब सिस्टम प्रारम्भ किया है जिससे दक्षिणी हरियाणा, अंबाला और नारायणगढ़ के इलाकों में जहां पानी 200, 250 और 300 फुट से नीचे है वहां के किसानों को बहुत राहत मिली है। उपाध्यक्ष महोदय, चौटाला जी ने कहा है कि हरियाणा में 8 बार बिजली के दाम बढ़े हैं,ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में बिजली के दाम सिर्फ दो बार बढ़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब केन्द्रीय सरकार पैट्रोल, डीजल आदि के दाम बढ़ाती है तब इन चीजों के दामों पर भी असर पड़ता ही है। हरियाणा सरकार ने सिर्फ दो बार बिजली के दाम बढ़ाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन किसानों को जो बिजली दी जाती है उसके दाम नहीं बढ़ाये गए हैं, उस गरीब आदमी के बिजली के दाम नहीं बढ़ाये जो 40 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करता है, जिसके घर में दो लट्टू और एक पंखा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे हिंदुस्तान में बिजली की सबसे अच्छी सप्लाई मुम्बई की मानी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मुम्बई में बिजली की सप्लाई टाटा फर्म द्वारा की जाती है, वहां पर डोमैस्टिक बिजली 4 रु०5 पैसे या 4 रु० 6 पैसे प्रति-यूनिट दी जाती है जबकि हमारे यहां 3 रु० 5 पैसे प्रति-यूनिट डोमैस्टिक और किसानों को 50 पैसे प्रति-यूनिट बिजली दी जाती है। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से बिजली के डोमैस्टिक और कामर्शियल रेट जानना चाहता हूं, क्या वे दोबारा से इन रेट्स को बताने की तकलीफ करेंगे ? (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जो डोमैस्टिक रेट हैं वे दो तरह के हैं एक तो उन गरीब आदमियों के लिए जिनके घर में दो लट्टू और एक पंखा है और दूसरे उनके लिए जो बिजली बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। (विघ्न) हरियाणा प्रदेश में 6 लाख ऐसे लोग हैं जिनके घर में दो लट्टू और एक पंखा है, चाहे वे गांव के या शहर के रहने वाले हों। उनको हमने रियायती दरों पर बिजली दे रखी है और न ही उनकी बिजली के दाम बढ़ाये हैं। (विघ्न एवं शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब इन्होंने बिजली की एक प्रणाली बना रखी है फिर ये इसको गरीब और अमीर को अलग-अलग दामों में क्यों दे रहे हैं। इसको दो भागों में क्यों बांट रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त हमारी सरकार थी उस वक्त चार प्रणाली सिस्टम होता था, कांग्रेस ने इसको दो प्रणाली सिस्टम कर दिया और चौ० बंसी लाल की सरकार ने इसको एक प्रणाली सिस्टम कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जब एक प्रणाली सिस्टम कर दिया फिर इसमें गरीब और अमीर का सवाल क्यों है ?

श्री राम विलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से चौटाला साहब शायद स्लैब और प्रणाली को अलग-अलग समझ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, स्लैब सिस्टम पहले भी 4 स्लैब्ज़ में था और अब भी चार स्लैब्ज़ ही बनाए गए हैं। दो स्लैब डोमैस्टिक बिजली के हैं। उपाध्यक्ष महोदय, छः लाख कन्ज्यूमर्ज़ ऐसे हैं जिनको हमने बिजली की कन्ज़म्पशन के हिसाब से गरीबी की रेखा से नीचे माना है इस हिसाब से हमने दो स्लैब प्रणाली सिस्टम बनाया है। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि बिजली का डोमैस्टिक कन्ज़म्पशन का क्या रेट है और कमर्शियल कन्ज़मशन का क्या रेट है, इसें भी थोड़ा क्लीयर करें?

श्री राम विलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, 6 लाख कन्जयूमर्ज़ हमने एक प्रणाली में रखे हैं और हमारी सरकार बनने के बाद इनको दी जाने वाली बिजली के रेट में कोई बढ़ौतरी नहीं की गई है। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक बात कहना चाहता हूं। ये इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गरीब आदमी और किसान को उसी रेट पर बिजली देंगे। मन्त्री महोदय को पता होना चाहिए कि 757 करोड़ रुपये बिजली बोर्ड को सबसिडी के नाम पर अधिक देने वाले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसिडी की यह राशि कोई ऊपर से थोड़े ही आएगी। यह राशि भी तो किसानों और दूसरे लोगों की जेबों से ही आएगी।

श्री राम विलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि 40 यूनिट तक बिजली उसी रेट पर दी जाएगी।

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। वर्ल्ड बैंक से 240 करोड़ रुपये का लोन मिल गया है और 1000 करोड़ रुपये का दूसरा लोन वर्ल्ड बैंक से अभी और मिलना है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) वर्ल्ड बैंक ने लोन देने के लिए शर्त लगाई है कि 30 प्रतिशत बिजली के रेट्स आपको बढ़ाने होंगे। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार को वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाएगा तब क्या इस रेट पर बिजली दे पाना सम्भव रह पाएगा और क्या यह बात सत्य है कि इस प्रकार की शर्त लोन के लिए लगाई गई है ?

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की आशंका निराधार है। कोई शर्त हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए तय नहीं की है। बिजली के सुधारीकरण की बात है और उसको हमने प्रोसैस भी किया है। जिस गति से हमने काम आरम्भ किया है उससे बिजली का सुधारीकरण तेजी से होगा। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, स्लैब प्रणाली लागू करने के लिए मैं इसका स्वागत करता हूं। मन्त्री महोदय से मैं एक बात जानना चाहता हूं कि स्लैब प्रणाली 50 फुट गहराई तक के टयूब्वैल्ज़ के लिए हमारे टाईम में शुरू की गई थी। हमारे एरिया में ज्यादातर टयूबवैल्ज़ 75 और 80 फुट से ज्यादा गहराई पर लगे हुए हैं। दूसरे एरियाज में एक साल में 4-4 फसलें होती हैं लेकिन हमारे एरिया में साल में केवल एक ही फसल होती है और हम लोगों को उनके साथ इक्वेट कर दिया गया है। आबियाना 20 रुपये से शुरू होता है और दूसरे हमारे किसान केवल एक ही फसल पर निर्भर करते हैं और सिंचाई के लिए सिर्फ टयूबवैल्ज़ पर ही निर्भर हैं, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारी इस समस्या की ओर भी ध्यान दे।

मुख्य मन्त्री (चौधरी बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, हमने यह कर दिया है कि जो लोग स्लैब प्रणाली से बिजली लेना चाहेंगे उनको उस हिसाब से पैसा देना होगा और जो लोग मीटर लगवाना चाहते हैं उनको मीटर लगा कर देंगे। हमने मीटर्ज लगाने शुरू कर दिये हैं और काफी मीटर्ज लग भी चुके हैं। जहां तक 75 फुट या 80 फुट गहरे ट्यूबवैलज़ का ताल्लुक है, आज ट्यूबवैल कहीं पर भी 75 या 80 फुट से कम गहराई पर नहीं लगता है। कुरुक्षेत्र और करनाल में भी जो ट्यूबवैल्ज़ लगते हैं वह 75 या 80 फुट से कम गहराई पर नहीं लगते हैं।

16.00 बजे **श्री रामविलास शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब, की तो आदत ही उल्टी है जब प्रश्न काल का समय होता है तो ये डिबेट बना लेते हैं जब हम बजट का जवाब देते हैं तो ये उसे प्रश्न काल बना लेते हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि स्लैब सिस्टम जो चालू हुआ है उससे आहिरवाल और अम्बाला को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। कृष्ण लाल और चौटाला जी ने कम रेट के बारे में पूछा था। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 40 यूनिट बिजली की खपत तक 1.45 रुपए प्रति यूनिट रेट है यह रेट पहले था और पिछले दो साल से हमने भी इन रेटों में कोई बदलाव नहीं किया है। 40 यूनिट से ज्यादा पर 3.06 रुपए और इंडस्ट्री का 3.92 रुपए रेट है। मुम्बई में इन्डस्ट्री से 4.50 रुपए प्रति यूनिट और कर्नाटक में 4.00 रुपये प्रति यूनिट बिजली के रेट चार्ज किये जाते हैं। आज भी हरियाणा में किसानों को और 40 यूनिट से कम प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं को सबसे कम रेट पर बिजली दी जाती है। हमारे यहां पर टोटल उपभोक्ता 32 लाख हैं और दो लट्टू वाले डोमैस्टिक कंज्यूमर 6 लाख हैं। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : आप हमें टोटल कंज्यूमर्ज के बारे में बताएं कि वे कितने हैं।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वे 32 लाख के करीब हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे हरियाणा में बिजली के रेटों को बढ़ाने के बाद भी सबसे सस्ती दरों पर किसानों को बिजली मिलती है। आज बिजली का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए इस बारे में चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने किसाऊ डैम की बात कही। बीरेन्द्र सिंह जी, यह बहुत ही लम्बा प्रोजैक्ट है। फिर पन बिजली की बात कही गई। आज हरियाणा में खेती का और इन्डस्ट्री का भट्ठा बैठ रहा है, बिजली का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए इस बारे में सोचने की आवश्यकता थी। पिछले 16 सालों में कोई भी सरकार और कोई भी भाई का लाल इस मामले को अपने हाथों में नहीं ले सका। हमारी एच०बी०पी० और बी०जे०पी० की सरकार ने इस काम को अपने हाथ में लिया तो ये उसको क्रिटीसाईज़ कर रहे हैं। शराब बंदी के आठ सौ करोड़ रुपए के घाटे के बाद हमने इस सुधारीकरण के प्रोजैक्ट को अपने हाथों में लिया है और इससे हरियाणा में बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। यह जो प्रौजैक्ट हमने अपने हाथों में लिया है यह हिम्मत का काम था। जब यह काम हमने अपने हाथ में लिया था तब वर्ल्ड बैंक से कोई ग्रान्ट नहीं मिली थी। वहां से कोई ऋण मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बारे में कुछ पता नहीं था। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी भी बिजली और सिंचाई मंत्री रहे और उन्होंने उस वक्त सर्वेक्षण किया था अब ये उस बारे में यहां पर कह नहीं पाए। ये ही इस बारे में जाने कि क्यों नहीं कह पाए। श्री बलवीर सिंह जिनके कान टूटे हुए हैं मेहम वाले हैं उन्होंने बोलते हुए कहा कि इस सरकार ने पंचायतों से लेकर हरियाणा में बाढ़ रोकने तक अच्छा काम किया है और आज हरियाणा के टेल तक पानी पहुंच रहा है। बिजली के बारे में भी अच्छा काम किया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अब वे इससे डरते हुए इस बात की हां नहीं भर रहे हैं तो मैं क्या करूं। (विघ्न) स्पीकर सर, बहन करतार देवी ने शिक्षा जगत की भी चर्चा की और कहा कि रोहतक विश्वविद्यालय में संध्याकालीन कक्षाएं बंद कर दी गयी हैं। स्पीकर सर, उस विश्वविद्यालय में उस समय इन कक्षाओं में 128 छात्र थे

और चालीस प्राध्यापक थे। सायंकालीन कक्षाएं इसलिए लगायी जाती हैं कि जो लोग दिन में नौकरी या दूसरा रोजगार करते हैं, वे ये सुविधा बड़े नगरों में पाते हैं। स्पीकर सर, इन छात्रों में से पांच प्रतिशत ऐसे छात्र थे जो कहीं दूसरी जगह पर नौकरी वगैरह करते थे लेकिन बाकी सब लोग दिन में कक्षाएं अटैंड करते थे। सर, इसका बजट करीब 60 लाख का था। स्पीकर सर, मैं बलवन्त सिंह मायना जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी इस बात के लिए प्रशंसा की कि हमने सांपला में दीन बन्धु छोटू राम के नाम पर एक कालेज प्रारंभ किया। (विघ्न) सर, उधर के सारे लोगों को सम्पत सिंह ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि वे हमारी प्रशंसा नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोग हमारी प्रशंसा कर ही जाते हैं।

श्री बलवन्त सिंह : सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, जो संध्याकालीन कक्षाएं वहां रोहतक यूनिवर्सिटी में लगती थीं, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। इनको इस बारे में आश्वासन देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, संध्याकालीन कक्षाओं के जितने लैक्चरर्ज़ थे, वे अब ऑन रोड घूम रहे हैं। कल ही मेरे को एक लैक्चरर ने बताया कि सरकार ने मेरा वहां से ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर भी ऐसी जगह कर दिया जहां मेरा सब्जैक्ट नहीं है। वह कहने लगा कि अब आप ही बताएं कि मैं अब कहां जाऊं इसलिए मंत्री जी से मेरा यह कहना है कि वह इन संध्याकालीन कक्षाओं को वहां फिर से शुरू करवा दें।

श्री अध्यक्ष : मायना जी, संध्याकालीन कक्षाओं के लैक्चरर्ज़ का कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि वे तो यूनिवर्सिटी के इम्पलाईज हैं।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात दुरूस्त है लेकिन मुझे पता लगा कि वहां से 18 लैक्चरर्ज़ के ट्रांसफर की लिस्ट भेजी गयी है। मेरी अपनी जानकारी के अनुसार तो उन 18 लैक्चरर्ज़ का वहां से ट्रांसफर हो गया है। सर, इसका मतलब यह है कि वहां उनको सजा दी जा रही है।

श्री रामबिलास शर्मा : स्पीकर सर, इस बारे में माननीय विधायक को ठीक बात बतायी नहीं जा रही है। जैसा मैंने पहले बताया कि वहां पर चालीस प्राध्यापक काम करते थे। वहां पर प्राध्यापक की दो श्रेणियां होती हैं। सर, आप तो शिक्षा जगत के आदमी हैं इसलिए आप इस बारे में जानते हैं। सम्पत सिंह जी भी इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं लेकिन मायना साहब को थोड़ी मुश्किल होगी। स्पीकर सर, मैं बता रहा था कि दो तरह के प्राध्यापक वहां पर थे, एक तो यूनिवर्सिटी कैडर के थे और दूसरे स्टेट कैडर के थे। इन सबका हमने इस कालेज में समायोजन किया है और किसी का भी ट्रांसफर नहीं किया है। लेकिन अगर मायना साहब के पास किसी की स्पैसिफिक शिकायत है तो मुझे बता दें। जो विद्यार्थी संध्याकालीन कक्षाओं में आते थे उन सबको डे कालेज में ले लिया गया है। स्पीकर सर, रोहतक विश्वविद्यालय का वातावरण आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। इस सरकार के आने से पहले वहां पर एक प्राध्यापक की हत्या हुई थी। अब इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति सेना के रिटायर्ड जनरल कौशिक हैं। वे बड़ी मुस्तैदी से इस विश्वविद्यालय को देख रहे हैं। उनके आने के बाद वहां पर पढ़ाई की एक मिसाल बनी है। उन्होंने वहां के वातावरण को ठीक किया है। किसी भी छात्र को और प्राध्यापक को इन संध्याकालीन कक्षाओं के बंद करने से असुविधा नहीं हुई है। इन दो वर्षों में हमारे कुछ साथियों ने स्कूल का दर्जा बढ़ाने की मांग की थी और हमने पिछले दो वर्षों में 400 स्कूलों का दर्जा बढ़ाया है।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। माननीय शिक्षा मंत्री जी बड़े विद्वान हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही हैं। हमें प्रथा भी डालनी चाहिए कि हाउस के अंदर जो बात

[श्री बलवन्त सिंह]

सही है उसको सही कहा जाए। अच्छे काम को अच्छा ही कहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जो ऐड-हॉक के साढ़े छह हजार अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। 1993-94 में भी उनको पक्का किया गया था आज सरकार उनको वहां से हटाना चाहती है और जो रैगुलराइज टीचर्ज हैं उनको लेना चाहती है। मेरा सुझाव है कि जो ऐडहाक टीचर्ज हैं उनमें किसी की सिफारिश होती है, किसी की सिफारिश नहीं होती है, किसी ने बच्चे पालने हैं और किसी ने शादी करानी है। मेरा सुझाव है कि उनको तो कन्फर्म कर देना चाहिए। किसी को ऑन रोड रखना ठीक नहीं है। पहले भी सरकारें कन्फर्म करती रही हैं आपको भी इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय भायना साहब, जिन अध्यापकों की चर्चा कर रहे हैं, उनका मुकद्दमा हाईकोर्ट में जेरेगौर है When the matter is sub-judice, any commitment is illegal. इसलिए मैं इस महान सदन में कोई बात कहना नहीं चाहता परन्तु मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि दो वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा जगत में जो उपलब्धि हुई है इस बारे में आम अध्यापक भी महसूस करता है, यह अभिभावक महसूस करते हैं। अगर आप परीक्षा परिणामों को देखें तो आपको भी इस बारे में महसूस होगा। 1995 में दसवीं दो का 14.54 प्रतिशत रिजल्ट रहा था, 1998 में 54.45 प्रतिशत रिजल्ट है और हरियाणा में राजकीय विद्यालय, चरखी दादरी का दीपक कुमार 10+2 कक्षा में प्रथम आया है। दसवीं का रिजल्ट 1995 में 23.88 प्रतिशत था और 1998 में दसवीं का सरकारी विद्यालय का रिजल्ट 59.93 प्रतिशत है, इसमें पिछले साल से 19.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आठवीं का रिजल्ट 1995 में 23.03 प्रतिशत था और 1998 में यह 54.91 प्रतिशत रहा है। यह परिणाम दर्शाते हैं कि शिक्षा जगत में इन दो वर्षों में कितनी मेहनत हुई है। वर्ष 1995 में 2180 सीटें जे०बी०टी० के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित थीं, उन सीट्स को हमने बढ़ाकर साढ़े तीन हजार किया है। ओ०टी० के लिए हरियाणा में कुल 350 लड़के-लड़कियां प्रशिक्षण लेते थे, हमने यह संख्या भी बढ़ाकर 850 की है। इसके अलावा शिवालिक और मेवात के इलाके जहां के स्थानीय बच्चे जे०बी०टी० में नहीं आ पाते थे हमने उनको रिलैक्सेशन दी कि वे मैट्रिक करके सीधे जे०बी०टी० में आ सकेंगे। मोरनी और फिरोजपुर नमक में दो वर्षों में हमें जे०बी०टी० की काफी संख्या बढ़ाई है। इसके अलावा हरिजनों के बच्चों का बैकलॉग काफी समय से चला आ रहा था, उसको पूरा करने के लिए पिछले दो सालों में हमने दस हजार अध्यापक ऐडहॉक इत्यादि के मिलाकर मैरिट के आधार पर लगाए हैं। हमने घोषणा की थी कि कोई छात्र बगैर अध्यापक के नहीं रहेगा और कोई अध्यापक बगैर छात्र के नहीं रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप इन दो वर्षों में यह परीक्षा परिणाम उत्साहजनक दिखाई दिए। उसका कारण यह नीति थी कि हमने चाहे 89 डेज पर टीचर लगाए परन्तु हमने कक्षा को खाली नहीं रखा और इस बार शिक्षा के लिए इस वर्ष के बजट में 1408 करोड़ रुपये का प्रावधान योजनागत और गैर योजना गत तरीके से किया गया है। प्राथमिक शिक्षा के लिए 552.24 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा के लिए 529.57 करोड़ रुपये तथा उच्चतर शिक्षा के लिए 208.14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्पीकर सर, पहले हमारे यहां चार जिलों में प्राथमिक शिक्षा योजना थी परन्तु पिछले साल से महेन्द्रगढ़, भिवानी और गुड़गांव तीन जिलों में इसे और चालू किया गया है। हरिजनों के बच्चों और गाड़िया लुहार के बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो अपना घर बनाकर नहीं रहते उनके बच्चों को स्कूल में आने के लिए प्रतिदिन एक रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से दिया जाता है और जिसके कारण आज हरिजनों और गाड़िया लुहार के बच्चे काफी संख्या में स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जैसा कि मंत्री महोदय ने दर्शाया कि हम गाड़िया लुहार के बच्चों को प्रतिदिन प्रति बच्चे के हिसाब से एक रुपया देते हैं तो यह स्कीम कब शुरू की है ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार आई है तभी से यह योजना शुरू की है। पहले की सरकार जो कुछ करके गई थी वह हमारी सरकार भुगत रही है हमारी सरकार तो सभी चीजों को तुलनात्मक दृष्टि से चालू करती है वह किसी चीज को तहसनहस करने का काम नहीं करती। जब वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला था, उस समय प्रदेश का खजाना खाली था। यह तो वही बात हो गई कि नानी खसम करे और दोहता उसका दण्ड भुगते। जिस दिन सरकार ने शपथ ली उस समय बिजली बोर्ड में 3300 करोड़ रुपये का घाटा था तथा बिजली बोर्ड की क्रेडिब्लिटी ऐसी थी कि न तो वर्ल्ड बैंक और न ही एल०आई०सी० उसको कर्ज देने के लिए तैयार थे। वर्तमान सरकार ने बिजली बोर्ड की क्रेडेब्लिटी बनाई जिससे आज हरियाणा बिजली बोर्ड पूरे देश में सबसे बढ़िया बोर्ड है तथा बिजली उत्पादन में सबसे अग्रणी है।(विघ्न) श्री धर्मवीर गाबा जी ने गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की बात की कि इस यूनिवर्सिटी का अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है। हमने उस समय भी कहा था कि हम किसी चीज को समाप्त करने वाले नहीं है बल्कि हम तो चीजों को विस्तार देने वाले हैं। हमने उस यूनिवर्सिटी को बरकरार रखा उसको सहयोग दिया और उसी का परिणाम है कि आज वह यूनिवर्सिटी यू०जी०सी० से और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर रिकोग्नाइज हो गई है। उसमें पहले कुछ खामियां थी। पिछली सरकार ने कुरुक्षेत्र रिजनल इंजीनियरिंग कालेज को जिसकी क्लासिज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कैम्पस में लगती हैं उसको गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के साथ एफिलियेट कर दिया था और तीन साल तक बच्चों के परिणाम नहीं आए। आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र रिजनल इंजीनियरिंग कालेज की क्रेडिब्लिटी सारे देश में है। जो कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैम्पस में था, उसकी एफीलिएशन अब फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ कर दी है। इसी तरह से कुछ कॉलेज रोहतक यूनिवर्सिटी को दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है, उसको कैम्ब्रिज और कैलीफोर्निया यूनिवर्सिटीज की तरह से ही बढ़ाना है। इसको एक रैजिडैंशियल यूनिवर्सिटी बनाया है और इसका रूतबा और भी बढ़ाना है। इसलिए इस बात की इन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैप्टन अजय सिंह जी ने कहा कि राज्यसभा के लिए जो दो सदस्य चुने गए हैं, उन में से एक बी०जे०पी० का है और दूसरा विरोधी पक्ष का बी०जे०पी० का सपोर्टिड है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, कैप्टन अजय सिंह, राव अभय सिंह जी के सुपुत्र हैं और राव साहब भारतीय जनसंघ के प्रांत उपाध्यक्ष रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय,एक कहावत भी है कि ''मां पर पूत, पिता पर घोड़ा, बना नहीं तो थोड़ा-थोड़ा''। कैप्टन साहब ने यूनिवर्सिटी का रीजनल सैंटर भीरपुर में खोलने की बात कही। इन से मेरी इस बारे में व्यक्तिगत तौर पर बात भी हुई है और इस बारे में इनकी तरफ से सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आया था। मैं इन को बताना चाहता हूं कि इस के लिए सरकार ने पैसे का प्रावधान किया है और जो इन की शंका है कि उस को भी गुरू जम्भेशवर यूनिवर्सिटी की तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन की पार्टी के शासनकाल में जब मैं कहता था कि अहीरवाल का इलाका तो हमारे इलाके से मिलता है इसलिए नारनौल, महेन्द्रगढ़ रिवाड़ी को पानी दिया जाए तब कैप्टन साहब मेरे समर्थन में बोलते नहीं थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ये पांच साल मंत्री रह चुके हैं और अपने खेत में पानी तक नहीं लगवा सके जबकि नहर इनके बराबर से जा रही है।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, गावा साहब ने एस०सी०ई०आर०टी० की रिपोर्ट की बात कही। मैं बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ हरियाणा के संबंध में ही नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया कौंसिल ऑफ एस०सी०ई०आर०टी० ने एक बार एग्जामिन किया और पाया कि गुड़गांव में स्थित एस०सी०ई०आर०टी० सही ढंग से काम करता है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जे०बी०टी० व ओ०टी० वगैरह के दाखिले पूर्ण रूप से कंप्यूटराईज्ड होते हैं तथा कहीं से भी हेराफेरी की एक शिकायत भी नहीं आती है। अगर कोई पूछने आता है तो हम फलॉपी निकालकर के दिखा देते हैं कि यह रही आपकी उत्तर-पुस्तिका और इतने आपके नम्बर आए हैं। पिछले साल 40 हजार छात्र-छात्राओं ने एंट्रेस टैस्ट दिया था तथा जितने भी दाखिले किए गए वे मैरिट के आधार पर ही किए गए। इस प्रकार यह जो रिकार्ड होता है, उस को हम 3 साल तक रखते हैं।

श्री धर्मवीर गावा : अध्यक्ष महोदय, मेरी रिक्वैस्ट तो यह थी कि प्राईवेट स्कूलों में एजुकेशन का स्तर गिर रहा है। क्या इस को सुधारने के लिए भी कोई गाईडलाईज दी गई हैं ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जो डी०पी०ई०पी० की योजना है, पहले यह प्रदेश के 4 जिलों में होती थी। मौजूदा सरकार ने इस को 3 और जिलों में लागू करने का प्रस्ताव दिया है। उसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए भी सिफारिश की गई है। भाई रमेश खटक जी ने कह दिया कि इस सरकार ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। (विघ्न)

श्री रमेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने बिजली और बेरोजगारों को नौकरी देने के वायदे की बात कही थी।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगले 6 महीने में हरियाणा के सभी निवासियों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। (शोर)

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्वाईंट ऑफ आर्डर। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 6 महीने में 24 घंटे बिजली मिलेगी और पहले मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि डेढ़ साल के बाद हरियाणा में 24 घंटे बिजली मिलेगी, दोनों में से कौन सही है ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम दोनों ही सच बात कह रहे हैं। डेढ साल में 6 महीने भी आते हैं। मुख्य मंत्री जी और मेरी बात में 6 महीने तो कॉमन हैं। छः महीने के बाद फिर हम सदन में आएंगे। (विघ्न) आप 6 महीने के बाद देख लेना कि बिजली में कितना सुधार होगा। गांव का प्रत्येक किसान महसूस करेगा कि बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है और इसको राहत मिली है। 25 माननीय साथी बजट पर बोले। कैप्टन अजय सिंह और चौटाला जी बोले। चौधरी बीरपाल सिंह जी ने बजट के आंकड़ों की बात की, कानून और व्यवस्था की बात की। इन्होंने रोहतक जिले के डी०सी० और एस०पी० को कमजोर आदमी बताया है। वहां के डी०सी० और एस०पी० तो जवाब है लेकिन पता नहीं इनको किस नजर से वे कमजोर लग रहे हैं। इन्होंने रोहतक और झज्जर जिलों के अपराध की बात की। रोहतक जिले के बहादुरगढ़ गांव में एक दिन में 5 हत्याएं हुईं। उस केस में मुजरिम पकड़े गए हैं। निर्मल सिंह जी ने 24 घण्टे बिजली देने की बात कही। चन्द्र मोहन जी ने गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की बात की वह मैंने पहले ही बता दी है। चन्द्र भाटिया जी ने इस बजट को अब तक की सरकारों का सबसे बढ़िया बजट बताया और कहा कि कुछ लोग मुख्य मंत्री की छवि को खराब करते हैं उनका निराकरण करना चाहिए, उन्होंने यह बात ठीक कही। सोमवीर सिंह और बन्ता राम ने गदौर की बात की। जयसिंह राणा और अशोक कुमार ने महाविद्यालय की बात की और प्राइवेट स्कूलों में फीस मैनेजमैंट की कुछ शिकायतों की

बात कही। दादुपुर नलवी कैनाल की बात मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि किस तरह वहां पर काम चल रहा है। आपने कहा कि पिछले साल कोई कालेज नहीं बनाया गया। मैं यहां बताना चाहूंगा कि डेढ़ साल में हमने हरियाणा में 8 नए महाविद्यालय खोले हैं। अम्बाला में इस साल नया राजकीय महाविद्यालय खोला है जहां एम०ए० कौमर्स और बी०ए० हिन्दी की क्लासें चल रही हैं। बोन्द कलां जो कि स्पीकर साहब आपका भी गांव है वहां कितना अच्छा कालेज चल रहा है। नारनौल के किशन नगर गांव में जो कि राजस्थान की सीमा पर है वहां कालेज खोला है। फतेहाबाद और शिवानी में कालेज खोलने जा रहे हैं। नारनौंद में कालेज में बी०एड० की क्लासें चल रही हैं। नांगल चौधरी के कालेज को सरकार ने अधिग्रहण किया है। इस प्रकार हमने थोड़े से समय में 8 नए महाविद्यालय खोले हैं। चौ० भागीराम जी के लड़के की डबवाली में महालक्ष्मी फिलिंग स्टेशन में जो वारदात हुई उसके बारे में गृहमंत्री जी से बात हुई है और उस बारे में पुलिस कार्यवाही कर रही है। यह बहुत ही दुखद घटना है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। किसाऊ डैम की बात मुख्य मंत्री जी के ध्यान में है और वे उस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। खुर्शीद अहमद जी ने बेरोजगारों को बसों के रूट परमिट देने की बात कही। इस बारे में कैबिनेट की सब कमेटी बनाई हुई है वह फैसला करेगी और जल्दी ही वह अपने फैसले का एलान करने जा रही है। मनीराम जी ने कहा कि शराबबन्दी के कारण जो टैक्स लगाए गए उनको वापिस लिया जाए, जबकि शराबबन्दी के कारण कोई भी टैक्स नहीं लगाए गए हैं। स्पीकर साहब, मैं संक्षेप में इस महान सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट पर 25 माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने बिजली के बारे में कहा। मैं उनको बताना चाहूंगा कि बिजली का सबसे बड़ा काम हमने पहले दिन ही अपने हाथ में ले लिया था और उसमें हमने सफलता प्राप्त की है। बिजली की जिन योजनाओं के बारे में वर्ल्ड बैंक ने मान्यता दी तो जब वर्ल्ड बैंक के आदमी यहां आए तो वह बिजली के प्रोसैस, बिजली की गतिविधि और इसकी डिवैल्पमैंट के वर्क्स से सन्तुष्ट हुए। एक बात हमारे विरोधी पक्ष के भाईयों ने हमारी गठबंधन सरकार के बारे में कही कि यह सरकार चल पाएगी या नहीं ? स्पीकर साहब, अगर हमारे गठबंधन के बारे में किसी की कोई वहम हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। वहम का कोई इलाज नहीं है। इनको हमारे गठबंधन की चौधरी बंसी लाल जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ऐसे लग रही है जैसे जापे वाली औरत को गूंद लगता है।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, बजट पर बहुत लम्बी बहस हुई। सदन में जो मेन मुद्दे उठाए गए वह बिजली, पानी और सड़कों के बारे में उठाए गए। मैं उन मुद्दों के बारे में रोशनी डालना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के हर गांव में आज से 28 साल पहले मैंने बिजली पहुंचाई थी। उसके बाद न किसी ने कोई तार बदली और न किसी ने कौइल खरीदी ताकि बिजली को बढ़वा दिया जाए। बिजली की कंजम्पशन बढ़ती गई। लेकिन बिजली की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत नहीं किया गया। ये खामियां बिजली के बारे में रही। वर्ष 1997-98 में बिजली की हालत कम्फरटेबल रही और 1998-99 में आज तक बिजली की हालत कम्फरटेबल है। अप्रैल, 1997 में 303 लाख यूनिट बिजली दी गई, 1998-99 में 334 लाख यूनिट बिजली दी गई। मई 1997-98 में 334 लाख यूनिट बिजली दी गई। 1998-99 में 364 लाख यूनिट बिजली दी गई। जून, 1997-98 में 348 लाख यूनिट बिजली दी गई। 1998-99 में 394 लाख यूनिट बिजली दी गई। जुलाई, 1997-98 में 396 लाख यूनिट बिजली दी गई। 1998-99 में 430 लाख यूनिट बिजली दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, बिजली क्षेत्र में हमने खासी प्रगति की है। लगभग 10 या 15 दिन पहले वर्ल्ड बैंक के एशिया के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वे हमारे यहां आए थे उन्होंने कहा कि हम प्रदेशों को ही नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज को हरियाणा की मिसाल दे रहे हैं कि बिजली ऐसे बनती है। उन्होंने हमारे बिजली के प्लांट

[श्री बंसी लाल]

भी देखे। अध्यक्ष महोदय, जब से हरियाणा प्रदेश बना है उस दिन से ले कर आज तक हमारे पास बिजली की पैदावार के लिए जो कारखाने लगे हुए हैं वे टोटल 863 मैगावाट बिजली उत्पादन करने की कैपेसिटी के हैं। उनमें से कुछ प्लांट बहुत पुराने हो गए हैं वे प्लांट 27-28 और 30-31 परसैंट लोड फैक्टर पर चलते हैं। हमें उनको भी ठीक करवाना है और इस 863 मैगावाट की कैपेसिटी में और कैपेसिटी एड करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगस्त 1998 तक इस साल में 45 मैगावाट बिजली शामिल कर देंगे। 30 जून 1999 तक 360 मैगावाट बिजली शामिल कर देंगे और दिसम्बर 1999 से पहले पहले 376 मैगावाट और नई बिजली शामिल कर देंगे। हमारा ख्याल है कि दिसम्बर 1999 तक ही हम 508 मैगावाट और बिजली जिसका हमने प्लान बना रखा है, जिसका हमने काम भी दे रखा है, दिसम्बर 1999 तक 1289 मैगावाट बिजली इस 863 मैगावाट में नई शामिल कर देंगे। इससे ज्यादा तेजी से कम से कम हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में तो बिजली ऐड करने की, पैदा करने की कोशिश किसी ने नहीं की। अब अध्यक्ष महोदय, सवाल उठता है कि हम यह बिजली कहां से पैदा करेंगे। एक तो 25-25 मैगावाट के दो प्लांट 10-15 दिनों में ही कमीशन हो जाएंगे। दूसरे हम जो करेंगे वह है मैगनम पावर प्लांट जो बादशाहपुर पास है उससे 25 मैगावाट की बिजली पैदा करेंगे। इसी प्रकार से एन०टी०पी०सी० द्वारा 342 मैगावाट का प्लांट हम फरीदाबाद में बना रहे हैं। उसका एक यूनिट कागजों में तो कहते हैं कि जून, 1999 तक तैयार करके दे देंगे लेकिन हमारा ख्याल है कि वह अगले साल जनवरी तक दे देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। उस यूनिट में अगले साल 146 मैगावाट और बिजली ऐड हो जायेगी। यह मार्च, अप्रैल में मिल जाने की उम्मीद है। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन को सुधारने का काम हमने एक जर्मनी की फर्म "ए०बी०बी०" है, उसको दिया है। जो पानीपत के 110-110 मैगावाट के 4 पुराने यूनिट्स हैं उनका इस वक्त प्लांट लोड फैक्टर 27 से 31 प्रतिशत के बीच में वैरी करता है। हमारे से जर्मनी की फर्म ने वायदा किया है कि एक तो इनको 110 मैगावाट की बजाय 118 मैगावाट कर देंगे और दूसरे इनका प्लांट लोड फैक्टर कम से कम 80 कर देंगे। जब यह काम हो जायेगा तो 68 मैगावाट बिजली और आ जायेगी। इसके बाद एन०टी०पी०सी० का तीसरा प्लांट आ जायेगा और पानीपत के आगे 136 मैगावाट के दो यूनिट और आ जायेंगे। लिक्यूड फ्यूल के 4 नए स्टेशन 100-100 मैगावाट के दिसम्बर 1999 से पहले तैयार हो जाएंगे, इस तरह हमें 100 मैगावाट बिजली और मिल जायेगी। इसके अलावा 289 मैगावाट बिजली की हमारी प्लान है मेरे ख्याल में 2000 तक वह बिजली हमें मिल जायेगी। इसी प्रकार से पानीपत थर्मल प्लांट में 60 मैगावाट बिजली और आ जायेगी। पानीपत का छठा यूनिट चालू हो गया है। इससे हमें 210 मैगावाट बिजली आ जायेगी। यह दिसम्बर 1999 तक आ जायेगी।

डा० बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि हमारे यहां की सभी यूनिटें ठीक काम कर रही हैं। कल यह खबर आई थी जिसमें कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पानीपत थर्मल प्लांट के 110 मैगावाट का एक प्लांट गत 8 मास से बन्द पड़ा है। जबकि ये कह रहे हैं कि वह प्लांट चालू है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर स्थिति यह है कि यदि पानीपत के इन यूनिटों को ठीक करने के लिए 24 घंटे दिन रात काम किया जाये तो भी यह सारा काम 4 साल में पूरा हो पायेगा।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, लिक्वड फ्यूल में 200 मैगावाट और आ जाने की उम्मीद है। इसी तरह से भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट से हमको 30 मैगावाट बिजली और मिल जायेगी। फरीदाबाद में एन०टी०पी०सी० का 432 मैगावाट का जो प्लांट बन रहा है उस पर 1163 करोड़ रुपये की लागत आयेगी लेकिन उसके पूरा होने तक लगभग 1200 करोड़ रुपये लग जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्लांट का कार्य भी हम जल्दी ही करवा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक 110-110 मैगावाट वाले यूनिट्स

की रैनोवेशन का सवाल है इसमें 300 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा और वहां पर बिजली की भी बढ़ौतरी होगी 250-60 मैगावाट। अध्यक्ष महोदय, पानीपत में जो छठा यूनिट है उसको बनाने का काम 1989 में शुरू किया गया था और उसी वक्त मशीनरी आनी शुरू हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, अगर यह यूनिट उस वक्त बन जाता तो उस पर 238 करोड़ 26 लाख रुपये का खर्चा होता। उस वक्त चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी, उसके बाद चौधरी भजन लाल भी सत्ता में आये। (शोर एवं व्यवधान) अगर वे उसी वक्त उसको बनवा देते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में प्वाइंट आफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान) मैं एक बात पूछना चाहता हूं * * * * * ।

Shri Ram Bilas Sharma : Sir, this is not the question hour.

Mr. Speaker : Nothing to be recorded.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस गलत आंकड़े देकर सदन को * * * * * कर रहे हैं। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब प्लीज आप बैठ जायें।

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह * * * * * शब्द अच्छी सैंस में नहीं है, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाये। मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप सदन की कार्यवाही में विघ्न न डालें, सदन की कार्यवाही ठीक तरह से चलने दें, यह प्वायंट आफ आर्डर का समय नहीं है। (विघ्न एवं शोर)

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल यह रिक्वैस्ट की है कि "गुमराह" शब्द को कार्यवाही से डिलीट किया जाए। इन्हें फैक्ट्स और फिगर्ज़ दे कर बताना चाहिए कि कहां पर और कैसे गुमराह किया जा रहा है। "गुमराह" शब्द को इतना सस्ता नहीं बनाया जाना चाहिए। (विघ्न) It is not in good sense. Please speake with facts & figures (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कृष्ण लाल जी, क्या आपको पता है कि प्वायंट ऑफ आर्डर क्या होता है ? आप अपनी सीट पर बैठें (विघ्न एवं शोर) लीडर आफ दि हाउस की तरफ से जो बताया जा रहा है वह सही है, अगर उनकी बात सही नहीं है तो बताइये। (विघ्न)

एक आवाज : ये वही तो बता रहे हैं। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के नेता ने पानीपत थर्मल प्लांट के बारे में बताया कि 210 मैगावाट का इन्होंने शुरू किया है इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि यह थर्मल प्लांट 1989 में जब चौधरी देवी लाल की सरकार थी उस वक्त में शुरू किया गया था। उस वक्त चौधरी देवी लाल सरकार ने 157.6 करोड़ रुपये में इसको बर्क आउट किया था। इस प्लांट के काम को करने के लिए 100 करोड़ रुपये के लगभग के सामान का आर्डर भी दिया गया था और मशीनरी भी आई, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई और चौधरी भजन लाल जी के समय में इस पर आगे कोई काम नहीं हुआ। (विघ्न एवं शोर)

श्री वंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि मशीनरी 1989 में आई और उस वक्त चौधरी देवी लाल जी मुख्य मन्त्री थे और 75-80 करोड़ रुपये की मशीनरी आई। यह 75-80 करोड़ रुपये की

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री बंसी लाल]
मशीनरी तो जरूर मंगवाई गई लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया गया। चौधरी देवी लाल के समय में अगर यह 210 मैगावाट का प्लांट कम्पलीट हो जाता तो इसकी लागत 238.26 करोड़ रुपये आती। (विघ्न)

Shri Krishan Lal : Speaker Sir. ..... (Interputions)

Mr. Speaker : Shri Krishan Lal ji, please take your seat otherwise, I will have to name you.

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर यह मशीनरी उस वक्त यूज़ हो जाती तो यह प्लांट 238.26 करोड़ रुपये में बन जाता लेकिन यह मशीनरी पेटियों में पड़ी रही और उसको जंग लगता रहा। हमने आ कर के इन पेटियों को खुलवाया है और इस मशीनरी को इस्तेमाल किया है। अध्यक्ष महोदय, 1991 में चौधरी भजन लाल जी के समय में अगर यह प्लांट लग जाता तो 320 करोड़ रुपये में यह बन जाता और अगर 1993 में इसे लगा देते तो यह 405 करोड़ में बन जाता। अध्यक्ष महोदय, जितनी देर इसको पूरा होने में होती रही उसी अनुपात में रेट्स भी बढ़ते रहे और इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ती जा रही है। अब इस प्रोजैक्ट के लिए हमने 634 करोड़ रुपये की लागत आंकी है और अब 634 करोड़ रुपये में इसे हम बना रहे हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गईं) यह मशीनरी बेकार पड़ी रही और उस पर ब्याज की राशि भी पड़ती रही। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, छठे यूनिट का यह काम तेजी से चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा बारह प्लांट 25-25 मैगावाट के फील्ड में हम लगवा रहे हैं, इसकी क्लीयरैंस दे दी है। इसकी अनुमति भारत सरकार से आनी है और अपने आप पैसे का प्रबन्ध कर रहे हैं। जैसे ही पैसे का प्रबन्ध हो जाएगा उन पर काम चालू हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारा पावर परचेज एग्रीमैंट है पानीपत की आयल रिफायनरी से हो गया है। वह हमें अल्टीमेटली मार्च 2001 तक 301 मैगावाट बिजली देगी। यह जो पानीपत की रिफायनरी बनी है उससे एक रिफयूज निकलता है जिससे बिजली पैदा होती है जोकि हमें वहां पर मिलेगी। यमुना नगर में 250-250 मैगावाट के दो प्लांटों के टैण्डर आज कल में निकलने वाले हैं, शायद ईशू भी हो गए हों। इस तरह से जो हम पावर को बढ़ा रहे हैं इसके बढ़ाने से बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे और प्रदेश को बहुत फायदा होगा। इसके बाद इन्डस्ट्री में भी फायदा होगा। सदन में यह भी एलिगेशन लगाया गया कि हमारी सरकार के आने के बाद हरियाणा में कोई भी इण्डस्ट्री नहीं लगी है। मैं इनको यह बताना चाहता हूँ कि हम उनको इनवाइट ही नहीं कर रहे हैं। हम उनको इसलिए इनवाइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने उनको बुला लिया, उसने यहां पर पैसा इन्वैस्ट कर लिया और हम उसको पूरी बिजली नहीं दे पाएं तो ठीक बात नहीं होगी। वह तो फैक्टरी लगा लेगा और मजदूर रख लेगा तो उससे हमारे लिए भी ला एण्ड आर्डर की प्रौब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन हमारे यहां पूरी बिजली न होने के बावजूद भी इन्डस्ट्रीलिस्ट हमारे पास हरियाणा में इन्डस्ट्री खोलने के लिए आते हैं। वे इसलिए आते हैं क्योंकि हरियाणा में ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। अध्यक्ष महोदय, एक बात और यहां पर कही गई कि वर्ल्ड बैंक से हम कर्जा इसलिए ले रहे हैं कि हम उसको खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं उसको हम हज़म कर जाएंगे। ये इस प्रकार की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि इन भाईयों ने वह देखा ही नहीं है और इनकी हैसियत ही नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक उस इन्स्टीच्यूशन को और उस कारपोरेशन को लोन देता है जिसकी क्रैडिबिलीटी हो। इसके साथ-साथ वर्ल्ड बैंक के आदमी आते हैं, वे सर्वे करते हैं, हिसाब करते हैं, पार्टी को साथ बिठाते हैं और यह भी देखते हैं कि यह पार्टी पैसा वापिस दे सकती भी है या नहीं दे सकती है यह कंडिशन तो उनकी सबसे

पहले है। कोई बैंक और कोई भी मनी लैन्डर तब तक पैसा नहीं देगा जब तक उसको उसका पैसा वापिस आने की गारन्टी न हो। सदन में एक साथी ने कह दिया कि हम वर्ल्ड बैंक से एक हजार करोड़ रुपया खुर्द बुर्द करने के लिए ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक का जो लोन होता है उस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सी जगहों पर जहां पर काम करवाते हैं वर्ल्ड बैंक सीधा पैसा दे देता है। उसके साथ जो चीजें हम खरीदते हैं वर्ल्ड बैंक के आदमी उसकी इन्सपैक्शन करते हैं कि वह चीज ठीक है या नहीं है उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं और वे यह भी देखते हैं कि वे चीजें पूरी हैं या नहीं हैं। वे यह भी देखते हैं कि वह चीज ठीक जगह पर भी लगी है कि नहीं लगी है। अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक वालों ने हमें वहाँ जाकर के जो चिट्ठी लिखी है अगर वह हम पढ़कर यहां पर सुना दें तो इनकी देही में बाकी कुछ न रहेगा। इतनी बढ़िया चिट्ठी उन्होंने हरियाणा सरकार के बारे में लिखी है। अध्यक्ष महोदय, जो वर्ल्ड बैंक से हमको लोन आता है चाहे वह बिजली बोर्ड के लिए आए या चाहे वह डब्ल्यू०आई०सी०पी० के लिए आए, उस पर 13 परसैंट ब्याज होता है और जो रुपया हमको वर्ल्ड बैंक से लोन के रूप में मिलता है उस लोन में 30 परसैंट भारत सरकार हमको ग्रांट देती है और 70 परसैंट लोन हमको वापस करना है। अध्यक्ष महोदय, जहां इतनी तसल्ली से काम हो रहा हो वहां इनको सबसे बड़ी बात यही लगती है कि बिजली का काम साल डेढ़ साल में बहुत बढ़िया हो जाएगा तो फिर ये क्या कहेंगे इनके पास फिर कहने को कुछ भी नहीं रहेगा ? अध्यक्ष महोदय, अभी हमें 240 करोड़ रुपये का लोन मिला है। वर्ल्ड बैंक वालों ने यह 240 करोड़ रुपया हमें पर्टीकुलर आईटम के लिए पर्टीकुलर स्कीम के लिए दिया है। जो 240 करोड़ रुपया हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है इसमें जो जो स्कीम शामिल हैं वह इस तरह हैं- ओवर लोडिड फीडर्ज को जिनमें पूरी बिजली नहीं ले जायी जा सकती, को मजबूत करने के लिए एवं सही बनाने के लिए हम ऐसे फीडर्ज को रिप्लेस करेंगे। हम 50 फीडर्ज 35.79 लाख रुपये की कीमत से खरीदेंगे। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर्ज छोटे रह गए हैं, उनकी आगमेंटेशन के लिए हम साढ़े पांच हजार नये ट्रांसफार्मर्ज बदलेंगे। इनकी कीमत चालीस करोड़ 66 लाख रुपये होगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हम एक 220 के०वी० का सब-स्टेशन पल्ला में बनाएंगे। इस सब-स्टेशन पर 18 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा हम तीन नयी लाइनें पल्ला से पाली, पाली से समेहपुर और यमुनानगर से शाहबाद बनाएंगे। इनकी लागत पर 24 करोड़ 50 लाख रुपये लगेंगे। इसी प्रकार से 32 करोड़ रुपये की लागत से हम दो लाख ऐनर्जी मीटर्ज परचेज करेंगे। इसके अलावा 24 ऐगजिस्टिंग 33 के०वी० सब-स्टेशंज 9 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत से आगमेंटेशन करेंगे। 80% of these works would be completed before March, 1999 and the remaining works would be completed by December, 1999. यह सब हमारा 240 करोड़ रुपये में आएगा। इसके अलावा जो हमको एक हजार करोड़ रुपये का और लोन वर्ल्ड बैंक से मिलेगा, उसके बारे में वर्ल्ड बैंक वाले सारी चीजों को यहां पर आकर देख गए हैं और हमारे साथ डिसकस कर गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस लोन में हम जो काम करेंगे वह यह है-इम्प्रूवमैन्ट ऑफ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए हम 15500 किलोमीटर लम्बी डिस्ट्रीब्यूशन लाईन बिछाएंगे जिसकी लागत 290 करोड़ रुपये आएगी। जिन लाईनों से पावर हम कंज्यूमर ऐंड तक पहुंचाएंगे, उनके लिए हम 12 हजार नये ट्रांसफार्मर्ज खरीदेंगे जिनकी कीमत 120 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा हम 3.77 हजार नये मीटर्ज खरीदेंगे इनकी कीमत चालीस करोड़ रुपये होगी। इसी तरह से हम पांच एल०टी० कैपीसिटेटर्ज पावर की वोल्टेज को इम्प्रूव करने के लिए पांच करोड़ रुपये की लागत से खरीदेंगे। इसके अलावा डिमांड साईड की मैनेजमैंट पर भी काम किया जाएगा जिसकी लागत 47 करोड़ रुपये आएगी और जो ऐगजिस्टिंग सब-स्टेशंज हैं उनका भी आगमेंटेशन किया जाएगा। जिसकी लागत 320 करोड़ रुपये आएगी। इसी तरह से हम 220 के०वी० के चार नये सब-

[श्री बंसी लाल]

स्टेशंज बनाएंगे जो कि यमुनानगर, टेपला, चीका और महेन्द्रगढ़ में होंगे। इसी तरह से 220 के०वी० के हम पांच सब-स्टेशंज का आगमेंटेशन करेंगे जो कि पेहवा, सोनीपत, पानीपत, निसिंग और पंचकूला में 17.00 बजे होंगे। 132 के०वी० के ग्यारह नये सब-स्टेशन कुंडली, सकूझाना, बाड़ला, कंथली, जस्सान, मुरथल, हरसाना कलां, जलमाना, तोशाम, भिवानी और लोहारू में बनाएंगे। 132 के०वी० की 3 की आगमैंटेशन होगी जिसमें गोहाना, इस्माइलाबाद और उकलाना शामिल हैं। 66 के०वी० के छह सब-स्टेशन, कालका मंसा देवी, सैक्टर-9 गुड़गांव, सैक्टर-55,56 गुड़गांव, सैक्टर-45 गुड़गांव और लोहारू में बनाएंगे। 33 के०वी० के 35 सब-स्टेशन बनाएंगे और 33 के०वी० के सब-स्टेशन जो आगमैंट करेंगे वह 36 होंगे। कुछ साथियों ने ऐतराज किया था कि 500 करोड़ के लोन का क्या करेंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक इन चीजों की गारन्टी करता है और किस-किस स्टेज पर करता है यह बता देता हूं। जब हम टैंडर मांगते हैं तो उसकी फार्मुलेशन की स्पेसिफिकेशन वर्ल्ड बैंक को भेजते हैं Tenders are cleared by the Bank before, issue. टैंडर मांगने से पहले हम उसको क्लीयर कराते हैं और जब टैंडर आ जाते हैं, हम उनको ऐग्जामिन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये ठीक हैं कि नहीं। अगर ठीक होते हैं, तब वर्ल्ड बैंक को भेजते हैं। जब वर्ल्ड बैंक उनकी मंजूरी देता है तब काम अलौट होता है। The World Bank also sends supervision mission to ensure that whether the material has actually arrived whether the material is of good quality and material has actually installed. इसके बारे में वर्ल्ड बैंक वाले अपनी पूरी तसल्ली करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी कहा गया कि बिजली के रेट 8 बार बढ़ा दिये। स्पीकर सर, बिजली के रेट बढ़ाए जाने का फार्मूला यह है कि Ingredients of the general tariff include the cost of purchase, establishemtnt costs, depreciation, interest, repayment to Government, Operation and maintenance, charges of thermal plant and cost of fuel, increase in cost of oil and freight. The fuel costs are raised by Government of India. अध्यक्ष महोदय, जो बिजली के टैरिफ चौधरी भजन लाल ने 14-9-1982 को 15 परसैंट बढ़ाए, 15-9-1983 को 35 परसैंट सिर्फ इंडस्ट्री पर, 1-4-1984 को 45 परसैंट इंडस्ट्री पर, 1-5-1985 को 30 परसैंट जनरल बढ़ाए। During this period the fuel surcharge was increased five times. 1-10-1982 को चौधरी भजन लाल मुख्य मंत्री थे तब 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए, 1-4-1983 को 11 पैसे, 1-10-1983 को 12 पैसे, 1-4-1984 को 16 पैसे और 1-10-1984 को 17 पैसे इस प्रकार पांच बार बढ़े। उसके बाद लोकदल की सरकार आई और चौधरी देवी लाल मुख्यमंत्री बने तो तीन बार बिजली के रेट बढ़े। 1-12-1987 को ऐक्सैप्ट डौमैस्टिक 25 परसैंट बढ़ाए, 1-9-1988 को 45 परसैंट सब पर, 1-12-1990 को 25 परसैंट और ड्यूरिंग दिस पीरियड आठ बार फ्यूल सरचार्ज बढ़े, एक बार 1-12-1987 को 16 पैसे, 1-4-1988 को 21 पैसे, 1-10-1988 को 22 पैसे, 1-4-1989 को 28 पैसे, 1-10-1989 को 33 पैसे, 1-4-1990 को 36 पैसे, 1-10-1990 को 38 पैसे और 15-10-1990 को 42 पैसे बढ़ाए। जब चौधरी भजन लाल का सैकिण्ड टन्योर आया तो बिजली बोर्ड का टैरिफ 5-6-1992 को 25 प्रतिशत, 1-2-1994 को 25 प्रतिशत, 28-12-1994 को 25 प्रतिशत बढ़ा और इस दौरान फ्यूल सरचार्ज ग्यारह बार बढ़ा जो कि इस प्रकार है-- 16-6-1992 को 61 पैसे, 17-2-1993 को 66 पैसे, 1-4-1993 को 72 पैसे, 18-6-1994 को 74 पैसे, 29-1-1994 को 75 पैसे, 1-4-1994 को 81 पैसे, 16-6-1994 को 83 पैसे, 11-10-1994 को 85 पैसे, 1-4-1995 को 5 पैसे, 29-12-1995 को 10 पैसे, 1-4-1996 को 18 पैसे। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने बिजली का जो टैरिफ बढ़ाया है वह इस प्रकार है-- 1-7-1996 को 20 प्रतिशत, 15-6-1998 को 15 प्रतिशत

तथा सात बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। जो कि इस प्रकार है-- 1-7-1996 को 8 पैसे, 19-8-1996 को 13 पैसे, 12-9-1996 को 19 पैसे, 20-12-1997 को 22 पैसे, 6-5-1997 को 35 पैसे 18-9-1997 को 38 पैसे और 20-11-1997 को 41 पैसे। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने एक बात इस सदन में कही है कि वर्तमान सरकार दिसम्बर तक बिजली का रेट छः रुपये प्रति यूनिट कर देगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे इस सदन में नहीं आयेंगे। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि आज भी ये इस बात को अक्सैप्ट करते हैं ? (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात कही है कि जो वर्ल्ड बैंक से बिजली बोर्ड के लिये 2400 करोड़ रुपया लिया है उसकी जब दूसरी किस्त एक हजार करोड़ रुपये की यह वर्तमान सरकार दिसम्बर के आस-पास लेगी तो वर्ल्ड बैंक की यह शर्त है कि इस सरकार को बिजली का टैरिफ 30 प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पहली किस्त 240 करोड़ रुपये की इसी शर्त पर रिलीज की गई है जब इस सरकार ने 15 प्रतिशत टैरिफ को बढ़ाया है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने यह बात इस सदन में कही है कि अगर दिसम्बर तक बिजली का टैरिफ 6 रुपये प्रति यूनिट नहीं हुआ तो ये इस सदन में नहीं आयेंगे। क्या ये अपनी इस बात पर कायम हैं ? मैं तो इनसे सिर्फ इतनी बात ही पूछना चाह रहा था ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि वर्ल्ड बैंक से दिसम्बर में जब अगली लोन की किस्त हरियाणा बिजली बोर्ड को दी जायेगी तो वह इसी शर्त पर दी जायेगी कि बिजली का टैरिफ 30 प्रतिशत बढ़ाया जाये, नहीं तो अगली किस्त रिलीज नहीं की जायेगी।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को यह आश्वासन देता हूं कि दिसम्बर तक हम बिजली का टैरिफ एक पैसा भी नहीं बढ़ायेंगे ? मैं एक बात और इस सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा बिजली बोर्ड पर वर्ल्ड बैंक की 30 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने की कोई शर्त नहीं है। अब चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी यह फैसला करें कि अगर दिसम्बर तक बिजली की दरें 6 रुपये प्रति यूनिट नहीं हुई तो क्या ये सदन में नहीं आयेंगे ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पर कायम हूं कि जब भी इनकी दूसरी या तीसरी किस्त फाईनल होगी जोकि 2400 करोड़ रुपये की वर्ल्ड बैंक ने देनी है उस समय इनको टैरिफ को बढ़ाना ही पड़ेगा। इस सरकार ने 2400 करोड़ रुपये बिजली बोर्ड के लिए, 1400 करोड़ रुपये रोड्ज के लिए और 1805 करोड़ रुपये नहरों के लिए तीन लोन लिये हैं और राम बिलास शर्मा जी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि पोखरण में परमाणु बम विस्फोट करने से देश की शान बढ़ी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि विस्फोट करने के बाद यू०एस०ए० और जापान ने इन तीन बड़े लोनज की कंडीशन के आधार पर सैंक्शन किया है या नहीं। दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार इन तीन बड़े लोनज के बारे में हरियाणा की दो करोड़ जनता को व्हाइट पेपर जारी करके स्पष्ट करेगी ताकि हरियाणा की जनता को इस बारे में पता लगे ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि राम बिलास जी ने परमाणु बम विस्फोट के बारे में कहा। मैं समझता हूं कि परमाणु बम विस्फोट के बारे में अकेले राम बिलास जी ने नहीं पूरे देश की 99 करोड़ जनता ने कहा है। मैं समझता हूं कि इससे चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को भी गर्व है कि हमारा देश ताकतवर बना है। 11 और 13 तारीख को जो परमाणु बम के धमाके पोखरण में हुए हैं, उस से तो अमरीका जो सारे संसार में अपनी दादा गिरी करता है, वह भी हिल गया। जहां

[श्री बंसी लाल]
तक सैंक्शंज़ की बात है कि उनसे कितना फर्क पड़ेगा, मैं कहना चाहता हूं कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, यह तो बाद की बात है लेकिन हमारे ऊपर अभी तक इस का कोई प्रभाव नहीं है। हमें 2400 करोड़ रुपये का लोन ज्यों का त्यों प्राप्त होगा, उस में कोई बाधा नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार का वर्ल्ड बैंक के साथ जो एग्रीमैंट था, वह चिट्ठी पिछले सत्र में मैंने पढ़कर सुनाई थी तथा वह चिट्ठी आपको दी भी थी। उस में लिखा था कि पहले जो लोन लिया जाएगा उस पर 15 प्रतिशत टैरिफ पड़ेगा तथा वह टैरिफ सरकार पर पड़ना था। फिर आपने वर्ल्ड बैंक से दोबारा लोन की परमिशन लेकर इस टैरिफ को बढ़ाया। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी का अंदेशा बिल्कुल सही है कि उस एग्रीमैंट में यह लिखा है कि दूसरा जो लोन लिया जाएगा, उस पर आप को 30 प्रतिशत टैरिफ देना पड़ेगा अन्यथा वे आपको लोन नहीं देंगे। अब आप लोन कब लेंगे यह बात अलग है लेकिन आप यह बताएं कि यह एग्रीमैंट हुआ है या नहीं ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा ऐसा कोई एग्रीमैंट नहीं हुआ है क्योंकि हम ने रियलाईजेशन ठीक कर ली है इसलिए रेट बढ़ाने की कोई बात ही नहीं है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी सदन में वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की बात कह रहे थे, उस समय बदकिस्मती से मैं सदन में उपस्थित नहीं था। इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है क्योंकि यहां सदन में बोलने से पहले मैं इन को किसी और काम से असैंबली के ऑफिस में ले गया था उस वक्त ये मुझसे कह रहे थे कि खूब लोन लो और हर चीज के लिए लोन लेकर काम करते जाओ। मैंने उन को कहा कि मैं तो सिर्फ उस लोन की क्लीयरैन्स महकमें को देता हूं कि जिसकी मुझे तसल्ली हो जाए कि यह आसानी से हमें रुपये वापिस कर देगा। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने यह भी कहा कि आप तो लोन लेते जाओ, इन को आकर के तो हम ने ही देना है। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, यह कुर्सी सिर्फ मेरी ही नहीं है। इस पर आज कोई है, कल कोई था और भविष्य में न जाने कौन होगा। लेकिन कोई न कोई तो इस कुर्सी पर बैठेगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्वाएंट ऑफ आर्डर। मैं मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि यह बात मैंने उनको अपने भाषण के बाद कही है। (विघ्न) मैंने उस वक्त मुख्य मंत्री जी को यह बात भी कही थी कि कम से कम लोगों को यह तो बता दें कि सरकार यह जो लोन ले रही है, वह किन टर्मज़ एंड कंडीशंज़ पर ले रही है। सरकार को व हमें तो मालूम है लेकिन लोगों को भी इस बारे में मालूम होना चाहिए।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हम लोगों को बता रहे हैं और आगे भी बता देंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है कि पहले तो कहा कि लोन ले लो और फिर आधे घंटे या 15 मिनट के बाद कहा कि लोन क्यों ले रहे हो। इन्होंने मुझे गलत गाईड क्यों किया ? (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, चिमन भाई पटेल 3 साल गुजरात के मुख्य मंत्री रहे हैं और उन्होंने 3 साल के अंदर 30 करोड़ रुपये की गुजरात में इन्वैस्टमैंट की। परिणामस्वरूप गुजरात आज सबसे सम्पन्न राज्य है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इन से पूछना चाहता हूं कि ये ज्यादा कर्जे लेने के हक में हैं अथवा नहीं ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हां मैं इस हक में हूं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, यही बात तो मैं भी कह रहा हूं। लेकिन इन्होंने तकरीर कुछ और ही कर दी है। अध्यक्ष महोदय, 6 रुपये वाली बात तो खैर अपने घर के ही सदस्य की है, इसलिए मैं ज्यादा इन्सिस्ट नहीं करूंगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात और हिमाचल प्रदेश के हाइड्रो पॉवर प्रोजैक्ट के बारे में कही है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश का जो नाथपा झाखड़ी का प्रोजैक्ट है मैंने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का एग्रीमैंट करवाया था जबकि वह अकेले हरियाणा का होना चाहिए था। लेकिन बाद में आने वाली सरकारों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह सैन्ट्रल प्रोजैक्ट हो गया। पार्वती प्रोजैक्ट में 5 स्टेटस सांझेदार हैं-हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात। उसमें भी हिमाचल प्रदेश वाले रोड़ा अटका रहे हैं, वे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अल्टिमेटली वह भी भारत सरकार ले लेगी। हम तो कहते हैं कि कोई ले लो, हमें तो बिजली अलाट कर दो। यह चीज अकेले हमारे काबू की बात नहीं है कि चलते-चलते हम लें लें क्योंकि केस छीन तो हम सकते नहीं। एक बात और कही गई कि टैरिफ क्यों बढ़ाया। टैरिफ इस लिए बढ़ाया कि the tariff increase has become essential because of the following reasons :-

(i) Between May, 1996 and May, 1998, the whole price index has gone upto 20%

(ii) Acceptance of recommendations of Fifth Pay Commission would cost the Electricity Board Rs. 47 crores per annum.

(iii) Reintroduction of slab system in whole of the State would need about Rs. 30 crores per annum.

अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर सैक्टर में हमने बिजली का रेट नहीं बढ़ाया। जहां तक बिजली का रेट बढ़ाने की या किसी कंज्यूमर पर बोझ डालने की बात है, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब लोकदल की सरकार आई तो उन्होंने डौमैस्टिक पावर के ऊपर सिंगल फेस पर 1-4-1981 तक 20 रुपये डिपोजिट था और 31-12-1987 को 50 रुपये कर दिया था। थ्री फेस जिसको बड़े आदमी इस्तेमाल करते थे उस पर 1-4-1987 को 300 रुपये डिपोजिट था और 31-12-1987 को वह बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया था। गरीब आदमियों के लिए 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये यानी ढाई गुना डिपोजिट बढ़ा दिये गये। जबकि बड़े आदमियों के लिए 300 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये किये गए यानी केवल 50 रुपये बढ़ाए गए थे। एग्रीकल्चर के मीटर पर पहले डिपाजिट 1-4-1981 को 50 रुपये थे। लोक दल की सरकार ने 31-12-1987 को डिपाजिट 100 रुपये कर दिये यानी 50 रुपये की जगह 100 रुपये कर दिया था। इण्डस्ट्रियल ऐरिया के ऊपर लो टैंशन कनैक्शन पहले 75 रुपये था, वह इन्होंने 350 रुपये कर दिया। लेकिन जो हाई टैंशन कनैक्शन के असली कंज्यूमर हैं उन पर 5000 रुपये से 7500 रुपये कर दिया, यह डिस-क्रिमिनेशन है। आज बिजली का जो भाव हम लेते हैं वह 3 रु. ये 6 पैसे प्रति यूनिट लेते हैं और पंजाब में प्रति यूनिट 2 रुपये 99 पैसे लिये जाते हैं। इस प्रकार पंजाब और हमारे हरियाणा का 7 पैसे का फर्क है। दिल्ली में तीन रुपये प्रति यूनिट चार्ज किये जाते हैं। इ प्रकार दिल्ली और हरियाणा का 6 पैसे का फर्क है। हरियाणा के किन-किन मुख्य मंत्रियों ने डौमैस्टिक पावर पर पैसे बढ़ाएं यह मैं बता देता हूं। 28-6-1979 को चौधरी भजन लाल ने 22.50 पैसे बढ़ाए और 5-6-1979 को 36 पैसे कर दिया। 6-4-1991 को लोकदल की सरकार ने 36 पैसे से बढ़ाकर एकदम 65 पैसे कर दिया। फिर चौधरी भजन लाल ने दोबारा आकर 90 पैसे कर दिया लेकिन हमने

[श्री बंसी लाल]

अभी तक कुछ नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, 6 लाख गरीब परिवार जो 40 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करते हैं उन पर हमने बिजली का किसी किस्म का कोई रेट नहीं बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, 1996 से 1998 तक जो ट्रांसमिशन लाईन कमिशंड की गई हैं वह पानीपत से नीसिंग 40 किलोमीटर लम्बी पर 7 करोड़ रुपये खर्च किए गए। पेहवा से कैथल सैकिण्ड सर्किट सवा 31 किलोमीटर लम्बी लाईन पर डेढ़ करोड़ रुपये खर्च किए गए। भिवानी से दूसरी जगहों पर 1 करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए गए। पेहवा से शाहबाद तक 35 किलोमीटर लाईन पर दो करोड़ रुपये खर्च किए गए। बादशाहपुर से रिवाड़ी 50 किलोमीटर लम्बी लाईन पर 8 करोड़ रुपये खर्च किए गए। पानीपत से रोहतक 63 किलोमीटर लम्बी लाईन पर 12 करोड़ रुपये खर्च किए गए। नीसिंग से कैथल तक 2 करोड़ रुपये खर्च किये गए। ये सारी 220 के०वी०ए० ट्रांसमिशन की लाईनें थीं। अब मैं 132 के०वी०ए० ट्रासमिशन लाईनों के बारे में बता देता हूं। नीसिंग से सग्गा 11 किलोमीटर लम्बी लाईन पर 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया। एक्सटैंशन ऑफ पानीपत 15.22 किलोमीटर आई०ओ०सी०डी०सी० लम्बी लाईन पर 2 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च किए गए। पेहवा से मलिकपुर इस्माइलाबाद 23 किलोमीटर लम्बी लाईन पर दो करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए गए। चन्दोली छाजपुर 11 किलोमीटर लम्बी लाईन पर 1 करोड़ 10 लाख रुपये खर्च किए गए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 66 के०वी० ए० ट्रांसमिशन लाईन के बारे में बता देता हूं। डाइवर्शन ऑफ पिंजौर पंचकूला 2.04 किलोमीटर लम्बी लाईन पर 20 लाख रुपये खर्च किए गए। पलवल से हथीन 14.11 किलोमीटर लम्बी लाईन पर 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया। बादशाहपुर से डुण्डाहेड़ा तक की लाईन पर 1 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च किए गए। चीका से मस्तगढ़ 12 किलोमीटर लम्बी लाईन पर 25 लाख रुपये खर्च किए गए। भूना नहला लाईन पर 30 लाख रुपये खर्च किए गए। चन्दोली बरसत लाईन पर 25 लाख रुपये खर्च किए गए। अध्यक्ष महोदय, जो और छोटी-छोटी लाईनें हैं वे मैं नहीं पढ़ रहा हूं। टी०ऑफ फाजिलपुर से खरखौदा 12 किलोमीटर लम्बी लाईन पर 25 लाख रुपये खर्च किए गए। मुनक से धर्मगढ़ 8 किलोमीटर लम्बी लाईन पर 20 लाख रुपये खर्च किए गए। टोटल 44 करोड़ 82 लाख रुपये खर्च किए गए। अध्यक्ष महोदय, 1998-99 में हम बिजली बोर्ड का जो काम करेंगे वह भी मैं बता देता हूं। सोनीपत में हम 220 के०वी०ए० का एक नया पावर हाउस बनाएंगे। इसके अलावा हम 220 के०वी०ए० के पांच पावर हाउसिज की आगमैंटेशन करेंगे वह हैं-- पेहवा, इंडस्ट्रीयल एरिया हिसार, नीसिंग, सोनीपत और पलवल। हम 132 के०वी० के चार नए सब स्टेशन पिपली, पाई, मलिकपुर और सैक्टर 27 और 28 हिसार में बनाएंगे। हम 132के०वी०ए० के 12 सब स्टेशंज की आगमैंटेशन करेंगे वे रतिया, पिंजौर, कुरुक्षेत्र में भोरे, चन्दोली, मुनक, गोहाना रोड़ पानीपत, गोहाना, न्यू नरवाना, रानियां, सिरसा, बाढ़ड़ा, बहादुरगढ़ और झज्जर में हैं। अध्यक्ष महोदय, 66 के०वी० के 5 नए सब-स्टेशन इण्डस्ट्रियल एरिया अम्बाला कैंट, बरनाला अम्बाला, सैक्टर-23, गुड़गांव, जठलाना कुरुक्षेत्र, भोले कलां गुड़गांव में बनाएंगे। हम चार नये सब स्टेशन शाहबाद, नूह, होडल और ठील में आगमैंट करेंगे। 33 के०वी० के हम 15 नए सब-स्टेशन धर्मगढ़ पानीपत में, अम्बाला कैंट, टयोंटा, भिवानी रोहिला, सिंघाना, इण्डस्ट्रियल एरिया सिरसा, द्वारका भिवानी, मोरवाला भिवानी, देवराला भिवानी, एम०डी०यू० रोहतक, जसौर खेड़ी, झज्जर, गढ़ी मातेहसर महेन्द्रगढ़, एम०सी०रिवाड़ी, जहाजगढ़ केहरवाला में बनाएंगे। 33 के०वी० के हम पुन्हाना, कुटेल, काबरी, ताजपुर देगा एम० आई० बहादुरगढ़, पाढ़ला, कुरुक्षेत्र, शिवम गेट, कैथल, ढांढ-कैथल, इसराना करनाल में आंगमैंट करेंगे। करनाल में एक और है। एच०एम०जी० बहादुरगढ़, एन०आई० बहादुरगढ़ गंगा सरसा, बेगु सरसा, वाहुदीन सरसा, कालांवाली सरसा, रामगढ़िया सरसा, और सिकन्दरपुर सरसा। इस साल के शुरू से लेकर 30 जून

तक हमने यह काम कर दिया है। नम्बर ऑफ सब-स्टेशन टू बी कमीशनड/आगमैंटीड। इस साल 25 नए लगाए गए और 40 आगमैंट किए गए, इन दोनों को मिलाकर कुल 65 बनाए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित मेरे पास एक पोथा है। अगर मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसमें 1996 से लेकर 1998 तक जितने हमने सब-स्टेशन नए बनाए हैं या जिनको आगमैंट किया है वे हैं। किस किस गांव को या इलाके को फायदा पहुंचा है यह सब इसमें है। इन सब की लागत 137 करोड़ रुपये है। बिजली के प्रोजैक्ट के बारे में मैंने बताया है कि हम और लगाने जा रहे हैं। अगले 3 साल के अन्दर-अन्दर वे आ जायेंगें। तो फिर इन सबको मिलाकर हमारे पास बिजली 863 मैगावाट से 1523 मैगावाट हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इरीगेशन की बात करूंगा। चौधरी धीर पाल जी ने कहा था कि हमारे यहां पर पानी नहीं जाता। इनके यहां पानी दुलेहड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी से जाता है। इसकी रिहबीलेटेशन का काम चालू कर दिया गया है। यह 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा। उम्मीद है दिसम्बर 1998 तक पूरा हो जायेगा। भाखड़ा मेन लाईन, नरवाना ब्रांच यानि भाखड़ा सिस्टम के बारे में चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि करीब 10 साल से पंजाब से हमारे हिस्से का जो पानी आना चाहिए वह नहीं आ रहा और न हमारे खेतों में लग पा रहा है क्यों नहीं लग पाता उसका कारण यह है कि यह नहर पंजाब से ही आती है। वे उसकी डिसिल्टिंग नहीं करते, उसको मजबूत नहीं करते, उसकी स्ट्रैंथन नहीं करते। हमने उनको इस काम के लिये सात करोड़ साढ़े तेरह लाख रुपये दिये हैं। जब हम अपने इंजीनियर को उनके एरिया में चैक करने के लिए भेजते हैं तो वे कई बार कह देते हैं कि हरियाणा की गाड़ी लेकर न आया करो हमारे लोग एतराज करेंगे। हरियाणा के लोग तो कोई एतराज नहीं करते अगर पंजाब की गाड़ी हरियाणा में आए। फिर ऐसा क्यों है ? यह उनका बहाना मात्र है। गाड़ी किसी की कोई नहीं रोकता भाखड़ा मेन कैनाल जहां से हमें 6700 क्यूसिक्स पानी मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय, जबकि हमें भाखड़ा मेन से 5700 क्यूसिक पानी मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, भाखड़ा मेन से हमको 1000 क्यूसिक पानी कम आता है। (विघ्न) इसके अतिरिक्त नरवाना ब्रांच से 4022 क्यूसिक की जगह हमें 3200 क्यूसिक पानी मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, नरवाना ब्रांच से भी हमको 800 क्यूसिक से ज्यादा पानी कम आ रहा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमने उनको 7 करोड़ से ज्यादा का अमाउन्ट दे दिया है, और भी दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, काम पूरा करवाने के लिए हम उनके आगे पीछे भी घूम रहे हैं। कई बार हमने उनसे टेलीफोन पर भी बात की है, अभी तीन-चार दिन पहले भी मैंने टेलीफोन किया था लेकिन पंजाब के मुख्य मंत्री श्री बादल बाहर दूर पर गये हुए थे। अध्यक्ष महोदय, यह कम पानी हमको पिछले 10-12 साल से मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, चौ० भजन लाल जी की सरकार के वक्त में एस०वाई०एल०कैनाल के पानी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई थी, वह रिट डिफैक्टिव दायर की गई थी और हमने उसको वापिस ले लिया। उस केस की लिगल फोरमैल्टिज पूरा करके हमने उस केस को दोबारा से दायर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की अगली तारीख 27-10-98 दी है। अध्यक्ष महोदय, अभी 8-10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी थी उसमें पंजाब वालों ने ऐसा बहाना बनाया जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। पंजाब ने बहाना बनाकर दरख्वास्त दे दी कि भारत इंडिया में ला एण्ड आर्डर की स्थिति बड़ी खराब है इसलिए इस केस को फिलहाल न सुनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, जज ने पंजाब वालों से पूछा की स्थिति में क्या खराबी है तो पंजाब के वकील ने कहा कि पोखरण में एक बहुत जबरदस्त बम धमाका हुआ, इस पर राजस्थान के वकील ने कहा कि बम तो हमारे यहां फटा है इससे आपको क्या सिर दर्दी है ? अध्यक्ष महोदय, इन सबको देखते हुए हमारे वकील ने कह दिया कि पंजाब वाले लिखकर दे दें कि हमारे यहां ला एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक जज ने कहा कि अभी

[श्री बंसी लाल]

मैं गुरदासपुर अपनी कार में गया था। रात 10 बजे तक वहां औरतें सड़कों पर घूम रही थी, वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं थी और पंजाब के एडवोकेट जनरल ने भी कहा कि लोग 12-12 बजे तक सड़कों पर घूमते हैं। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के वकील से ला एण्ड आर्डर की रिपोर्ट मांगी तो उसने कहा कि मैं तो इरीगेशन डिपार्टमैंट से आया हूं यह तो होम मिनिस्टर ही बताएंगे। इराड़ी ट्रिब्यूनल ने उसको हुक्म दिया कि एक महीने के अंदर-अंदर ला एण्ड आर्डर की स्थिति के बारे में भारत सरकार को रिपोर्ट भेजो। अध्यक्ष महोदय, हम इस केस को सुलझाने का काम कर रहे हैं, बड़ी तेजी और ताकत के साथ कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसका फैसला जल्दी ही हो जायेगा कोई बहुत लम्बा समय नहीं लगेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसाऊ डैम का सवाल है, इस डैम को बनाने का काम हमारे हाथ में नहीं है, इसको बनाने का काम अपर यमुना बोर्ड के हाथ में है। अपर यमुना बोर्ड के ऊपर हम इसे जल्दी बनवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों के मुकाबले हम हरियाणा की 6 हजार एकड़ जमीन को ज्यादा पानी दे रहे हैं, हमने नहरों की डिसिल्टिंग करा दी है जिन नहरों को मजबूत करना था उनको मजबूत कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, एक मसला वाटर लोगिंग का है। सदन में वाटर लोगिंग के बारे में काफी चर्चा हुई है और इससे लोग परेशान भी हैं। इस समस्या से इस सदन का हर मैम्बर परेशान है। अध्यक्ष महोदय, हम इस परेशानी का हल भी निकाल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपके द्वारा आपकी मार्फत सदन के सामने यह बताया था कि हमने हिसार से घग्गर में पानी डालने की 111 करोड़ रुपये की स्कीम बनाई है। अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम को जल्दी से जल्दी सिरे चढ़ाने की कोशिश करेंगे इससे यह पानी घग्गर में चला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात यहां सदन में और आई कि कैथल के पाई इलाके में बाढ़ से नुकसान हुआ और नग्गल हल्के के बारे में भी कहा गया कि पंजाब से बाढ़ का पानी आने से इस हल्के में फसलें बरबाद हो गई। अध्यक्ष महोदय, इस समस्या का इलाज भी हम कर रहे हैं। आपको पता ही है कि हर चीज में थोड़ा समय तो लगता ही है एकदम कुछ नहीं हो सकता है। 20-22 साल ये भाई रहे लेकिन इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। यदि ये 20-22 साल में कुछ नहीं कर पाए तो हम दो दिन में इसको कैसे कर सकते हैं। हर काम में समय तो लगता ही है। अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के सदस्यों की तरफ से किसी भी समस्या को हल करने के लिए कोई सुझाव आए हम उसे मानेंगे। उनकी जो समस्याएं हैं चाहे वे बिजली की हैं, चाहे पानी की हैं या और दूसरी समस्याएं हैं उनको हम हल करेंगे। प्रदेश की भलाई के लिए हम कोई भी काम करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इरीगेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। पब्लिक हैल्थ का सवाल भी यहां पर आया। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हैल्थ का काम भी हम अच्छी खासी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। पानी की आगमैंटेशन का जहां तक सवाल है, हमने 28 कस्बों में पानी देने की नई स्कीमें शुरू की हैं और कुछ सीवरेजिज को भी ठीक किया गया है। इन 28 आगमैंटेशन स्कीमों से 2193 गांवों को लाभ होगा, 93 करोड़ रुपये व्यय होंगे और वाटर स्कीमें जो चल रही हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यमुना ऐक्शन प्लान में हमने पिछले दो सालों में 140 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और इस साल 50 करोड़ रुपये और खर्च करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यमुना ऐक्शन प्लान के लिए हमने पलवल, गोहाना, रादौर और छछरौली के लिए 20.60 लाख रुपये रखे हैं और कुल मिला कर 232 करोड़ रुपये अभी तक खर्च हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में पीने के पानी का प्रबन्ध किया है, उनकी सूची काफी लम्बी है और अगर उस लिस्ट को पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अध्यक्ष महोदय, टूरिस्ट रिसोर्टस पर भी हमने 37 जगह काम किया है। जहां तक पी०डब्ल्यू०डी० का सवाल है, पी०डब्ल्यू०डी० ने दो साल में क्या-क्या काम किए हैं यह मैं सदन को बता दूं (विघ्न) कालका का रैस्ट हाउस बनाया है। हरियाणा भवन, नई दिल्ली में

एनसिलरी भवन बनाया है, पी०डब्ल्यू०डी० रैस्ट हाउस सांपला में बनाया है और डबवाली में जूडिशियल कम्पलैक्स बनाया है यानि जजों के रिहायशी मकान बनाए गए हैं। टीचिंग ब्लॉक, गवर्नमैंट पोलिटैक्निक का कमिशन हुआ है, नारनौल में गवर्नमैंट पोलिटैक्निक का टीचिंग ब्लॉक , एम०टी०सी० कैंटीन , गैलरी, होस्टल का डाईनिंग हाल, और पैसेज बना है। इस में 3 करोड़ 32 लाख रुपये पिछले सरकार के वक्त में खर्च हुए और बाकी हमारी सरकार के वक्त में खर्च हुआ है। डी०सी० रैजिडैंस रिवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट जेल सोनीपत, कमिश्नर रोहतक का रैजिडैंस, जमुना नगर में डी०सी० का रैजीडैंस, गवर्नमैंट पोलिटैक्निक कालेज लड़कों का अम्बाला में एवं लड़कियों का भी पोलिटैक्निक कालेज अम्बाला में बन रहा है। इसके अलावा न्यू सैक्रेटेरिएट की सात मंजिला बिल्डिंग सैक्टर 17 में हमने बनवाई है। यह बस स्टैण्ड के साथ है वह इन लोगों को दिखती ही नहीं है। इसका काम हमने बार फुटिंग पर 16 महीने में करवाया था। अब वह बिल्डिंग इनको न दिखे तो मैं क्या करूं। हमारे दफ्तर पहले चण्डीगढ़ में जगह जगह पर बिखरे पड़े थे अब वे सब एक जगह हो गए हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, वर्कशाप पोलिटैक्निक कालेज लड़कों का अम्बाला में, प्राईमरी हैल्थ सैंटर विद रैजिडैंस ढहिना में, आई०टी०आई० बहादुरगढ़, 12.जे० टाईप डबल स्टोरी 16, मैडिकल कालेज रोहतक में बन रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव टीचिंग वर्कशाप ब्रोकन गवर्नमैंट कालेज रोहतक एवं नीलोखेड़ी है अध्यक्ष महोदय, मेजर बिल्डिंगज वर्कशाप प्रगति पर है। ज्यूडिशियल कम्पलैक्स पंचकूला, रिवाड़ी, लोहारू और जमुना नगर में बन रहा है। Extension of six courts buildings in judicial complex in Mini Secretariat, Kaithal, copy agency and record room in judicial complex at Bhiwani, Mini Secretariat, Rewari and Jhajjar, S.D.O. (Civil) and Tehsil building, Asand and Mini Secretariat at Fatehabad, Yamunanagar and Kaithal are being constructed. In addition to this we are also constructing a jail in Sirsa and work is in progress. We are also constructing, Polytechnic at Dhamla, Polytechnic at Sirsa, Polytechnic at Rohtak, Technical College at Rohtak and Government Institute of Engineering, Sonipat. In Govt. Institute of Engineering, Sonipat the buildings of a Workshop, Laboratory, Library with Multi-Purpose Hall. Hostel for 16 boy students and for 30 Girls students are being constructed. The construction of Mahila Polytechnic at Khanpur, Govt. Polytechnic at Faridabad, Government Polytechnic at Utawar, additional Block with Lab. Block in Government Polytechnic for boys at Sirsa, Women Hostel, Phase-II for 50 students in C.R.H.C., Murthal, Science Block in Government College, Kalka is under progress. (Interruptions). Mr. Speaker Sir, the work on the Buildings of Science Block in Government College, Bahadurgarh, Gymnastic Hall in I.C. College, Rohtak, 150 Bed Hostel in Panchkula, New General Civil Hospital (100 beds) in Rohtak, 60 Bed Hospital in Mandi Dabwali, 50 Beds Hospital in Mandi Khera, building of Trauma Centre in Medical college, Rohtak, Sir Krishan Government Ayurvedic College, Kurukshetra, C.H.C. residents and non-residents in Bahadurgarh, C.H.C. with residential accommodation at village Punana, C.H.C. at Ganaur and logistic stores 11 No. Panchkula, Ambala, Bhiwani, Jagadhari, Hisar, Sirsa, Kaithal, Jind, Panipat and Sonipat is going on पंचकूला में पूरी स्टेट का होगा और बाकी डिस्ट्रिक्ट लैवल पर होंगे। The work on the buildings of Hostel for training school for M.P.W., Gurgaon, Hostel for M.P.W. training school at Rohtak, Houses for judicial officers at Bhiwani, 2 No. Houses 1882 sq. ft. and 2 No. 1220 sq. ft. for judicial officers, Faridabad, residential complex for 2 Nos. Additional and Session

[श्री बंसी लाल]
Judges, Hisar, Houses for Haryana Minister and members for Public Service Commission, Sector 12, Panchkula, 252 houses for Government employees in Sector 39-B and bus stand at Ambala Cantt., New Bus stand, Bhiwani New Bus Stand, Rohtak and Panchayat Bhawan in Sector 28 in Chandigarh is going on.अध्यक्ष महोदय, जहां से ये लोग रोज निकलते हैं वहां पर भी इनको वह बड़ी बिल्डिंग नजर नहीं आती है तो फिर इनको ईंट कहां से नजर आएगी ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पास बहुत सारे पेजिज बताने के लिए हैं। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह : मुख्य मंत्री जी, जितना अभी आपने काम का खुलासा किया है तो क्या इतनी बड़ी ट्रांसफर्ज की भी लिस्ट है ?

श्री बंसी लाल : कोई बात नहीं, ट्रांसफर्ज तो होते ही रहते हैं। आपके वक्त में भी ये होते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पे-कमीशन की भी बात यहां पर आयी। कुछ साथियों ने बल्कि शायद सम्पत सिंह जी ने इस बारे में कहा है कि क्लर्कों की तनख्वाह यहां पर क्या है और भारत सरकार में दिल्ली में क्या है? अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार में क्लर्कों की दो कैटेगरीज हैं एक एल०डी०सी० और दूसरी यू०डी०सी० हमारे यहां पर एल०डी०सी० का जो ग्रेड है वह 950-1500 का है लेकिन अब यह रिवाइज्ड होकर 3050-4590 का हो गया है। दस साल की सर्विस के बाद यह ग्रेड 4000-6000 और बीस साल की सर्विस के बाद यह ग्रेड 5000-7850 हो जाएगा। जबकि भारत सरकार में दिल्ली में क्लर्क को बगैर प्रमोट हुए कोई ग्रेड नहीं मिलता और उसका ग्रेड वही रहेगा 3050-4590 अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से असिसटैन्ट्स को हमने 5450-8000 वाला ग्रेड दिया है। दस साल की सर्विस के बाद इनका यह 5500-9000 वाला हो जाएगा और बीस साल की सर्विस के बाद इनका यह ग्रेड 6500-9900 वाला हो जाएगा। जबकि भारत सरकार में असिसटैन्ट्स का ग्रेड 1400-2600 वाला पहले था और वह यह रिवाइज्ड होकर 5000-8000 वाला हो गया है।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जो इन्होंने क्लेरिकल ग्रेड की बात की और कहा है कि दस साल की सर्विस के बाद इनका यह ग्रेड 4000-6000 हो जाएगा जबकि दिल्ली में भारत सरकार में इनका यह ग्रेड दस साल के बाद 5000-7850 हो जाता है। परन्तु हमारे यहां पर यह ग्रेड बीस साल के बाद होगा यानि बीस साल की सर्विस के बाद का हमारा क्लर्क और उनका दस साल की सर्विस के बाद का क्लर्क बराबर होगा। इसलिए यह बात अपने स्केल्ज में क्यों नहीं डाली गयी ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा जो नोन सैक्रेटेरिएट का क्लर्क है उसका बीस साल की सर्विस के बाद 5500-9000 वाला ग्रेड हो जाएगा और जो हमारा सैक्रेटेरिएट का क्लर्क है उसका 6500-9900 वाला ग्रेड हो जाएगा। जबकि दिल्ली में वहां के क्लर्क का ग्रेड 5500-9000 तक ही रहेगा। अध्यक्ष महोदय, फिफ्थ पे-कमीशन का बहुत बड़ा बर्डन स्टेट पर आया है।

अध्यक्ष महोदय, मानेसर में बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल अस्टेट बन रही है और वह बहुत तरक्की करेगी। मुझे अभी-अभी चिट लिखकर भेजी गई है और किसी ने सोच समझकर ही लिखी होगी कि दिल्ली में 10 और 20 साल की सर्विस के बाद अलग-अलग कोई ग्रेड नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, ला एण्ड आर्डर के बारे में मैं बता चुका हूँ। ला एण्ड आर्डर की जो सिचुएशन हमारे यहां है उस बारे में पिछले दो साल के और इससे पहले वाली सरकार के इससे पहले वाले दो साल के आंकड़े बता देता हूं। 11-5-1994 से 10-5-1996 तक 1367 मर्डर हुए और 11-5-1996 से 10-5-1998 तक 1216 हुए तो बताओ कौन से ज्यादा हैं ? हमारे वक्त के दो सालों में 151 मर्डर

कम हुए हैं। कल्पेबल हौमीसाइड पहले वाले में 170 थे और अब 209 है इसमें 39 बढ़े हैं। अटैम्प्ट टू मर्डर के केस पहले वाले दो साल में 794 थे इन दो सालों में 723 तो वे भी 71 घटे हैं। अध्यक्ष महोदय, गड़बड़ कहां है ? टोटल आई०पी०सी० के केसिज में 4283 हैं। पहले वाली सरकार के आखिरी साल के मुकाबले में हमारे कम हैं लेकिन यह बात ठीक है कि क्राइम अगेंस्ट वीमैन बढ़ा है। थैफ्ट और किडनैपिंग बढ़ी है। डकोइटी 32 घटी है और रोबरी 138 घटी है। किडनैपिंग 1994-96 तक 829 थी अब 887 हैं सात परसैंट बढ़ी है दिल्ली के मुकाबले अगर आप देखें तो हमारा ला एण्ड आर्डर बहुत इम्प्रूवड है दिल्ली में 1995-97 तक 1048 मर्डर हुए थे 1997-98 में 1211 हुए इस प्रकार 163 फालतू हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही इम्पोरटैंट बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। In normal circumstances, the crime is increasing at the rate of 2.3 % per annum at all India level, whereas in Haryana total cases under IPC have registered a decline of 3.21% less. कहने के लिए तो विरोधी पक्ष के भाई क्या-क्या कहेंगे ? पता नहीं क्या-क्या बात कह देंगे ? जो बात इनके ध्यान में आती है वही कह देते हैं इसका हमारे पास कोई ईलाज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एम०आई०टी०सी० की चर्चा आई कि वहां पर स्टाफ सरप्लस हो रहा है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वर्तमान सरकार का कोई कसूर नहीं है। 1977-1979 तक चौधरी देवीलाल जी और चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय में यह भर्ती की गई थी हमने तो कोई भर्ती नहीं की है। उन्होंने किस बात का कंसीडिरेशन करके इस स्टाफ को भर्ती किया यह मैं तो कुछ कह नहीं सकता। वर्ल्ड बैंक की असिस्टैंस की बात के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, एम०आई०टी०सी० के लिए जो इस सरकार ने बजट रखा है वह सिर्फ खालों को बनाकर देने का बजट है उनकी रिपेयर का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक ने किसानों को कहा है कि किसान अपनी एसोसियेशन बनायें तथा पैसा इकट्ठा करके बैंक में जमा करायें और उस पैसे से खालों को रिपेयर करायें। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वह तो सिर्फ खालों को एक बार बनाकर देगा उसके बाद उसकी रिपेयर या रख-रखाव का काम किसान का होगा।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बार रिपेयर का तो वर्ल्ड बैंक ने अलाऊं किया होगा ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, दूसरी एक बात कही जा रही है कि हमने जनता पर टैक्स लगा दिये, वर्तमान सरकार ने जनता पर बहुत टैक्स लगा दिये। विपक्ष के भाई जब जनता के बीच जाते हैं तो कोई भाई यह कह देता है कि 1500 करोड़ रुपये के टैक्स लगाये हैं और कोई भाई यह कह देता है कि 2500 करोड़ रुपये के टैक्स लगाये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। गलत बात का हम मुकाबला नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, इन दो सालों में हमने जो टैक्स लगाये उनसे कुल आमदनी 177.41 लाख रुपये साल की हुई है। इसमें कोई लूट नहीं है हमने किसान पर कोई ज्यादा टैक्स नहीं लगाये लेकिन विपक्ष के साथियों द्वारा इस बारे में बड़े जोर से प्रचार किया जा रहा है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी कृपया यह बतायें कि इनकी सरकार में फर्द की फीस क्या है, इंतकाल की फीस क्या है और ये फीसें कितनी बढ़ाई हैं ? पहले बहन भाई के नाम जमीन की डिक्री करवा दिया करती थी परन्तु अब इन्होंने इसको कितना बढ़ा दिया है ? रजिस्ट्री फीस को कितना बढ़ा दिया है ? पंजाब में अब भी इंतकाल की फीस 1.25 पैसे है लेकिन इस सरकार ने उसको

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]
कितना बढ़ा दिया है ? दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो भी टैक्स लगते हैं इनका इनडायरेक्ट रूप से असर उपभोक्ता पर ही पड़ता है। सरकार जो टैक्स लगाती है उस पैसे को आखिरकार उपभोक्ता को ही भरना होता है। वर्तमान सरकार ने जो रिसैंटली टैक्स लगाये हैं उनके बारे में भी आप बता दीजिए।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह सब मिलाकर ही मैं बता रहा हूं। इंक्रीज इन रेट्स ऑफ सेल्ज टैक्स एक साल में 102 करोड़ रुपये आए हमने यह बाद में लगाया था इसलिए पहले साल 76 करोड़ रुपये ही आए थे, गुड्ज फीस एक साल में 5.64 करोड़ रुपये, पैसेंजर टैक्स एक साल में 10.39 करोड़ रुपये, इंक्रीज इन रायल्टी ऑफ रेट्स ऑफ मिनरल्ज एक साल में 32 करोड़ रुपये, कामर्स एस्टिब्लिसमेंट की लैवी फीस एक साल में 15 करोड़ रुपये, इंक्रीज इन रेट्स आफ फीस बाई रेवन्यू डिपार्टमैंट, फूड एण्ड सप्लाईज डिपार्टमेंट तथा मैडीकिल कालेज रोहतक से एक साल में 12.38 करोड़ रुपये मिला है तथा कुल मिलाकर 177.41 करोड़ रुपये की आदमनी हुई है। इससे ज्यादा और कहां से आयेगा ? लेकिन प्रचार इतनी जोर से और इतनी-इतनी बातें कही जा रही हैं जिसका कोई न तो सिर है न पैर और न कोई हिसाब है ऐसे कहते रहते हैं क्योंकि यह समझते हैं कि ऐसा कहने से इनको कौन 18.00 बजे रोकेगा ? अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक के लोन के बारे में तो मैं बता चुका हूं। दूसरी बात श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने यह कही कि जब बजट सरप्लस हो गया तो फिर प्लान क्यों काटा ? मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम ने प्लान इसलिए काटा कि उस वक्त हमें इतने पैसे की आमदनी की उम्मीद नहीं थी। बाद में जब हमें स्माल सेविंग्स वगैरह से पैसा मिला तो उस पैसे को ऐसे ही सड़कों पर तो फेंकना नहीं था। उस पैसे को बड़े अच्छे ढंग से खर्च करना था, इसलिए वह कमी जो पहले रह गई थी, आज पूरी कर दी है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कहा था कि जब आप पिछले सत्र में ये सारी चीजें लेकर आ गए थे, तो अब इनको रिपीट करने की क्या आवश्यकता थी ? (विघ्न)

श्री बंसी लाल : आप ने तो यह बात कही थी कि हमारा पिछले साल का बजट जब सरप्लस था तो अब प्लान क्यों काटा है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें उस समय आ गई थीं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि वह तो बजट एस्टिमेट था तथा एक्चुअल बजट के फिगर्ज तो हर साल अगस्त के आस-पास ही आते हैं। जो पिछले साल का हमारा बजट था, उस के सही आंकड़े तो कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल के ऑडिट के बाद अगले अगस्त के आस-पास ही आएंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : जनवरी में वोट-ऑन-अकांउट बजट एस्टिमेट था। लेकिन अब तो जुलाई का महीना आ रहा है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल के हिसाब का तो हम को इस साल अगस्त के बाद ही पता चलेगा। (विघ्न) अगर वे मेरी बात से संतुष्ट नहीं हैं तो इसका मेरे पास कोई ईलाज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने किसानों द्वारा आत्महत्या करने की बात कही। आत्महत्या चाहे किसान कर

रहे हों या कोई और व्यक्ति करता हो, किसी को भी आत्महत्या करने से रोका नहीं जा सकता है। जो किसान नहीं हैं, वे भी आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे किसानों के नाम अखबार में आए, और ये नाम ऐसे एक साथी ने अखबार में दिये थे। जिसकी सदस्यता राज्यसभा में खत्म होने लगी तो वे किसानों के नेता बन गए। अध्यक्ष महोदय, मैंने बाकायदा इन्क्वायरी कराई तथा इन्क्वायरी कराने के बाद पाया गया कि उनमें से एक आदमी जिसका नाम भीरा पुत्र इंद्र सिंह, जाति ब्राह्मण उम्र 35 वर्ष, निवासी बेलरखा की दिनांक 18-5-98 को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। अध्यक्ष महोदय, एक ही इलाके के ये सारे नाम हैं। प्रीतम पुत्र धन सिंह, जाति जाट, उम्र 40 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक, जो शराब का आदी था, ने गोली खाकर आत्महत्या कर ली। उस के ऊपर कोई कर्ज नहीं था। जय सिंह पुत्र तुला राम, जाट, उम्र 60 वर्ष, निवासी बेलरखा अपनी लड़की के पास पंजाब में दिनांक 12-5-98 को गया था और वहीं से ही उसकी डैड बॉडी आई थी। अध्यक्ष महोदय, बेलरखा में पता नहीं आत्महत्या करने की क्या बिमारी आ गई है। (हंसी) शमे सिंह पुत्र तुला राम, जाट, उम्र 63 वर्ष निवासी बेलरखा की दिनांक 18-5-98 को किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जाट घने हैं, मैं क्या करूं ? (हंसी) कृष्ण पुत्र बलवीर सिंह, जाट, उम्र 25 वर्ष, निवासी ढाकल ने दिनांक 18-5-98 को घरेलू झगड़े के कारण स्प्रे पीकर आत्महत्या कर ली। दरबारा पुत्र बिशना, निवासी ढाबी, टेक सिंह, उम्र 30 वर्ष ने दिनांक 5-2-98 को घरेलू समस्या के कारण स्प्रे पीकर आत्महत्या कर ली। वह शराब का आदी था। करमवीर पुत्र भलेराम, जाट, उम्र 30 वर्ष, निवासी करमगढ़, ने जनवरी, 1998 में घरेलू झगड़े के कारण अपनी पत्नी समेत आत्महत्या कर ली। सुभाष पुत्र देवा राम, जाट, उम्र 28-30 वर्ष, निवासी करमगढ़, जो एक शराबी व्यक्ति था तथा जिसका घरेलू झगड़ा रहता था, ने शराब पीकर आत्महत्या कर ली । ज्ञानी राम पुत्र शंकर, जाट, उम्र 45 वर्ष निवासी करमगढ़ एक शराबी व्यक्ति था। इसको शराब पीने के लिए गांव में कोई पैसे नहीं देता था। लोग इससे नफरत करते थे, इसलिए तंग आकर उस ने आत्महत्या कर ली। किताब सिंह पुत्र देवा राम, जाट, उम्र 25 वर्ष, निवासी करमगढ़, ने दिसम्बर, 1997 में घरेलू झगड़े के कारण आत्महत्या कर ली। इस के ऊपर कोई कर्ज नहीं था। धर्मवीर पुत्र शंकर, जाट, वासी करमगढ़ ने घरेलु झगड़े के कारण आत्महत्या कर ली। इस के ऊपर किसी का कोई कर्जा नहीं था। रामे पुत्र जागेराम, जाट, आयु 45 वर्ष वासी चौटड़ा पट्टी का चाल चलन ठीक नहीं था, उसके दूसरी औरत के साथ गल्त सम्बन्ध थे और उस वजह से घर में झगड़ा रहने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। लाला पुत्र जगत, जाट, उम्र 40 साल का आपस में भाइयों का लेन-देन का झगड़ा रहता था और झगड़े के कारण उसने आत्महत्या कर ली। इस पर कोई कर्जा नहीं था। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में डिमोलिशन कर दिया, के बारे में सदन में बात आई है वैसे इस बारे में हर्ष कुमार ने बता दिया था। जो पानी किसानों के पास जाना था उस पानी का बहाव रोक रखा था। लोग हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही फरीदाबाद में डिमोलिशन हुआ। नाव दुर्घटना में जो नाव थी वह भी अनअथोराईजड थी। अथोरिटीज ने उन नावों को बिल्कुल बन्द कर रखा था। किसी का नाव में बैठना भी मना था। महोदय, डी०सी० फरीदाबाद एक शानदार डिप्टी कमीशनर हैं जब उसको सिरसा से बदलकर फरीदाबाद लगाया गया तो सिरसा से बसें भर-भरकर आई कि इस तबादले को कैंसिल किया जाए। मैंने कहा नहीं। आज भी गणेशीलाल जी कहते हैं कि उस डिप्टी कमीशनर को हमारे यहां लगा दो। मैं समझता हूँ कि वह डिप्टी कमीशनर फरीदाबाद के लिए ही ठीक है। वह डी०सी० उड़ीसा का रहने वाला निहायत ईमानदार और भला आदमी है वह लोकल राजनीति में कोई दखल नहीं देता। किसी को भी अच्छे काम में दखल नहीं करने देता मैं कहूंगा तो भी नहीं करने देगा। वह बढ़िया और ईमानदार आदमी है। वह हमारा बैस्ट डिप्टी कमीशनर है। अध्यक्ष महोदय, किसानों को यह बात कही गई है कि मेरा नाम लेकर कि बंसीलाल ने

[श्री बंसी लाल]
किसानों से सहकारी लोन की रिकवरी तेज कर दी है इसलिए लोग खुदकशी कर रहे हैं। यह बात किसी साथी ने यहां सदन में कही है। शायद कैप्टन साहब ने कही है। 1994-95 में कोआप्रेटिव लोन वसूल करने में 1674 आदमी गिरफ्तार हुए और 1995-96 में कोआप्रेटिव लोन वसूल करने में 1753 आदमी गिरफ्तार हुए। पिछले 2 सालों में 1996 से 1998 तक अम्बाला जिले में कोआप्रेटिव लोन वसूल करने के लिए एक आदमी को दो-चार घण्टों के लिए हवालात में बैठाया गया इसके अलावा किसी आदमी को हवालात में बन्द नहीं किया गया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि रिकवरी तो हो रही है लेकिन जो नकली दवाईयां पैस्टीसाईड, बीज आ रहे हैं क्या इसके लिए किसी दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया ?

श्री बंसीलाल : नकली दवाईयों के लिए कानून बने हुए हैं जहां इस प्रकार की शिकायतें हैं वहां नमूना चैक करवा लेंगे, रेड करवा लेंगे। जिस तरीके से ठीक होगा हम वह कार्यवाही अवश्य करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आपके जिले की ऐसी कोई बात हो तो बता देना।

श्री बंसी लाल : हम ओटू झील का प्लान बना रहे हैं, इन्वैस्टीगेशन चल रही है। वहां हैड वर्क का काम शुरू हो गया है उसको नीचे बनाने की ओर बड़ा बनाने की स्कीम है। सिल्ट खाली होने जा रही है।

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सी०एम० साहब से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो ओटू झील पर पुल बना हुआ है वह काफी दिन पहले से अनसेफ डिक्लेयर हो चुका है जिस दिन उसकी छत टूट जाएगी उस दिन हनुमानगढ़ और डबवाली साइड के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे क्या आप उसकी जगह नया पुल बनाएंगे।

श्री बंसी लाल : आप निश्चिन्त रहें वह पुल नहीं टूटेगा। वह बहुत पक्का पुल है। मैं भी कई बार उस पुल के ऊपर से गुजरा हूँ। उसका सर्वे हो रहा है जो मौजूदा पुल है जो मौजूदा साइफन है उसको आगे ले जाने की हमारी स्कीम है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास फरीदाबाद जिले की कानून-व्यवस्था के बारे आंकड़े आ गए हैं मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। यहां सदन में एक बात कही गई कि पुलिस की भर्ती में एक-एक डेढ़-डेढ़ लाख रुपये रिश्वत के लिए गए, चीफ मिनिस्टर बदनाम हो गया। मैंने न किसी से पैसा लिया और न ही किसी से पैसा लूंगा। अगर इस बारे में कहीं से कोई शिकायत आई तो मैं उसकी इन्क्वायरी करवा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक फरीदाबाद में अपराधों की बात है वहां पर 1-1-1997 से 25-7-1997 तक कुल 6325 अपराध हुए हैं और 1-1-1998 से 25-7-1998 तक वह 5047 हुए यानी 1278 अपराध घट गये। वहां पर हत्याएं पहले से 5 ज्यादा हुई हैं। हत्याएं पहले 39 हुई थीं इस साल 44 हुई हैं। पहले 29 हत्याएं करने का प्रयास किया गया अब 27 हत्याएं करने का प्रयास किया गया। वहां पर बलात्कार के केस पहले 33 हुए अब 25 हुए हैं। वहां पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के पहले 80 केस हुए अब 48 हुए हैं। वहां पर डकैती के पहले 41 केस हुए अब भी 41 ही हुए हैं। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि फरीदाबाद जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, पहले से ठीक है। अध्यक्ष महोदय, पंचकूला में नई अनाज मंडी बन गई है उस पर 3 करोड़ 95 लाख रुपये खर्च हुए हैं और वह मंडी 1-11-1997 से चालू हो गई है। इसके अलावा पंचकूला में हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की बिल्डिंग बन चुकी है उस पर 1 करोड़ 27 लाख रुपये खर्च हुए हैं और वह 1-11-97 से चालू हो गई है। हरियाणा सीड्ज डिवैल्पमैंट कारपोरेशन की बिल्डिंग बन गई

है। उस पर 85 लाख रुपये खर्च हुए हैं और यह 6-9-97 से चालू हो गई है। पी०डब्ल्यू०डी० का भी काम हुआ है। मकानों की कंस्ट्रक्शन और मैंटीनैंस पर 131 करोड़ 30 लाख रुपये का काम हुआ है इसमें कारपोरेशंज का काम शामिल नहीं है। नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों कि रिपेयर पर 143 करोड़ 95 लाख रुपये खर्च किए गए हैं इनमें से नई सड़कें बनाने पर 45 करोड़ 91 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं और पुरानी सड़कों की रिपेयर पर 98 करोड़ 4 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं। मण्डी विकास बोर्ड की बिल्डिंग पंचकूला में बन गई है उस पर डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हुआ है। हमारे प्रदेश की क्राईम सिचुएशन बाकी दूसरे प्रदेशों से खराब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस में जो कमाण्डोज भर्ती किए गए थे उनमें एस०सी० कैटेगरी के कैन्डीडेट गिनती के आये, उन्होंने कोई कोटा पूरा नहीं किया रिसोर्सिज के लिए हमने भारत सरकार से कहा है कि जो वे 29 परसेंट देते हैं उसको बढ़ा कर 33 परसेंट किया जाए। हम किसान को बिजली पर 700 करोड़ रुपये की साल की सबसिडी दे रहे हैं। 6 लाख गरीब आदमियों पर जिनका 40 यूनिट तक खर्च आता है उस पर कोई रेट नहीं बढ़ाया गया। स्टेट के अन्दर टोटल 32 लाख कन्ज्यूमर्ज हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रोहिबिशन की बात आई कि यह सदन से पूछ कर लागू की गई थी, यह सही नहीं है। यह गलत है क्योंकि प्रोहिबिशन का फैसला जिस दिन हमने ओथ ली थी, उस दिन हमने तीन ने ओथ ली थी जिनमें मैं, गोदारा साहब और कमला वर्मा थीं। हमने ओथ लेने के 15 मिनट के अन्दर-अन्दर कैबिनेट मीटिंग वहीं पर करके प्रोहिबिशन के फैसले को लागू कर दिया था। एक तरफ तो महामहिम ओथ दिला रहे थे और दूसरी तरफ हम यह फैसला कर रहे थे। हमने उसी वक्त आर्डर कर दिए तो अब इसमें सदन से पूछ कर के शराब बन्द करने की बात कहां से आ गई।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पिछले बजट सैशन में झज्जर बाई पास एन०सी०आर० के तहत बनाए जाने की बात कही थी। लेकिन वह नहीं बनाया गया है। इस बारे में भी ये बता दें।

श्री बंसी लाल : यह बाई पास अब एन०सी०आर० में नहीं आता क्योंकि वे इससे इन्कार कर रहे हैं।

श्री धीरपाल : अध्यक्ष महोदय, पहले तो था। अब बजट स्पीच में फिर इस बाई पास की चर्चा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बाई पास को क्या इसी बजट ईयर 1998-99 में कम्पलीट कर दिया जाएगा।

श्री बंसी लाल : हम कोशिश तो करेंगे लेकिन पक्की हां नहीं करते।

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा मैंने अपनी बजट स्पीच में भी एक बात कही थी कि हमारे यहां पर कड़ैहली में जो हैड वर्क्स है उस हैड वर्क्स से लेकर झज्जर सब ब्रांच और नेहरू कैनाल दोनों इक्ट्ठी जाती हैं। झज्जर सब ब्रांच कड़ैहली हैडवर्क्स से लेकर गोच्छी गांव तक खत्म हो जाती है। इसके अन्दर गाद भरी हुई है। यदि इसके अन्दर पूरा पानी भी छोड़ दें तो ज्यादा से ज्यादा कहीं पर 2 फुट, कहीं पर अढ़ाई या तीन फुट पानी मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि उधर का जितना इलाका है झज्जर सब ब्रांच की लैफ्ट साईड की तरफ मायना, सुनारिया, करौथ या दूसरे गांव हैं। इसके राईट साईड में नेहरू कैनाल है। इस तरफ कड़ैहली से लेकर रिंटोली, कबूलपूर और दुबलधन तक का एरिया आता है। यह एरिया सारा झज्जर सब ब्रांच में आता है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसमें जो अधिक गाद आदि भरी है क्या उसकी सफाई का आश्वासन देंगे।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मायना साहब झज्जर सब ब्रांच का जिकर कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूँगा कि पहले इस ब्रांच को चौड़ा करने और लम्बा करने का इरादा था। लेकिन अब इन्जीनियर्ज ने दूसरी स्कीम बनाई है जिसकी वजह से वहां के एरिया को ज्यादा पानी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, उस स्कीम को हम स्टडी कर रहे हैं और इसको पूरा करने के लिए हम लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, रोहतक से झज्जर को जाते हुए बायें हाथ को एक लिफ्ट आती है, जब बिजली नहीं आती तब उस लिफ्ट से लोगों की खेती पानी से तबाह हो जाती है, उस लिफ्ट को भी अलैमिनेट करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, झज्जर सब ब्रांच के बारे में इंजीनियरों की राय है कि इसको सीधा आगे ले जाने की बजाए आगे जाकर दो हिस्सों में बना दें। (विघ्न एवं शोर)

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या इस ब्रांच की खुदाई भी की जाएगी ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इसका जितना भी डिसिल्टिंग वगैरह का कार्य है वह हम करवा देंगे। (विघ्न एवं शोर)

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, नेहरू कैनाल का जो पानी आगे जाता है, वह पानी लीक करता है और सीपेज हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उस पानी को 8 नंबर ड्रेन में गिराने का कार्य करवायेंगे, क्योंकि उसमें कई गांव पड़ते हैं और उन गांवों की जमीन खराब हो रही है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, भाई मायना जी ठीक कह रहे हैं कि दोनों तरफ पानी का सीपेज है इससे किसानों का नुक्सान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसका एक ईलाज डिच ड्रेन बनाना है और दूसरा ईलाज इस पानी को ड्रेन नंबर 8 में डालना है। इस बारे में हमारा प्रोग्राम भी है। (विघ्न एवं शोर)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी बाई पास को 1996 में बनाने का आश्वासन दिया था कि यह बाई पास बनवा दिया जाएगा। मुख्य मंत्री महोदय वहां पर आधार शिला भी रख कर आये थे। अध्यक्ष महोदय, इंडियन ऑयल कारपोरेशन वहां पर बन चुका है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इस बाई पास का सर्वे तो पिछले साल हो चुका है, क्या ये इसे जल्दी से जल्दी बनवाने का कार्य करेंगे। अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक ओवर ब्रिज की भी जरूरत है क्या मुख्य मंत्री महोदय इस ओवर ब्रिज को भी बनवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और जाम लग जाता है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हम बाई पास बनाने के बारे में सोच रहे हैं। जो हमने मोटे-मोटे काम किए हैं उनमें छोटे काम शामिल नहीं हैं। कन्स्ट्रक्शन के, डिसिल्टिंग के, सड़कों के और पुलों के कुल मिलाकर 2 साल में हमने 2135 करोड़ रुपये बड़े कामों पर खर्च किए हैं इनमें छोटे काम शामिल नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में बिजली की स्थिति सुधरती जा रही है और अगले डेढ़ साल में पूरे हरियाणा को 24 घंटे बिजली दे देंगे और भगवान ने चाहा तो हमारे पास बिजली सरप्लस भी होगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हम हर तरह का कार्य कर रहे हैं। अपोजिशन के भाई जो भी अच्छे सुझाव देंगे, जनता की भलाई के लिए हम उन सुझावों को अवश्य मानेंगे, इसमें हमें कोई एतराज नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, इतना कहकर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by half an hour ?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting is extended by half an hour.

वर्ष 1998-99 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Now, the Finance Minster will give reply on the Budget Estimates for the year 1998-99.

वित्त मंत्री (श्री चरण दास) : अध्यक्ष महोदय, मैं 1998-99 के बजट पर चर्चा में विपक्षी भाईयों ने जो मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 22,23,24 तारीख से लगातार बजट पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, जो बजट हमने पेश किया है, उस बजट पर बिजली के बारे में, इरीगेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में विपक्षी भाईयों की तरफ से कोई सुजैशन नहीं आया, विपक्षी भाईयों ने बजट की सिर्फ आलोचना की, कोई सुजैशन नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने और श्री राम बिलास शर्मा जी ने सभी सवालों का विस्तार से जवाब दे दिया है, लेकिन कुछ मुद्दों पर जवाब मैं भी देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब से हरियाणा बना है, हरियाणा में 2260 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना पहली बार सदन में पेश की गई है। यह सबसे बड़ी योजना है और पिछले वर्ष की 1400 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना से यह 61प्रतिशत ज्यादा है। हमने बजट बनाने से पहले मन्थन किया और बड़ी सोच समझ कर प्रदेश के अन्दर किस चीज़ की जरूरत है यह तय कर के ही बजट का प्रावधान किया है। बिजली उत्पादन के लिए हमने 505 करोड़ रुपये, इरीगेशन के लिए 550.81 करोड़ रुपये, सोशल सर्विसिज़ के ऊपर 590 करोड़ रुपया खर्च किया है, पिछड़े क्षेत्र पर 1844 करोड़ रुपये और एलायड एग्रिकल्चर के लिए 117 करोड़ रुपये हमने दिए हैं। हमने बहुत सोच-समझ कर डिवैल्पमैंट ओरिएण्टिड बजट पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, सदन में खुल कर लॉ एण्ड आर्डर पर चर्चा हुई और मुख्य मंत्री जी ने बड़े बिस्तार से इस के बारे में बताया है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय साथियों ने ला एण्ड आर्डर की स्थिति के बारे में बताया परन्तु किसी ने भी यह बताने की कोशिश नहीं की कि इस स्थिति के बिगड़ने के कारण क्या हैं। ये कारण राजनैतिक भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं और सामाजिक कारण भी हैं। लॉ एण्ड आर्डर के बारे में चोरियां बगैरा और दूसरे अपराध होते हैं उन को रोकने में टाईम भी लगता है क्योंकि इसके लिए सोच कर कार्यवाही करने की जरूरत होती है। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि यदि लॉ एण्ड आर्डर के बारे में बिना तथ्य के ज्यादा बोलते जाएंगे तो उससे मासिज़ पर भी गलत असर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० के बारे में भी मैं सुन रहा था। एस०वाई०एल० के पानी का बंटवारा होना चाहिए और हमारे हिस्से का पानी हमें मिलना चाहिए। एक ऑनरेबल मैम्बर ने बोलते हुए यह कहा कि हमें इसके लिए दूसरे तरीके अपनाने चाहिएं पंजाब रोडवेज़ की जो बसें हमारे यहां से गुजरती हैं उन्हें हरियाणा की सड़कों से गुजरने नहीं देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बात ठीक नहीं है। यदि हमें लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति को ऊंचा रखना है तो हमें बड़ी सावधानी से पग उठाने होंगे और पूरा मन्थन और विचार करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। विपक्ष के भाईयों ने एजुकेशन के बारे में, सोशल वैल्फेयर, रोडज़ के बारे में जो-जो बिन्दु उठाए हैं उनका जवाब मंत्रियों ने दे दिया है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अपोज़ीशन के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कई मुद्दे उठाए और कहा कि फिफ्थ पे कमीशन सरकार ने दिया है लेकिन बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है जिसको पूरा करने के लिए हम 1500 करोड़ रुपये के टैक्स लगाने जा रहे हैं। यह तथ्य बिल्कुल गलत है। सरकार ने 1697.95 करोड़ का प्रावधान किया

[श्री चरण दास]
है इसमें 1101.14 करोड़ रुपये ऐरियर्ज का बकाया है और उसके अन्दर 61 करोड़ रुपये वे भी हैं जो कि वर्ष 1996-97 के देने के लिए हैं और ए०डी०ए० की किश्त भी देनी है। इसके लिए कोई टैक्स लगाने की बात नहीं है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें। पिछले बजट स्पीच में इन्होंने कहा था कि 628 करोड़ रुपये पे कमीशन के लिए अलग से रखे गए हैं और उनको केवल 76 करोड़ रुपये दिए गये हैं। अब इन्होंने 6300 करोड़ रुपया 7600 करोड़ रुपये के अगेन्स्ट रखा है जो 1300 करोड़ का डैफिसिट है वह कहां से पूरा होगा। उनको 20-22 प्रतिशत तनख्वाहों में जोड़ें यह पैसा कब तक और कैसे दिया जाएगा। 7600 करोड़ के अगेन्स्ट 6300 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। 1300 करोड़ रुपया तो तनख्वाहों और इन्क्रीमैंट्स में चला जाएगा, वित्त मंत्री जी इसका भी स्पष्टीकरण करें।

श्री चरण दास : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ने जो सवाल किया है कि पिछले बजट में 628 करोड़ रुपये का प्रावधान था वह इन्होंने गलत बताया था और इसका जवाब हमने दिया था तो ये सदन में से चले गए थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने पढ़कर सुनाया था तो 628 करोड़ रुपये थे और इन्होंने 76 करोड़ रुपये ही उसमें से दिए हैं। मैं तो उस वक्त चला गया था तो ये बताएं कि यह पौथा किस बात का है।

श्री चरण दास : चौटाला साहब, आपको तो पता ही नहीं कि बजट कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है। आप हाऊस को गुमराह करते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, बहुत से विचारों का मंथन हो गया है। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वर्ष 1998-99 के अनुमानों को अनुमोदित किया जाए।

बिल्ज

(i) पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1998

Mr. Speaker : Now the Ayurveda Minister will introduce the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1998. He will also move the motion for its consideration.

आयुर्वेदिक राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1998 प्रस्तुत करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :-

पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved :

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) bill, be taken into consideration at once.

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में कहना है कि इस बिल को क्यों बार-बार लाया जा रहा है। यह बिल हर एक दो साल के बाद आता है पिछले 29 सालों से ऐसा हो रहा है। इसको

बार-बार लाकर क्यों चुनाव को टालते हैं। अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट का फैसला आया कि जो आर०एम०पी० हैं वे एलोपैथिक की दवाईयां नहीं बेच सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत से डाक्टर हैं जिनको हम थैले वाले डाक्टर कहते हैं ये हजारों की तादाद में हैं। आज क्या हो रहा है जो डाक्टर आयुर्वेदिक बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं वे एलोपैथिक दवाईयां इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके खिलाफ आज ये एफ०आई०आर० दर्ज करते हैं और उनको पकड़ते हैं। सरकार को यह सब बंद करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब दूसरी स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो रही है तो हमारे यहां पर क्यों बंद है। अध्यक्ष महोदय, आज पी०एच०सी०, सी०एच०सी० और डिस्पैंसरियों में डाक्टर्ज नहीं हैं और आज डाक्टरों की जरूरत है तो हमने क्यों उनकी रजिस्ट्रेशन को बंद कर रखा है। आज गांवों में डाक्टरों की बहुत ही जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, उनको किसी इन्टरव्यू से या किसी टैस्ट के द्वारा रखा जाए। अगर ऐसा होता है तो गांवों में लोगों का ईलाज हो जाएगा। उनके खिलाफ जो फर्जी एफ०आई०आर० दर्ज की जाती हैं वे बंद की जाएं। इस बारे में कुछ लोग बहन जी को मिले भी होंगे। मैं बहन जी से कहता हूं कि उनका कोई टैस्ट या इन्टरव्यू लेकर उनकी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए।

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, जो सम्पत सिंह जी कह रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहती हूं कि यह सैंट्रल कौंसिल का पास किया हुआ ऐक्ट है। वे डाक्टर्ज बिना निर्धारित परीक्षा/ऐग्जामिनेशन के रजिस्टर्ड नहीं हो सकते।

श्री सम्पत सिंह : आप उनका ऐग्जामिनेशन करो।

डॉ० कमला वर्मा : ये ऐग्जामिनेशन तो सैंट्रल कौंसिल में मंजूर किए हुए हैं वही ये निर्णय ले सकती है।

श्री धीरपाल सिंह : फिर इसका जो भी समाधान हो सकता है, वह आप करिए।

डॉ० कमला वर्मा : स्पीकर सर, यह तो केन्द्र सरकार ने देखना है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, एक डाक्टर्ज तो वे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है और दूसरे डाक्टर्ज वे हैं जो आलरेडी रजिस्टर्ड हैं। जो आलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनके खिलाफ एलोपैथिक दवाई का नाम लेकर रोजाना एफ०आई०आर० दर्ज क्यों की जा रही है ?

डॉ० कमला वर्मा : स्पीकर सर, एलोपैथिक दवाई इस्तेमाल करने का जो ऐक्ट है वह केन्द्र सरकार ने ही पास किया हुआ है। इसलिए हमारे जो भी ड्रग इंस्पैक्टर्ज हैं, वे जगह जगह जाकर ऐसे डाक्टर्ज की चैकिंग करते हैं और उसके बाद ही उनके ऊपर केसिज चलते हैं। इस तरह के डाक्टर्ज एलोपैथिक दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

श्री सम्पत सिंह : लेकिन जो डाक्टर्ज रजिस्टर्ड नहीं है उनके ऐग्जामिनेशन के बारे में आप क्या करेंगे?

डॉ० कमला वर्मा : जो डाक्टर्ज आर०एम०पी० हैं या जो आयुर्वेदिक रत्न हैं या भास्कर हैं, इनको सैंट्रल गवर्नमैंट एलोपैथिक दवाई के इस्तेमाल के लिए आज्ञा नहीं देती है। उन्होंने ही इस बारे में एक क्राईटेरिया तय किया हुआ है। मान्यता प्राप्त एग्जामिनेशन होने के बाद ही इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला तो सैंट्रल गवर्नमैंट के अधीन है। हमारे बोर्ड को इस बारे में कोई अधिकार नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : दूसरे स्टेट्स में तो ये रजिस्टर्ड हो रहे हैं।

डॉ० कमला वर्मा : वे तो पैसे लेकर झूठे सर्टिफिकेट्स दे देते हैं फिर अन्य प्रान्तों में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Minister of State for Ayurveda will move that the Bill be passed.

Minister of State for Ayurveda (Smt. Kanta) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The Motion was carried.

(ii) हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1998

Mr. Speaker : Now the Local Government Minister will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1998. He will also move the motion for its consideration.

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करती हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ कि—

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री धर्मवीर गाबा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि हर साल इस एक्ट के अंदर ये अमैंडमैंट आ जाती है। पिछली दफा भी हम वाकआउट करके गए थे, जब ये पंचायत एक्ट नहीं लाए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर गवर्नमैंट चाहती क्या है ? बेसिकली इस एक्ट में 1973 में कांस्टीच्यूशन के अंदर अमैंडमैंट की गई थी और उसका मकसद सिर्फ यही था कि हम बेसिक डैमोक्रेसी प्रोवाइड करें और उस डैमोक्रेसी को खत्म करने के लिए हरियाणा वाले बैठे हैं अपनी समझ में यह बात आज तक नहीं आई कि इनको क्या कहें, इन लोगों की तो वह बात है कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। इनकी कौन सी कल सीधी है अपनी समझ में यह बात नहीं आई। इस बिल की स्टेटमैंट में इसके औब्जैक्ट एंड रीजंस को पढ़ें आप लोगों ने तो उसमें यह प्रोवाइड किया है-

"Section 14 and 22 of the Haryana Municipal Act, 1973 provide a lengthy procedure for removal of President, Vice-President and Members of Committees on various grounds ....."

ये यह भी नहीं चाहते कि कोई आदमी कोर्ट में जाये, ये चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी उसको सस्पैंड करो, रिमूव करो और खत्म कर दो। स्पीकर सर, आज पंचायतों के अंदर जो हो रहा है उससे मेरे मन में डर है। मेरी कांस्टीच्यूएंसी के अंदर पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने झूठे-मूठे एलीगेशन लगाकर सस्पैंड कर दिया और सिर्फ इस विनाह पर कि इसने इम्बैजलमैंट की है इसने यह कर रखा है, इसको सस्पैंड कर दो यही सब हर केस में होगा तो डैमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी और जिस मकसद के लिए यह बिल लाया गया था वह मकसद पूरा नहीं होगा। अतः मेरी मुख्यमंत्री जी और मंत्री महोदया से प्रार्थना है कि इस बिल को वापस लें और डैमोक्रेसी जो बेसिक है उसमें लोगों को जीने दें और डैकोक्रेसी प्रोवाइड करें, यही मेरी रिकवैस्ट है।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जैसा गाबा साहब ने कहा, ख्याल तो मेरा भी यही है कि हरियाणा म्युनिस्पल (अमैंडमैंट) बिल वापस लिया जाए। स्पीकर सर, इसके रीजन्स यह हैं कि यह बिल अपने आप ही पास नहीं है। यह कांस्टीच्यूशनल अमैंडमैंट है। कांस्टीच्यूशन के बतौर गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने इसमें अमैंडमैंट की थी। म्युनिसिपल और साथ में आपकी लोकल बॉडीज और पंचायतों के दो एक्ट थे और दोनों को ज्यादा पॉवर्ज देने की बात थी। जो एक्ट हैं वे दोनों के पास किए गए थे। पिछली विधान सभा में स्पीकर साहब आप भी हमारे साथ मैंबर थे। कांस्टीच्यूशन को बदलने या कांस्टीच्यूशन में अमैंडमैंट लाने वाले लोगों की इच्छा यह थी कि महात्मा गांधी के सपने को पूरा किया जाए, पॉवर को डीसैन्ट्रलाइज किया जाए। सारी पावर्ज एक जगह क्यों हो जाए ? गांव को भी पॉवर जाये और शहरों को भी जाये। लोकल बॉडीज और पंचायतों को भी पॉवर्ज होनी चाहिएं। गवर्नमैंट को अमैंडमैंट तो ये लानी चाहिए थी कि पंचायतों को, ब्लॉक समितियों को और जिला परिषदों को पॉवर देते, उनकी फाईनैंशियल पोजीशन कुछ सुधारते, कुछ उनके पास बजट वगैरह होता। स्पीकर सर, हालात यह है कि इंस्टीच्यूशन बन तो गई, एक्ट बन तो गया लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर एक्ट बनाया गया था वह उद्देश्य एक परसैंट भी पूरा नहीं हुआ है। कहने को तो कह दिया और यहां तक हो गया कि जैसे पंचायतों और म्युनिसिपल कमेटीज के चुनाव हुए तो बहुतों में ये हो गया कि डी०सी० की रिपोर्ट जिला परिषद् के मैम्बर लिखेंगे, फलाने की रिपोर्ट सरपंच लिखेंगे और हालात ये हो गए कि जो रिपोर्ट वे देंगे उस पर तो ये सस्पैंड हो जाएंगे। डी०सी० की रिपोर्ट जिला परिषद् के सदस्य क्या लिखेंगे ? सस्पैंशन तो पंचायतों में आम होता है। मैं किसी पर्टिकुलर केस को साइट करके नहीं कह रहा हूं सवाल आज इस गवर्नमैंट का नहीं है, इस मिनिस्टर का भी नहीं है जिसके पास यह महकमा है महकमा तो आज किसी के पास है कल किसी और के पास आ सकता है सरकारें तो आती जाती रहती है लेकिन अगर इस तरह से सस्पैंड करने लगे, डायरैक्टर को पॉवर दे दी, चुने हुए आदमी को दे दी तो केसिज तो एम०एल०ए० और एम०पी० के खिलाफ भी दर्ज होते हैं केवल मात्र केस दर्ज हो गए, अंडर इंक्वायरी है या अंडर इन्वैस्टीगेशन है He will be suspended by the Director. प्रेजीडैंट भी सस्पैंड हो जाएगा, म्युनिसिपल काऊंसलर भी सस्पैंड हो जाएगा तो डैमोक्रेसी क्या रह गई है। कहां तो पॉवर्ज की डैलीगेशन करने जा रहे थे, फाईनैंशियल पावर्ज देने जा रहे थे, क्राइमस को रोकने के लिये कुछ सजा वगैरह की पॉवर्ज देने जा रहे थे वह चीजें तो हुई नहीं हैं। जो सैंस ऑफ अमैंडमैंट की थी वह सारी की सारी सैंस डिफीट तो पहले ही हो गई है अगर आप उनको सस्पैंड करने वाली अमैंडमैंट और ले आते हैं कि सिम्पली एक डायरैक्टर उनको सस्पैंड कर सकेगा तो कोई भी आदमी किसी के खिलाफ एक क्रिमिनल पर्चा दे दे तो आपको यह तो मालूम ही है कि केस किस तरह से दर्ज होते हैं। कई बार तो रास्ते में रोकने पर भी केस दर्ज नहीं होते कई बार चलने पर भी दर्ज हो जाते हैं। इस तरह यह बहाना लेकर किसी भी म्युनिसिपल काऊंसलर को या म्युनिसिपल प्रैजिडैंट को पावर्स देना तो दूर की बात है, सस्पैंड करने में भी देर नहीं लगेगी। The Enquiry is pending and he is suspended for 6 months. इसमें यह भी नहीं दिया है कि दोबारा कोई रिइंस्टैट हो सकता है इस तरह से थोड़ा गैप देकर 15-20 दिन बाद एक और कंम्पलेंट करवाकर उसको सस्पैंड कर देते हैं। इस तरह से उसका सारा पीरियड तो सस्पैंशन में ही चला जाता है। यह तो टोटली इंडमोक्रेटिक-वे है। जो स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की बजाए हम उसे कमजोर कर रहे हैं। प्रजातंत्र की बेसिक इकाई स्थानीय स्वशासन है। इसलिए मेरा आपसे तथा सरकार से निवेदन है कि इस बिल को वापस लिया जाये। इस तरह से प्रजातंत्र का गला न घोटा जाये और इलैक्टिड लोगों को इस तरह से सस्पैंड न किया जाये।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने लोकतंत्र को मजबूत करने की अच्छी बात

कही है हमें लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिये। लेकिन आज जो प्रदेश में प्रधान और उप-प्रधान व अन्य पार्षद हैं वे अपनी मनमानी कर रहे हैं। जिस तरह से आज प्रदेश में नगर पालिका विवशता में काम कर रही है, जिस प्रकार के आरोप मेरे पास रोजाना आते हैं, उन आरोपों की इंक्वायरी करने में दो-दो साल लग जाते हैं और हमारे पास कोई अधिकार नहीं होता कि हम कोई ऐक्शन ले लें। हमने इस एक्ट में कुछ नहीं किया केवल पंचायत एक्ट की तरह नगर पालिका को एक अधिकार की बात की है। जिस तरह पंचायत एक्ट में सरपंच जो किसी आरोप से सस्पैंड हो जाता है तो वह 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। उस अपील की सुनवाई से पहले उसे एक नोटिस दिया जायेगा, उस नोटिस का जवाब आने के बाद ही उस अपील का फैसला किया जायेगा। क्योंकि कई नगर पालिका के प्रधान दो-दो साल तक कोई मीटिंग नहीं बुलाते, जनता के पैसे का दुरूपयोग करते हैं। कहीं वृक्ष कटवा देते हैं या शहर में नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा करवा देते हैं इस तरह शहर में कोई विकास का काम नहीं हो पाता। इन सारे आरोपों को देखते हुए हम इसमें संशोधन ला रहे हैं। अगर कोई प्रधान गलत काम करता है और उस पर गंभीर आरोप लगते हैं तो हमने इसमें संशोधन किया है कि डायरैक्टर को यह अधिकार है कि वह प्रधान को निलम्बित कर उस की अपील 30 दिन के अंदर सुन सकता है और अगर उससे सहमत है तो उस पर फैसला कर सकता है इसमें क्या गलती है मुझे बताइये (विघ्न)

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Shri Sampat Singh : Sir, I want to speak on this clause. (Noise & Interruptions).

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

वाक आऊट

(At this stage all the members of Haryana Lok Dal (Rashtriya) Party and the Indian National Congress Party present in the House staged a walk out as a protest against not having been allowed to speak more on the Bill.

बिल्ज

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1998 (पुनरारम्भ)

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Local Government Minister will move that the Bill be passed.

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि—

विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Development & Panchayats Minister (Shri Kanwal Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 1998 and I also move—

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Minister for Development & Panchayats will move that the Bill be passed.

Development & Panchayats Minister (Shri Kanwal Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) पंजाब आबकारी (हरियाणा तृतीय संशोधन) विधेयक, 1998

Mr. Speaker : Now the Minister for Prohibition & Excise & Taxation will introduce the Punjab Excise (Haryana Third Amendment) Bill, 1998 and he will also move the motion for its consideration.

शहरी एवं नगर आयोजना मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब आबकारी (हरियाणा तृतीय संशोधन) विधेयक, 1998 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि—

इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Excise (Haryana Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Excise (Haryana Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Prohibition & Excise Minister will move that the Bill be passed.

शहरी एवं नगर आयोजना मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House is adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 28th July, 1998.

*18.56 p.m. (The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 28th July, 1998)

30579–H.V.S.–H.G.P., Chd.